भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी से जारी
प्रेस विज्ञप्तियां
(जूलाई 2010-जूलाई 2012)

प्रकाशकों की ओर से

हम यहां भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी की ओर से जुलाई 2010 से जुलाई 2012 के बीच जारी किए गए बयानों को प्रकाशित कर रहे हैं। यह दौर हमारे देश में एक अत्यंत उथल–पुथल भरा दौर रहा है और क्रांतिकारी आंदोलन पर भारतीय राजसत्ता द्वारा बढ़ाए गए आक्रमण की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो यह एक अत्यंत कठिन दौर भी है। इस दौर में भाकपा (माओवादी) ने देश और दुनिया में घटित विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इन बयानों में अपने रुख को साफ तौर पर जाहिर किया।

इन बयानों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हमने इन सभी को एक जगह लाकर यह संकलन तमाम कैडरों व जनता तथा देश–दुनिया के उन तमाम माओवादी, प्रगतिशील और जनवादी संगठनों, पार्टियों और बुद्धिजीवियों के सामने पेश कर रहे हैं जो माओवादी आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं। माओवादी आंदोलन का समर्थन करने वाले संगठनों, पार्टियों और बुद्धिजीवियों को विभिन्न मुद्दों पर पार्टी के दृष्टिकोण व रुख के बारे में समझदारी देने में और कैडरों व जनता को शिक्षित करने में यह संकलन उपयोगी रहेगा। विभिन्न मुद्दों पर पार्टी द्वारा इन बयानों के जरिए दिए गए आह्वानों को पार्टी कैडरों ने लागू किया। और इस तरह क्रांतिकारी व्यवहार में भी इन बयानों का खासा महत्व रहा है।

शासक वर्गों द्वारा अपने मनोवैज्ञानिक युद्ध के तहत, जोकि कम तीव्रता वाले संघर्ष की रणनीति का एक अभिन्न अंग है जिसे वे अमेरिकी साम्राज्यवादियों के मार्गदर्शन व पूर्ण समर्थन से देश में लागू कर रहे हैं, अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ाए गए झूठे व जहरीले प्रचार की पृष्ठभूमि में क्रांतिकारी प्रचार बेहद जरूरी हो गया ताकि उसके सामने जबर्दस्त चुनौती पेश की जा सके। हमारी उम्मीद है कि भाकपा (माओवादी) और उसके नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आंदोलन पर शासक वर्गों द्वारा चलाए जा रहे मनोवैज्ञानिक युद्ध का मुकाबला करने में भी

यह संकलन अपनी भूमिका अदा करेगा। हम अपने कैडरों तथा हमारे आंदोलन के हमदर्दों और समर्थकों से अपील करते हैं कि वे भारतीय राजसत्ता द्वारा जारी दुष्प्रचार के खिलाफ लड़ने में इस संकलन को क्रांतिकारी प्रचार के एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें।

इस संकलन को जारी करने के मौके पर हम अपने प्यारे नेता कामरेड चेरुकूरी राजकुमार (पोलिटब्यूरो सदस्य) और कामरेड मल्लोझुला कोटेश्वरलु (पोलिटब्यूरो सदस्य) को विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि पेश करते हैं जो क्रमशः केन्द्रीय कमेटी व पूर्वी रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता रहे। पार्टी के प्रवक्ता के रूप में इन साथियों ने दीर्घकालीन जनयुद्ध में राजनीतिक प्रचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय क्रांति के इन दोनों महान नेताओं को हमने इसी दौर में खो दिया और इस संकलन में वे बयान भी शामिल हैं जिनमें उनकी शहादत को लाल सलाम पेश किया गया।

जुलाई 2012

क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ,

केन्द्रीय कमेटी

भाकपा (माओवादी)

fo"k; lph

शहीद सप्ताह सफल मनाएं (2010) 7

पार्टी की 6वीं वर्षगांठ को ऊंचा उठाए रखो 13

कश्मीरी जनता के आंदोलन के समर्थन में भारत बंद 19

ओबामा! वापस जाओ! 24

'एकीकृत कार्य योजना' बुनियादी समस्याओं का हल नहीं करेगी 29

बाबरी मस्जिद का उसी जगह पर पुनरनिर्माण करो 33

डाक्टर बिनायक सेन, कामरेड नारायण सन्याल, पियूष गुहा, असित सेनगुप्ता की सजा के खिलाफ विरोध सप्ताह 37

महंगाई, घोटालों और सरकारी आतंक के खिलाफ भारत बंद 42

लीबिया पर दुराक्रमणकारी युद्ध का विरोध करो, अरब जनता का समर्थन करो 47

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करो 54

भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए जन संघर्षों को तेज करो 59

जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र के खिलाफ आंदोलनरत जनता का समर्थन करो 63

ओसामा बिन लादेन की बर्बर हत्या का विरोध करो 69

बिहार में माओवादी नेताओं की गिरफतारी के खिलाफ भारत बंद 74

कामरेड भूपेशजी की गिरफतारी के खिलाफ भारत बंद 82

छत्तीसगढ़ और ओड़िशा में प्रस्तावित नए सरकारी आक्रमण का मुकाबला करो 86

माड़ क्षेत्र में बसाए जा रहे सेना के प्रशिक्षण केन्द्र के खिलाफ विरोध सप्ताह 92

पोस्को विरोधी आंदोलनकारियों को लाल–लाल सलाम 94
राष्ट्रपति द्वारा रखा गया शांति वार्ता का प्रस्ताव
जनता को गुमराह करने का हथकण्डा 100
कामरेड्स जीतन मराण्डी और अन्यों को दी गयी
फांसी की सजाओं को रद्द करो 103
शहीद सप्ताह सफल बनाएं (2011) 107
मुम्बई में हुए बम हमलों की भर्त्सना करो 112
माओवादी नेतृत्व के खिलाफ जहरीले दुष्प्रचार को
रद्दी के टोकरे में फेंक दो 117
तेलंगानावासियों की 'सकल जन हड़ताल' के समर्थन में भारत बंद 122
पीएलजीए की 11वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सी.एम.सी. का संदेश 126
कामरेड किशनजी की बर्बर हत्या के खिलाफ भारत बंद 131
सब्यसाची पण्डा का पार्टी से बहिष्कार 137

20 जुलाई 2010

28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद-सप्ताह सफल मनाएं!

भारतीय क्रांति के महान नेता आजाद (राजकुमार), शाखामूरी अप्पाराव, जीवन (सूर्यम) समेत जनता के हित में अपने प्राणों को अर्पित करने वाले तमाम वीर शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करते हुए गांव-गांव में सभा-सम्मेलनों का आयोजन करें - शहीदों के अधूरे मकसद को पूरा करने की शपथ लें!

पार्टी के संस्थापक-नेता व महान शिक्षक कॉमरेड्स चारु मजुमदार और कन्हाई चटर्जी को लाल-लाल सलाम!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी समूची क्रांतिकारी जनता व पार्टी/पीएलजीए के कतारों का आह्वान करती है कि आगामी 28 जुलाई से 3 अगस्त तक देश भर में गांव-गांव में शहीद सप्ताह जोर शोर से मनाया जाए। इस अवसर पर, सबसे पहले, हमारी केन्द्रीय कमेटी अपनी पार्टी के संस्थापक-नेता व महान शिक्षक कॉमरेड्स चारु मजुमदार और कन्हाई चटर्जी को श्रद्धांजलि पेश करती है। हम फिर एक बार शपथ लेते हैं कि जब तक उनके सपनों का नया भारत, जोकि हर प्रकार के शोषण व उत्पीड़न से मुक्त हो, स्थापित किया नहीं जाता, तब तक विश्राम नहीं करेंगे।

पिछले 28 जुलाई से अभी तक एक साल में शोषित जनता की कई प्यारी संतानों ने नई जनवादी क्रांति की विजय के लिए मुस्कराते हुए अपने अनमोल प्राणों की आहुति दी है। इनमें से कइयों को पुलिस ने पकड़ने के बाद हत्या कर 'मुठभेड़' की कहानियां गढ़ दीं। कुछ और कॉमरेडों ने दुश्मन के साथ आमने-सामने लड़ते हुए अपनी जानें कुरबान कर दीं। और कई आम लोगों की मौत 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के तहत पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों द्वारा जारी अंधाधुंध गोलीबारियों

व नरसंहारों में और यातनाओं से हुई। चंद कॉमरेडों की शहादत बीमारी के चलते या हादसों में हुई। इस तरह देश भर में 250 से ज्यादा क्रांतिकारी आंदोलन के नेता, कार्यकर्ता, सदस्य और जनता शहीद हुए हैं। शहीदों में पार्टी के पोलिटब्यूरो सदस्य व प्रवक्ता कॉमरेड आजाद (चेरुकूरी राजकुमार); पार्टी के मिलिटरी इंटलिजेन्स के केन्द्रीय निर्देशक व वरिष्ठ राज्य स्तर के नेता कॉमरेड शाखामूरी अप्पाराव; और पीएलजीए की मध्य रीजनल कम्पनी-2 के राजनीतिक कमिस्सार व राज्य स्तर के नेता कॉमरेड जीवन (सूर्यम) समेत विभिन्न स्तरों के पार्टी नेता, पीएलजीए कमाण्डर व पार्टी/जन संगठन सदस्य शामिल हैं। कॉमरेड्स शारदा (रामक्का), नर्मदा, स्वर्णा जैसी वरिष्ठ महिला साथियों समेत कई महिलाएं भी शहीद हुई हैं। 12 मार्च को तकनीकी विभाग के वरिष्ठ कॉमरेड कोण्डलरेड्डी (रमणा) को महाराष्ट्र शहर से पुलिस ने उठाया था और बाद में आंध्रप्रदेश के वरंगल जिले के जंगलों में ले जाकर गोली मार दी। कॉमरेड आजाद के साथ सफर कर रहे हेमचंद्र पाण्डे को भी आजाद के साथ ही पुलिस ने गोली मार दी। उत्तर तेलंगाना में कॉमरेड्स दया, रमेश, भास्कर, पुन्नम और सुरेश दुश्मन के हमलों में शहीद हुए।

दण्डकारण्य में गड़चिरोली डिवीजनल कमेटी सदस्य कॉमरेड मंगेश (साईनाथ) ने पिछले 8 अक्टूबर को लहेरी के पास दुश्मन के कमाण्डो बलों के साथ बहादुराना लड़ाई लड़ते हुए शहादत को हासिल किया। 6 अप्रैल को हुए ऐतिहासिक ताड़िमेट्ला ऐम्बुश में आठ नौजवान कॉमरेडों - रुकमति, वागाल, विज्जाल, इंगाल, राजू, मंगू, रामाल और रतन ने शौर्यपूर्ण लड़ाई लड़ते हुए अपनी जानें कुरबान कीं। 29 जून को नारायणपुर जिले के कोंगेरा के पास किए गए एक और साहसिक कारनामे में कम्पनी पार्टी कमेटी सदस्य/प्लटून कमाण्डर कॉमरेड्स बण्डू और शंकर तथा प्लटून पार्टी कमेटी सदस्य कॉमरेड रमेश - तीन कॉमरेडों ने अनुपम पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अपने प्राणों को अर्पित किया। 15 फरवरी को पश्चिम बंगाल के सिल्दा में दुश्मन के कैम्प पर किए गए जबर्दस्त हमले में पांच कॉमरेड शहीद हुए थे। जून महीने में पश्चिम बंगाल के जंगलमहल में हुए दुश्मन के हमले में 8 कॉमरेडों की जानें गईं। 16 जून को झारखण्ड के सरंडा इलाके में पार्टी के उच्च नेतृत्व का उन्मूलन करने की साजिश के तहत 2,000 पुलिस, अर्ध-सैनिक व कोबरा बलों ने तीन वायुसैनिक हेलिकॉप्टरों की मदद से एक कैम्प पर हमला किया था। इस हमले को विफल करते हुए, पार्टी-नेतृत्व की रक्षा करते हुए और शत्रु बलों का सफाया करते हुए सेक्शन कमाण्डर कॉमरेड

डेविड ने अपने प्राणों का बलिदान किया। इन तमाम शहीदों को हमारी केन्द्रीय कमेटी विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि पेश करती है... शहीदों के परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है।

देश के शासक वर्गों द्वारा लागू साम्राज्यवाद-परस्ती लूटखसोट की नीतियों के खिलाफ जनता हर जगह सड़कों पर उतरकर लड़ रही है। देश के कई इलाके जन संघर्ष के गढ़ों के रूप में उभरकर आ रहे हैं। शासकों ने यह सोचकर कि इन जन संघर्षों को कुचल दिए बिना अपनी लूटखोर नीतियों को लागू करना नामुमकिन है, उन्हें खून की नदियों में डुबोने की कोशिशें कर रहे हैं। ओड़िशा के कलिंगनगर में अपनी जमीनें सौंपने से इनकार करने वाले आदिवासियों पर गोलियां बरसाकर कई लोगों की जानें लेना और अभी-अभी 13 जुलाई को आंध्रप्रदेश के सोंपेटा में प्रस्तावित थर्मल बिजली परियोजना से अपने अस्तित्व को हो सकने वाले खतरे के मद्देनजर विरोध जता रही जनता पर गोलीबारी कर तीन लोगों की हत्या करना इसके चंद उदाहरण हैं। शोषक शासक यह दिवास्वप्न देख रहे हैं कि वे जन संघर्षों की अगुवाई करने वाली ताकतों का भौतिक रूप से उन्मूलन कर उन आंदोलनों की कमर तोड़ पाएंगे। जमीन के लिए संघर्ष कर रहे नारायणपटना (ओड़िशा) इलाके में आंद्रू और सिंगन्ना तथा पुलिसिया दमनचक्र के खिलाफ लड़ रहे लालगढ़ (पश्चिम बंगाल) इलाके में लालमोहन टुडू जैसे जन नेताओं की गोली मारकर हत्या कर मुठभेड़ के रूप में चित्रित करना इसका उदाहरण है। उन तमाम लोगों और जन नेताओं को हमारी केन्द्रीय कमेटी सिर झुकाकर लाल सलाम करती है जो पिछले एक साल के दौरान देश भर में लुटेरे शासक वर्गों के खिलाफ जन आंदोलन चलाते हुए हत्या का शिकार हुए थे।

क्रांतिकारी आंदोलन का समूल उन्मूलन कर देश की सभी संपदाओं और प्राकृतिक संसाधनों को साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और दलाल पूंजीपतियों के हाथों लुटवाने के इरादे से देश के शासक गिरोह द्वारा छेड़े गए ऑपरेशन ग्रीन हंट के तहत, खासकर दण्डकारण्य के बस्तर इलाके में बड़े पैमाने पर आदिवासियों का नरसंहार किया जा रहा है। पिछले 10 महीनों के दौरान अकेले दण्डकारण्य में ही करीब 150 आदिवासियों को पुलिस, अर्ध-सैनिक बलों और एसपीओ ने मौत के घाट उतार दिया। इनमें से ज्यादातर लोगों की मौतों को 'मुठभेड़' के रूप में घोषित किया गया जबकि कुछ लोगों की हत्याएं दर्ज तक नहीं हुईं। गोल्लागूड़ेम, वेच्चापाड़, सिंगनमडुगू, पालाचेलमा, गोमपाड़, टेट्टेमडुगू, गुमियापाल, कुटरेम,

ताकिलोड़, ओंगनार, राजूवेड़ा... ऐसे कई गांवों में आम जनता को गोली मारकर 'मुठभेड़' की कहानियां गढ़ दी गईं। दूसरे राज्यों में भी आम जनता को गोली मारकर मुठभेड़ की कहानियां गढ़ देने की कई घटनाएं हुई हैं। जनता के खिलाफ शोषक शासक वर्गों द्वारा छेड़े गए युद्ध के तहत सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा मचाए जा रहे अंधाधुंध हत्याकाण्डों में अपनी जानें गंवाने वाली तमाम जनता को हमारी केन्द्रीय कमेटी विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि पेश करती है।

इसके साथ-साथ महान विश्व समाजवादी क्रांति के तहत दुनिया के कई देशों में जारी साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्षों और सभी न्यायपूर्ण संघर्षों में तथा कश्मीर व पूर्वोत्तर के इलाकों में जारी राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों में प्राण गंवाने वाले योद्धाओं और जनता को हमारी केन्द्रीय कमेटी तहेदिल से श्रद्धांजलि पेश करती है।

वीर शहीदों के आदर्शों, लड़ाकूपन, दृढ़ संकल्प और बलिदान की भावना को ऊंचा उठाए रखें!

1 जुलाई को खून के प्यासे एपीएसआईबी और केन्द्रीय खुफिया संस्थाओं के हत्यारों ने पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड आजाद को उनके साथ सफर कर रहे एक स्वतंत्र पत्रकार हेमचंद्र पाण्डे के साथ महाराष्ट्र के नागपुर इलाके से उठाकर आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद के जंगलों में ले जाकर 'मुठभेड़' के नाम से गोली मार दी। कॉमरेड आजाद की मृत्यु से भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। वरंगल रीजनल इंजिनीयरिंग कॉलेज में क्रांतिकारी छात्र के रूप में शुरू कर पिछले करीब चार दशकों से भारतीय क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले कॉमरेड आजाद ने मुख्य रूप से सैद्धांतिक व राजनीतिक मोर्चों पर बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया। पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, क्रांतिकारी प्रचारक के रूप में, कई क्रांतिकारी पत्रिकाओं के सम्पादक के रूप में, लेखक के रूप में, संगठनकर्ता के रूप में, आंदोलनकारी के रूप में, साहित्यकार के रूप में, रंग-बिरंगे संशोधनवादियों व कई प्रतिक्रियावादियों के सड़े-गले सिद्धांतों व कुतर्कों को चकनाचूर कर मार्क्सवाद को अपराजेय बताकर बुलंद रखने वाले सर्वहारा बुद्धिजीवी के रूप में, देश में क्रांतिकारी ताकतों के एकीकरण के लिए प्रयास करने वाले कम्युनिस्ट योद्धा के रूप में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारी संगठनों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भरसक प्रयास करने वाले सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवादी के रूप में.... कॉमरेड आजाद ने अतुलनीय योगदान दिया। पिछले 40 सालों से जारी भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के विकासक्रम से कॉमरेड आजाद को अलग

करना असंभव है। हमारी केन्द्रीय कमेटी देश की युवा पीढ़ी, छात्र-बुद्धिजीवियों और मजदूर-किसानों का आह्वान करती है कि कॉमरेड आजाद के आदर्शों को आत्मसात करते हुए उनके द्वारा सौंपे गए लाल झण्डे को गर्व के साथ ऊंचा उठाए रखें।

12 मार्च को आंध्रप्रदेश के एसआईबी हत्यारों ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और मिलिटरी इंटलिजेन्स विभाग के केन्द्रीय निर्देशक कॉमरेड शाखामूरी अप्पाराव की गोली मारकर मुठभेड़ की कहानी प्रसारित की। पिछले 32 सालों से ज्यादा समय से क्रांतिकारी आंदोलन से गुंथी हुई कॉमरेड शाखामूरी की जिंदगी आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी। क्रांतिकारी छात्र आंदोलन में शामिल होकर इंजिनीयरिंग की पढ़ाई छोड़कर जल्द ही पूर्णकालीन क्रांतिकारी बनकर कुरियर (संदेशवाहक) के रूप में, संगठनकर्ता के रूप में, जिला, रीजनल व राज्य कमेटियों में सदस्य के रूप में, मिलिटरी इंटलिजेन्स विभाग के केन्द्रीय निर्देशक के रूप में उभरने वाले कॉमरेड शाखामूरी खासकर आंध्रप्रदेश के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में अपनी छाप छोड़ गए। कइयों के लिए प्रेरणा बनकर, कइयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़कर और अनगिनत लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ने वाले कॉमरेड शाखामूरी दुश्मन के लिए आखिर तक एक चुनौती बनकर डटे रहे। दुश्मन के दावपेंचों का हमेशा अध्ययन कर पार्टी व पीएलजीए को उसके अनुरूप तैयार करने के काम में उन्होंने जो भूमिका अदा की उसे सदा याद रखा जाएगा। 8 मई को शत्रु बलों पर किए गए ऐम्बुश में घायल होकर बाद में दम तोड़ने वाले कॉमरेड जीवन (सूर्यम) की मृत्यु मध्य रीजियन के जनयुद्ध के क्षेत्र में काफी बड़ा नुकसान है। आंध्रप्रदेश राज्य कमेटी के सदस्य के तौर पर काम कर चुके कॉमरेड सूर्यम पिछले कुछ समय से मध्य रीजियन के दायरे में - दण्डकारण्य, आंध्र-ओड़िशा सीमांत स्पेशल जोन और उत्तर तेलंगाना में जन सेना द्वारा अंजाम दी गई कई सैन्य कार्रवाइयों में अहम भूमिका निभाते रहे। नयागढ़ जैसी सैन्य ऑपरेशन्स को सफल बनाने में उनका खासा योगदान रहा। उनकी मृत्यु से पार्टी और पीएलजीए जनयुद्ध के एक जबर्दस्त कमाण्डर से वंचित हो गई।

क्रांति में कुरबानियां अनिवार्य हैं। यह क्रांतियों का युग है। जनता ही इतिहास का निर्माता है। जनता और जन आंदोलन ने ही आजाद जैसे महान क्रांतिकारी बुद्धिजीवी को, शाखामूरी जैसे मंजे हुए कम्युनिस्ट योद्धा को, सूर्यम जैसे जनयुद्ध के बहादुर कमाण्डर को, आंद्रू, सिंगन्ना, लालमोहन जैसे जन नेताओं को पैदा

किया... और करते करेंगे। जनयुद्ध ने ही मंगेश, रुकमति, डेविड, बंण्डू, रमेश जैसे जांबाजों को पैदा किया... और करता करेगा। इसलिए क्रांतिकारी जन आंदोलनों और जनयुद्ध को तेज करते हुए उन्हें और भी उन्नत स्तर पर विकसित करके ही तथा सैकड़ों-हजारों की संख्या में नई ताकतों को क्रांतिकारी आंदोलन में आकर्षित करके ही हम शहीदों के सपनों को साकार कर सकेंगे.... उनकी कमी को पाट सकेंगे। जनता और पार्टी के कतारों से हमारी केन्द्रीय कमेटी का आह्वान है कि शहीद सप्ताह के मौके पर यही संकल्प लिया जाए।

अभय

प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

30 अगस्त 2010

पार्टी की ऐतिहासिक 6वीं वर्षगांठ को ऊंचा उठाए रखो!
फासीवादी ऑपरेशन ग्रीन हंट को हरा दो!
देश की लूटखसोट के खिलाफ सांझे संघर्ष के लिए एकजुट हो!

हमारी पार्टी की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर 21 से 27 सितम्बर तक क्रांतिकारी जोशोखरोश के साथ मनाने का पोलिटब्यूरो का आह्वान

प्यारे कॉमरेडो और लोगो,

21 सितम्बर 2010 को हमारी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी, पीएलजीए, क्रांतिकारी जन कमेटियों और जन संगठनों के तमाम कॉमरेडों और क्रांतिकारी जनता को, जो दुश्मन के देशव्यापी भारी प्रति-क्रांतिकारी फौजी आक्रमण - ऑपरेशन ग्रीन हंट का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं, तहेदिल से क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करती है। इस अवसर पर हमारी पोलिटब्यूरो जेलों में कैद उन तमाम कॉमरेडों को क्रांतिकारी बधाई देती है जो अदम्य साहस के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं।

हमारी पोलिटब्यूरो उन 10 हजार से ज्यादा महान शहीदों को जो पिछले 45 सालों के दौरान शहीद हुए थे, और 2004 में एकीकृत पार्टी की स्थापना के बाद से अब तक शहीद हुए 1500 से ज्यादा शहीदों को और पिछले एक साल के दौरान शहीद हुए 300 से ज्यादा शहीदों को विनम्र श्रद्धांजली पेश करती है, जिन्होंने भारत की नई जनवादी क्रांति की सफलता के लिए तथा मानवजाति के महानतम लक्ष्य समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना के लिए अपने अनमोल प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इनमें से ज्यादातर शहीद आम लोग थे और क्रांतिकारी जन संगठनों व जन मिलिशिया के सदस्य थे। इस सचाई से यह साफ हो जाता है कि भारत के व्यापक जन समुदाय क्रांति में कूद पड़ रहे हैं।

पिछले साल हमारी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के बाद से क्रांति और प्रति-क्रांति के बीच युद्ध और ज्यादा तीखा हुआ। इस अवधि में रणनीतिक महत्व रखने वाले कई बदलाव हुए हैं जिससे आने वाले लम्बे समय तक भारतीय क्रांति पर प्रभाव पड़ेगा। इस अवसर पर हमारी ताकत और कमजोरियों को तथा क्रांति के

लिए अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों को जनता और पार्टी के कतारों के सामने पेश करने की जरूरत है।

सबसे पहले - मई 2009 से जुलाई 2010 तक पोलिटब्यूरो सदस्य और प्यारे नेता कॉमरेड आजाद समेत आठ अग्रणी नेताओं और राज्य स्तर के दस नेताओं को दुश्मन ने या तो पकड़कर मार डाला या फिर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। जिला स्तर और निचले स्तरों के कई कॉमरेड गिरफ्तार कर लिए गए या फिर मार डाले गए। इन सभी नुकसानों ने हमारी पार्टी और आंदोलन पर गंभीर प्रभाव डाला। खासकर कॉमरेड आजाद हमारी पार्टी की उच्चतम कमेटी में अहम जिम्मेदरियां निभाने वाले कॉमरेड थे और उन्होंने कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली तरीके से बहुमुखी योगदान दिया था। इस तरह यह हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है।

2004 में स्थापना के बाद नई पार्टी ने देश की जनता के सामने समृद्ध राजनीतिक, सांगठनिक व सैनिक लाइन को, मजबूत पार्टी-नेतृत्व को, एक जन सेना - पीएलजीए, व्यापक जनाधार तथा संघर्ष के व्यापक इलाकों को प्रस्तुत किया। इससे क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ। इन अनुकूल परिणामों को देख घबरा जाने वाले दुश्मन ने हमारी पार्टी को कुचलने का फैसला लिया और 2005 व 2006 में हुए सारे नुकसान इसी साजिश का परिणाम थे। फिर भी 2007 में सफलतापूर्वक आयोजित पार्टी की एकता कांग्रेस - 9वीं कांग्रेस ने हमारी पार्टी की एकता और पार्टी नेतृत्व को मजबूत बनाया और क्रांति को आगे बढ़ाने की सटीक योजना बनाई। हालांकि आंध्रप्रदेश और उत्तर छत्तीसगढ़ में आंदोलन को धक्का लगा था और उत्तर ओड़िशा में भारी नुकसान हुए थे, फिर भी हमारी कामयाबियों ने क्रांतिकारी खेमे को आत्मविश्वास से लबालब कर दिया।

एकता कांग्रेस के सफल आयोजन और बाद में अर्जित कामयाबियों ने दुश्मन के खेमे को बेहद डरा दिया, इसलिए दुश्मन ने जनता के खिलाफ अभूतपूर्व स्तर पर युद्ध छेड़ दिया ताकि पार्टी नेतृत्व का सफाया किया जा सके। मई 2009 के बाद हुए ये नुकसान संख्या और तीव्रता के हिसाब से पिछले नुकसानों से भारी हैं। नुकसान चाहे कितने ही गंभीर हों, क्रांतिकारी आंदोलन के पिछले 45 सालों के इतिहास में नया नेतृत्व हमेशा उभरता ही रहा और आगे भी यह सिलसिला जारी ही रहेगा। जब तक जन समुदायों को क्रांति की जरूरत रहेगी, वे अपने नेताओं को पैदा भी करेंगे।

दूसरा - यूपीए-2 ने फासीवादी 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' छेड़ दिया जोकि

चौतरफा आक्रमण की रणनीति का ठोस स्वरूप है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए भारतीय शासक वर्गों द्वारा अब तक बनाई गई सभी आक्रमणकारी रणनीतियों में से 2009 के मध्य से शुरू होकर चल रहा यह हमला अभूतपूर्व है, देशव्यापी है, तीव्रतम है, धोखाधड़ीपूर्ण है, केंद्रीकृत है और दीर्घकालीन है। यह दमनकारी सैन्य अभियान हमारे मजबूत ग्रामीण इलाकों तथा गुरिल्ला जोनों में, खासकर दण्डकारण्य, बिहार-झारखण्ड, लालगढ़ तथा झारखण्ड-ओड़िशा, आंध्रप्रदेश-ओड़िशा और तेलंगाना-छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में केन्द्रीकृत है। इस 'जनता के खिलाफ युद्ध' ने सामाजिक अंतरविरोधों को तीखा कर दिया। पिछले 45 सालों में ऑपरेशन ग्रीन हंट की तुलना में दूसरे किसी भी दमनकारी अभियान को जनता की तरफ से इतना विरोध व प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था।

तीसरा - यूपीए-2 के दौरान विद्रोह-विरोधी सिद्धांतों को, जिसके तहत राज्य यंत्र, भारतीय संविधान, न्यायव्यवस्था, विधायिका, प्रशासन-तंत्र, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, मीडिया आदि को या तो पुनरनिर्माण या फिर प्रभावित कर रहे हैं, लागू करने में एक गुणात्मक बदलाव आया है। अमेरिकी साम्राज्यवादियों के नेतृत्व में साम्राज्यवादियों द्वारा छेड़े गए 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' से इसे संबल मिला हुआ है। यह हमारे देश को एक विनाशकारी परिस्थिति की तरफ धकेल देगा। इस बर्बर युद्ध को जारी रखने की वो जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतने ही ज्यादा विरोध और प्रतिरोध का सामना उन्हें व्यापक जन समुदायों की तरफ से करना पड़ेगा। देश भर में इस तरह के प्रतिरोध को हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं।

पिछले एक साल के दौरान सभी मोर्चों पर चलाए गए संघर्षों और हमारे करीब तीन सौ आदरणीय व प्यारे कॉमरेडों की शहादत की बदौलत हमने कुछ महत्वपूर्ण कामयाबियां हासिल की हैं। वो हैं:

1. छत्तीसगढ़ में सिंगनमडुगु, मुकरम (ताड़िमेटला) और कोंगेरा; महाराष्ट्र में लाहेरी; पश्चिम बंगाल में संकरेल और सिल्दा; झारखण्ड में विष्णुपुर व लातेहार; बिहार में सोनो, सरकारी टोल प्लाज़ा (गया) और टांडवा बाजार; ओड़िशा में पोतकल और बैफरगुड़ा के पास किए गए हमलों ने, खासकर ऐतिहासिक मुकरम (ताड़िमेटला) हमले ने दुश्मन के मनोबल को तोड़ दिया और गुरिल्ला बलों की पहलकदमी को दोगुना कर दिया। इन हमलों ने पीएलजीए को ज्यादा हथियारों और नए अनुभवों से लैस कर दिया। ताड़िमेटला का अनुभव इन सभी में उच्च स्तर का

है। अगर इस तरह हमारे बलों और जनता का सक्रिय प्रतिरोध न होता, तो दुश्मन को हमारे आंदोलन का सफाया करने के लिए ज्यादा मौका मिल जाता। इन महान अनुभवों से उन शत्रु बलों का मुकाबला करने में हमें निश्चित रूप से मदद मिलेगी जो एक भारी हमले के लिए तैनात किए जा रहे हैं। यह जनता का सक्रिय समर्थन ही है जिसकी नींव पर हमने ये तमाम कामयाबियां हासिल कीं।

2. कलिंगनगर, सिंगूर और नंदीग्राम के संघर्षों और बाद में व्यापक और उन्नत स्तर पर फूट पड़े लालगढ़ व नारायणपटना के संघर्षों ने शासक वर्गों को झकझोर दिया। संशोधनवाद या दक्षिणपंथी अवसरवाद के खिलाफ तथा दुश्मन वर्ग साम्राज्यवादियों व राज्य के खिलाफ चले इन संघर्षों का हमारी पार्टी ने नेतृत्व किया। पिछले 25 बरसों में इस तरह के व्यापक, जुझारू और लम्बे समय तक चले जन विद्रोहों का उभार कभी नहीं देखा गया। जनयुद्ध के विकास के लिए इन क्रांतिकारी जन विद्रोहों से मिली शिक्षा अनमोल है।

3. जबकि दुश्मन ने अपने बलों को बड़े पैमाने पर तैनात कर किसान विद्रोह को कुचलने की कोशिश कर रहा था, लालगढ़ सशस्त्र किसान आंदोलन फूट पड़ा, उसका फैलाव हुआ और वह मजबूत हुआ, जोकि बेहद महत्वपूर्ण है। और इसने भारत के सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी संघर्ष के इतिहास के पन्नों में एक खास स्थान प्राप्त किया।

4. भारत के पूर्वी और मध्य इलाकों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े पूंजीपतियों के कॉर्पोरेशनों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए की गई कोशिशों को व्यापक जनता ने हमारी पार्टी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। हमारी पोलिटब्यूरो तमाम जनता का, क्रांतिकारी, जनवादी, प्रगतिशील व देशभक्तिपूर्ण संगठनों तथा शख़्सों का क्रांतिकारी अभिनंदन करती है जो इन संघर्षों में मजबूती से डटे रहे। और हम वादा करते हैं कि हमारी पार्टी इन संघर्षों की अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहेगी।

5. दुश्मन के मनोवैज्ञानिक युद्ध के खिलाफ हमारी पार्टी ने कॉमरेड आजाद के नेतृत्व में विचारधारात्मक व राजनीतिक प्रचार-युद्ध चलाया। कॉमरेड आजाद के साथ-साथ हमारी समूची पार्टी विभिन्न स्तरों पर अगर इस तरह नहीं लड़ती तो जनयुद्ध को इतना सम्मान नहीं मिलता। इस मोर्चे पर उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण व सर्वोच्च रहा। आइए, कॉमरेड आजाद की प्रेरणा से हम इस क्षेत्र में लड़ाई को जारी रखें।

इन पांच प्रमुख सफलताओं के साथ-साथ, कुछ राज्यों में हमारा संघर्ष नए इलाकों में फैल गया। पार्टी और पीएलजीए राजनीतिक व फौजी तौर पर मजबूत हुई। मौजूदा क्रांतिकारी जन कमेटियों/जनताना सरकारों को नए इलाकों में विस्तारित किया गया। इन सभी सफलताओं की बदौलत हम कई क्रांतिकारी ताकतों, बुद्धिजीवियों, जनवादियों, प्रगतिशील व देशभक्तिपूर्ण ताकतों का समर्थन जुटाने में कामयाब हो गए।

कॉमरेडो,

हमारे नुकसान बेहद गंभीर थे। अगर केन्द्रीय कमेटी से लेकर निचली कमेटियों तक सभी कमेटियां और समूची पार्टी सुनियोजित तरीके से और भी बड़े पैमाने पर नई ताकतों का निर्माण करने के लिए पूरा जोर लगाकर काम नहीं करती हैं और भूल-सुधार अभियान को सुचारू रूप से जारी नहीं रखती हैं, तो हमें हुए नुकसानों, खासकर कॉमरेड आजाद और केन्द्रीय व राज्य स्तर के खोए हुए दूसरे नेतृत्वकारी कॉमरेडों की भरपाई असंभव है।

इन नुकसानों के वास्तविक कारणों को समझने से ही हम उनकी रोकथाम कर पाएंगे और तभी हमारी पार्टी को मजबूत व दुश्मन के लिए अभेद्य बना पाएंगे। हमारी पार्टी और दूसरे देशों की माओवादी पार्टियों के अनुभवों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए ताकि असली कारणों को चिन्हित किया जा सके।

देश में और दूसरे देशों में संघर्षरत ताकतों से एकजुटता कायम करते हुए हमें अपने आत्मरक्षात्मक युद्ध को विस्तारित व तेज करना चाहिए जिसे हमारी पार्टी की अगुवाई में पीएलजीए और जनता अंजाम दे रही हैं। अगर हम जनता पर मजबूती से निर्भर करते हैं और इस युद्ध में पीएलजीए का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ऑपरेशन ग्रीन हंट को पराजित करने में हम निश्चित रूप से सक्षम हो जाएंगे।

आइए, हम जनयुद्ध को बेहद साहस और दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखने के लिए खुद को तैयार कर लें। हमारी पार्टी की 6वीं वर्षगांठ को पूरे इंकलाबी जोशोखरोश के साथ मनाएं। पिछले एक साल की अवधि में घोर दमन के बीचोबीच भी अर्जित की गई सफलताओं का व्यापक रूप से प्रचारित करें।

प्यारे कॉमरेडो व देशवासियो!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) देश की समूची जनता का आह्वान

करती है कि हमारे देश को साम्राज्यवादियों के हाथों बेचने वाले सामंती व दलाल शासकों के खिलाफ हमारी पार्टी के नेतृत्व में एकजुट हों। एक क्रांतिकारी पार्टी के बिना इन शोषकों के शिकंजे से हमारे देश को आजाद करना नामुमकिन है। देश में मची हुई लूटखसोट के खिलाफ जारी विभिन्न प्रतिरोधी संघर्षों में डटे हुए तमाम लोगों का हमारी पार्टी आह्वान करती है कि वे एकजुट हो जाएं ताकि एक व्यापक संयुक्त मोर्चे का रास्ता साफ हो सके। जोतने वालों को जमीन के लिए, जनता को जनवादी सत्ता के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए जारी संघर्षों तथा सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्रों), विस्थापन, कॉर्पोरेट खनन परियोजनाओं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, महंगाई, भ्रष्टाचार और ऐसी तमाम ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ संघर्षों को एकजुटता के साथ चलाना चाहिए। हम अपनी एकजुट ताकत के जरिए ही कामयाबी हासिल कर सकेंगे। ज्यों-ज्यों हमारी लड़ाई तेज होगी, सभी जनवादी व क्रांतिकारी संषर्षों के खिलाफ राज्य का हमला भी तीखा होगा। आइए, हम खुद को इसके लिए तैयार कर लें। जन जागरण, सलवा जुडुम, सेंदेरा, ग्रीन हंट आदि कोई भी प्रतिक्रियावादी ताकत दृढ़ संकल्प से लैस जनता या उनकी क्रांतिकारी पार्टी को तोड़ नहीं सकती। अंतिम जीत जनता की ही है।

- **हमारी पार्टी को एक अभेद्य किले के रूप में मजबूत करेंगे और नेतृत्व व कतारों में भारी नुकसानों की रोकथाम करेंगे!**
- **ताड़िमेटला लड़ाई को ऊंचा उठाकर तथा इस बेजोड़ नमूने का अनुसरण करते हुए 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' को हराएंगे!**
- **सभी प्रतिरोधी आंदोलनों में एकजुटता कायम कर तथा उनके साथ एकजुट होकर एक मजबूत व देशव्यापी संयुक्त मोर्चे की नींव रखेंगे!**
- **कॉमरेड आजाद के आदर्शों को ऊंचा उठाकर उनके योगदान को मिसाल बनाकर दुश्मन के मनोवैज्ञानिक युद्ध का सुचारू तरीके से मुकाबला करेंगे!**
- **जनयुद्ध के बहुमुखी कार्यभारों की पूर्ति के लिए व्यापक इलाकों में विस्तार करेंगे!**

अभय

प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

23 सितम्बर 2010

अपनी आजादी के लिए आंदोलन कर रहे कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहे भारतीय शासक वर्गों की दरिंदगी की निंदा करो!

सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा लगातार जारी हत्याओं के खिलाफ तथा कश्मीरी जनता के न्यायपूर्ण आंदोलन के समर्थन में... 30 सितम्बर 2010 को 24 घण्टों का 'भारत बंद' सफल बनाओ!

कश्मीर में सरकार द्वारा लोगों की हत्याओं का सिलसिला बेलगाम जारी है। सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा लगातार जारी मनमानी हत्याओं, अत्याचारों, बिना रुके जारी कर्फ्यू आदि की अवहेलना करते हुए पूरी कश्मीर की घाटी में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। 'आजादी' का नारा समूची घाटी में गूंज रहा है। 11 जून से शुरू कश्मीरी जनता के इस न्यायपूर्ण संघर्ष को कुचलने के लिए अर्ध सैनिक, सैनिक व पुलिस बलों द्वारा की जा रही गोलीबारियों में अभी तक सौ से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। (इनमें अत्यधिक बीस साल से कम उम्र के किशोर व नौजवान हैं।) सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। निहत्थे, शांतिपूर्ण व न्यायपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे कश्मीरियों पर भारत के विस्तारवादी लुटेरे शासक वर्ग, जो अपने को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं, बेशर्मी के साथ सशस्त्र बलों को उकसाकर बेहद क्रूरता से दमन कर रहे हैं। जहां कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार, खुद को वामपंथी कहने वाली सीपीएम व सीपीआई समेत सभी शासक पार्टियां कश्मीरियों पर हो रहे इस दमनचक्र का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन कर रही हैं, वहीं हिंदू साम्प्रदायिकतावादी भाजपा सरकार को बार-बार उकसा रही है कि वह कश्मीरियों का बेहद सख्ती से दमन करे। केन्द्र सरकार द्वारा कश्मीरी जनता पर जारी हिंसा में भाग लेने वाले भारतीय शासक वर्गों का वफादार सेवक ओमर अब्दुल्ला की सरकार जनता से पूरी तरह अलग-थलग पड़कर उनकी तीखी नफरत का शिकार बन रही है। लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़ने के साथ-साथ हर प्रदर्शन पर

गोलीबारी करना एक रिवाज सा बन गया है। इसी पृष्ठभूमि में कश्मीरी जनता, खासकर नौजवान हाथ में आए पथ्तरों से ही इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। इस अमानवीय दमनचक्र के विरोध में और अपनी आत्मरक्षा के लिए किया जा रहा यह प्रतिरोध पूरी तरह न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक है।

कश्मीरी जनता ने खुद को कभी भी भारत का हिस्सा नहीं माना। 1947 में अंग्रेजी शासकों से भारत और पाकिस्तान को मिली झूठी आजादी के पहले तक कश्मीर राजा हरिसिंह के शासन में एक स्वतंत्र देश के रूप में था। लेकिन कुटिलता में माहिर ब्रितानी साम्राज्यवादियों के पिट्ठू भारतीय व पाकिस्तानी लुटेरे शासक वर्गों ने अपने हितों के मद्देनजर कश्मीर को अपने देशों में जबरन मिला लिया जोकि कश्मीरियों की इच्छाओं और आकांक्षाओं से पूरी तरह खिलाफ था। एक हिस्से पर भारतीय शासक वर्गों ने कब्जा किया तो बाकी हिस्से को पाकिस्तान ने हड़प लिया। इस तरह बेहद निंदनीय तरीके से इन्होंने कश्मीर को दो टुकड़ों में बांट दिया। उस समय कश्मीरियों के विरोध को ठण्डा करने के लिए नेहरू सरकार ने लिखित रूप से कश्मीरी जनता व संयुक्त राष्ट्र संघ से यह वादा किया था कि कश्मीर में रायशुमारी (जनमत संग्रह) कराई जाएगी और जनता अगर आजादी चाहती है तो दे दी जाएगी। नेहरू ने इस वादे को कई बार दोहराया भी था। लेकिन कुछ ही समय बाद से उन्होंने सैन्य जूतों तले कश्मीर को रौंदना शुरू किया। नेहरू से लेकर आज के सोनिया-मनमोहन तक दिल्ली में गद्दी संभालने वाली हर शासक पार्टी ने कश्मीरियों के साथ वादाखिलाफी ही की। जब भी आजादी के लिए आवाज उठी, भारतीय विस्तारवादी सरकारों ने कश्मीरियों पर दमन का ही प्रयोग किया। आंखों के सामने घट रहे इतिहास को और अपने ही किए हुए वादों को छुपाते हुए भारतीय शासक सुनियोजित तरीके से यह प्रचार करते आ रहे हैं कि 'कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।' तबसे कश्मीरियों के दिलों में सुलगती आई आजादी की अदम्य इच्छा ने 1990 के दशक में मिलिटेंट हथियारबंद आंदोलन का रूप ले लिया। कई मिलिटेंट संगठनों ने हथियारबंद संघर्ष चलाया। उन संगठनों के राजनीतिक लक्ष्यों में कुछ फर्क होने के बावजूद उन्हें जनता का समर्थन हासिल हुआ था क्योंकि उन्होंने कश्मीरियों की राष्ट्रीय मुक्ति की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त किया। लेकिन उस संघर्ष को कुचलने के लिए भारत के फासीवादी शासक वर्गों ने 7 लाख से ज्यादा सैनिक और अर्ध सैनिक बलों को तैनात कर समूची कश्मीर की घाटी का सैन्यीकरण किया और अभी तक 80 हजार से ज्यादा कश्मीरियों की जानें लीं। हजारों लोगों को सरकार ने लापता कर दिया। यह कहना

गलत नहीं होगा कि दुनिया की किसी भी राष्ट्रीयता के संघर्ष पर किसी भी सरकार ने इतने ज्यादा समय तक, इतनी तीव्रता से, इतनी भारी संख्या में सशस्त्र बलों को उतारकर, इतने क्रूर तरीके से दमन नहीं किया। जब मिलिटेंट आंदोलन तीखे रूप से चल रहा था, तभी भारतीय शासक वर्गों ने कई साजिशों और षड़यंत्रों को रचकर 'फूट डालो और राज करो' वाली नीति से कश्मीरी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़ा पैदा किया। कश्मीरी जनता के जायज आंदोलन के खिलाफ कश्मीरी पंडितों को खड़ा करने की साजिशें लगातार जारी हैं। इसमें विशेषकर विस्तारवादी देशीय अंधराष्ट्रवादी कांग्रेस और हिंदू धार्मिक साम्प्रदायिकतावादी फासीवादी संघ गिरोह की भूमिका बेहद नीचतापूर्ण है। 'मिलिटेन्सी' के रूप में प्रचलित कश्मीरियों के उस संघर्ष में कुछ पाकिस्तान-अनुकूल ताकतों और इस्लामिक ताकतों के शामिल होने के बहाने भारतीय शासकों का यह प्रचार कि कश्मीरियों का राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम पूरी तरह पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आंदोलन है तथा उनके आंदोलन का लक्ष्य भारत से अलग होकर पाकिस्तान में शामिल हो जाना है, सरासर झूठ है। कश्मीरी जनता की आकांक्षा शुरू से ही अपनी राष्ट्रीयता की आजादी रही है। यही वजह है कि कश्मीर में मिलिटेन्सी को खत्म करने के दावे भले ही भारतीय शासक करते रहें, दरअसल यह संघर्ष रुका ही नहीं। अलग-अलग मौकों पर जिस किसी भी मुद्दे को लेकर यह आंदोलन उफान पर आया हो, 'आजादी' का नारा ही उसमें प्रमुखता से उठाया जाना इसका सबसे बड़ा सबूत है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) दृढ़तापूर्वक घोषणा करती है कि अपनी राष्ट्रीयता की आजादी के लिए तथा आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए कश्मीरी जनता द्वारा जारी आंदोलन पूरी तरह न्यायपूर्ण है और कश्मीर पर न तो भारत को न ही पाकिस्तान को कोई हक है।

आजादी-पसंद कश्मीरी लोगो,

अपनी आजादी के लिए तथा आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए भारतीय विस्तारवादी शासक वर्गों के खिलाफ जारी आपके संघर्ष का हमारी पार्टी समर्थन करती है और तहेदिल से भाईचारा प्रकट करती है। गोलीबारियों, लाठीचार्ज, कर्फ्यू, लगातार जारी तलाशी मुहिमों और अंतहीन अपमानों का मुकाबला करते हुए दृढ़ता के साथ जारी आपके संघर्ष का हमारी पार्टी भारत की समूची क्रांतिकारी, जनवादी व संघर्षरत जनता की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करती है। अंधाधुंध गोलीबारियां करते हुए दर्जनों की संख्या में युवक-युवतियों का कत्लेआम करने के बावजूद भी शहीदों के शवों को कंधों पर उठाकर जनाजों में हजारों की संख्या में भाग लेते

हुए 'आजादी' का नारा बुलंद करने का आपका जज़्बा और क़ुरबानी का जोश इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज रहेंगे। भारतीय विस्तारवादियों के भाड़े के सशस्त्र बलों की गोलीबारियों में अपनी जानें गंवाने वाले शहीदों के परिजनों, दोस्तों और समूचे कश्मीरी कौम के प्रति हमारी पार्टी गहरी संवेदना प्रकट करती है। आज जो भारतीय शासक वर्ग आपके संघर्ष पर विघटनकारी और देशद्रोहपूर्ण आंदोलन का ठप्पा लगाकर आपको अलग-थलग करने के नापाक मंसूबे से मनमानी हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, वे ही आज भारत की समूची शोषित जनता, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं और व्यापक जन समुदायों के घोर दुश्मन हैं। इसलिए, आइए, अपने सांझे दुश्मनों के खिलाफ हम सब एकजुट होकर लड़ें। इस लड़ाई को और तेज करें।

भारत के इंसाफ-पसंद लोगो,

कश्मीरी जनता के जायज संघर्ष के खिलाफ भारतीय लुटेरे शासक वर्ग, खासकर कांग्रेस व भगवा आतंकी गिरोह सुनियोजित तरीके से जो भड़काऊ दुष्प्रचार कर रहे हैं, उससे प्रभावित न होवें। हमारी पार्टी आप सभी से अपील करती है कि आप सच्चाई को समझते हुए न्याय के पक्ष में मजबूती से खड़े होवें।

इस मौके पर हमारी पार्टी की ठोस मांगें इस प्रकार हैं -

1) **कश्मीर में भारत के सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा जारी हत्याओं को फौरन रोको।**

2) **सैन्य बलों को जनता को मनमाने ढंग से मार डालने का अधिकार देने वाले फासीवादी कानून - 'सशस्त्र बलों का विशेष अधिकार कानून' (एफपीएसए) को फौरन रद्द करो।**

3) **कश्मीर से अर्ध सैनिक व सैनिक बलों को फौरन वापस लो।**

4) **कश्मीर में रायशुमारी (जनमत संग्रह) करवाकर कश्मीरी जनता को अपने भविष्य का फैसला खुद ही करने का अधिकार दो।**

5) **तमाम राजनीतिक बंदियों को फौरन रिहा करो।**

आप सभी से हमारा आह्वान है कि कश्मीरी जनता पर सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा जारी हत्याकाण्डों के खिलाफ तथा कश्मीरियों के जायज संघर्ष के प्रति भाईचारा प्रकट करते हुए आप 30 सितम्बर को 24 घण्टों का 'भारत बंद' सफल

बनाएं। इस 'भारत बंद' के दौरान छह राज्यों – बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र के गड़चिरोली, गोंदिया व चंद्रपुर जिलों तथा मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में रेलवे, सड़कें, बैंक, सरकारी व निजी कार्यालय, उद्योग-धंधे, शिक्षा व व्यापार संस्थानों को बंद रखने व उसमें उपस्थित न होने का हम जनता से आह्वान कर रहे हैं। हालांकि हम मेडिकल आदि अत्यावश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखेंगे।

आनंद
सचिव, मध्य रीजनल ब्यूरो
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

31 अक्टूबर 2010

विश्व जनता का नम्बर एक दुश्मन

अमेरिकी साम्राज्यवाद का सरगना

बराक ओबामा के भारत दौरे का जोर शोर से विरोध करो!

गांव-गांव और गली-गली में

"ओबामा! वापस जाओ!" का नारा बुलंद करो!

आगामी 6 नवम्बर को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आने वाला है। हमारे देश के दलाल शासक उसके स्वागत में लाल कालीन बिछाकर मुम्बई व दिल्ली महानगरों को सजाने-संवारने में लगे हुए हैं। यह देश के तमाम जनवाद-पसंद, अमन-पसंद और देशभक्त अवाम के लिए बड़ा अपमान है। दुनिया के पिछड़े देशों का बेरहमी से शोषण करने वाला, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं का दमन करने वाला, बदनाम तानाशाहों को सत्ता पर बिठाने वाला, सहयोग नहीं देने वाले देशों को आए दिन डराने-धमकाने वाला, विश्व के तेल, खनिज व अन्य तमाम सम्पदाओं और संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने के लिए किसी भी हद तक जाकर दरिंदगी का नंगा प्रदर्शन करने वाला अमेरिकी साम्राज्यवाद विश्व जनता का नम्बर एक दुश्मन है। इसका नेतृत्व करने वाला बराक ओबामा एक ऐसा व्यक्ति है जिसे समूची जनता को दुत्कारना चाहिए। चूंकि उसके पूर्वाधिकारी जार्ज बुश से दुनिया भर की जनता बेहद नफरत करने लगी थी, इसलिए अमेरिकी साम्राज्यवादी आकाओं ने सुनियोजित तरीके से बराक ओबामा को सामने लाया ताकि उसके शरीर के रंग से लोगों को धोखा दिया जा सके। बुश की नीतियों के विरोध में ओबामा ने चाहे जो भी कहा हो, व्हाइट हाउज में कदम रखने के बाद से अभी तक उसने जो भी नीतियां अपनाईं और जो भी फैसले लिए, वो सब बुश प्रशासन की धारावाहिकता के रूप में ही हैं। दरअसल जार्ज बुश और बराक ओबामा के बीच शरीर के रंग में तथा प्रतिनिधित्व वाली पार्टियों के नाम में ही फर्क है। दुनिया की जनता, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं, देशों और अमेरिकी मजदूर वर्ग को लूटने-खसोटने में तथा उनका दमन करने में उनके बीच कोई बुनियादी फर्क नहीं है। यह अकाट्य सच्चाई

है कि अमेरिकी साम्राज्यवादी व्यवस्था को अपने उंगलियों पर नचाने वाले एकाधिकारी कॉर्पोरेट संस्थाओं के बदनाम गोरे प्रभुओं ने ही इस काले रंग के राष्ट्रपति का चयन किया था।

आज अफगानिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान में अमेरिकी साम्राज्यवादी हर दिन बम बरसाकर तथा ड्रोन हमले कर मासूम नागरिकों के कत्लेआम कर रहे हैं। इराक में बर्बर कत्लेआमों का सिलसिला अभी भी जारी है। ओबामा ने अपने शासनकाल में अफगानिस्तान को 30 हजार अतिरिक्त अमेरिकी फौजियों को भिजवाकर अपने युद्धोन्मादी चरित्र का परिचय दिया। इस भूगोल को कम से कम दस बार तबाह कर सकने वाले विनाशकारी हथियारों के जखीरे पर खड़ा अमेरिकी साम्राज्यवाद अपने युद्ध उद्योग को, जोकि उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है, संकट में फंसने से बचाने के लिए युद्ध भड़का रहा है और खुद युद्ध कर रहा है। दूसरी तरफ वह परमाणु क्षमताओं को विकसित करने के नाम पर इरान व उत्तर कोरिया को निरंतर धमकियां दे रहा है। फिलहाल वह अल क़ायदा को शह देने के आरोप में येमेन पर निशाना साध रहा है। 9/11 के हमलों के बाद 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' के नाम से जार्ज बुश द्वारा शुरू किए गए फासीवादी हत्याकाण्ड व हिंसाकाण्ड को ओबामा बिना किसी व्यवधान के जारी रखते हुए अल क़ायदा, तालिबान और इस्लामिक आतंकवादियों का दमन करने के नाम से अंधाधुंध हमले कर रहा है। गाज़ा को धरती पर नरक में तब्दील करने वाले इज़्राएली यहूदी अंध राष्ट्रवादियों द्वारा जारी पाशविक हमलों और उसके बदनाम खुफिया संगठन मोसाद द्वारा जारी षड़यंत्रपूर्ण हत्याओं को रुकवाने की कोशिश न करके तथा उसका खण्डन न करके ओबामा सैकड़ों फिलिस्तीनियों की मौत का जिम्मेदार बन गया।

अमेरिकी खुफिया संस्था एफबीआई घिनौनी करतूतों को अंजाम देते हुए स्टिंग ऑपरेशन्स के जरिए मासूम अमेरिकी मुसलमानों को, खासकर पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नौजवानों को हमलों के लिए उकसाकर, आखिर में कोवर्ट ऑपरेशन्स में उन्हें सबूतों के साथ गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबियां हासिल करने का झूठा प्रचार कर रहा है। यह तरीका ओबामा के शासन में स्पष्ट रूप से सामने आया है जोकि बुश की विरासत ही है। इस तरह उसकी सरकार एक तरफ अमेरिकी जनता में असुरक्षा की भावना को लगातार बरकरार रखते हुए दूसरी तरफ जनता से जुटाए गए धन को भारी पैमाने पर अपने 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' में लगा रही है। इस तरह वह अमेरिका के अंदर मुस्लिम समुदाय को, कुल मिलाकर अमेरिकी

श्रमिक जनता को पीड़ा और हताशा के गहरे गड्ढे में धकेल रही है।

आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था ऐसे तीव्र आर्थिक संकट में फंसी हुई है जहां से उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। सब-प्राइम संकट के रूप में फूट पड़ने वाले इस संकट ने इतना तीव्र रूप धारण कर लिया है कि 1930 के दशक के बाद कभी नहीं देखा गया। 10 प्रतिशत से ऊपर चली गई बेरोजगारी की दर उसके इतिहास में ही अभूतपूर्व है। लेकिन ओबामा तो सैकडों अरब डॉलरों का जन-धन पहले से बेहद मोटाए हुए एकाधिकारी कार्पोरेट संस्थाओं की जेबों में पहुंचाकर अमेरिकी जनता को, खासकर श्रमिकों व मध्यम वर्ग को बेहिसाब तकलीफें पहुंचा रहा है। उसने जन कल्याणकारी योजनाओं में कई कटौतियां कीं। इसके बावजूद भी इस संकट के भंवर से बाहर आने में नाकाम अपनी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए वह पिछड़े व गरीब देशों से संसाधनों की लूट-खसोट में और ज्यादा तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। अब ओबामा के साथ-साथ कॉर्पोरेट घरानों के मोटाए हुए बड़े सेठ हमारे देश में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मुम्बई और दिल्ली महानगरों की खूबसूरती को देखकर खुश हुआ जा सके। बल्कि यहां पर और ज्यादा पूंजी का बहाव कर, इस देश का खून और ज्यादा क्रूरता से चूसने वाले कई और समझौते करने के लिए वो आ रहे हैं ताकि अपने संकट का बोझ भारत पर और ज्यादा लादने की योजनाओं को अंजाम दिया जा सके। हमारे देश के संसाधनों को मनमाने लूटने-खसोटने के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट के रूप में खड़े माओवादी आंदोलन समेत सभी जन आंदोलनों का और ज्यादा क्रूरता से दमन करने में सलाह-सुझाव देने के लिए वो यहां आ रहे हैं।

भारत के सामंती व बड़े पूंजीपति शासक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूपीए सरकार और उसका नेतृत्व करने वाले मनमोहनसिंह ने अपने शासन के पहले ही दौर में जनता की खिलाफत की जरा भी परवाह न करते हुए अमेरिका के साथ परमाणु करार कर अमेरिकी साम्राज्यवाद के नमकहलाल सेवक के रूप में घुटने टेक दिया था। अभी हाल में संसद द्वारा पारित 'परमाणु दायित्व विधेयक' इसी नीति की कड़ी है। हजारों लोगों की बेमौत तथा लाखों लोगों की जिंदगी में अंधेरा छाने के लिए जिम्मेदार भोपाल गैस रिसाव के हादसे का जख़्म और उसकी पीड़ा भारतवासियों के दिलोदिमाग में अभी भी ताजा है। इसके बावजूद ऐसे कई और 'भोपाल' पैदा करने के लिए तथा ऐसी घोर दुर्घटनाएं होने पर भी उसके लिए जिम्मेदार विदेशी पूंजीपतियों को जहां तक संभव हो कम से कम 'जुर्माना' भरकर

आसानी से बच सकने का मौका देते हुए (जैसे कि वारेन एण्डरसन और डाउ केमिकल्स को दिया गया था) यूपीए सरकार ने निर्लज्जता और निरंकुशता से इस विधेयक की रूपरेखा तैयार की थी। इस विधेयक को पारित करवाने में जहां भाजपा ने 'चोर-चोर मौसेरे भाई' की तरह सरकार की मदद की, वहीं अपने आपको कम्युनिस्ट बताने वाली चुनावी वामपंथी पार्टियों ने इस देशद्रोहपूर्ण विधेयक का मजबूती से विरोध न करके तथा इसके खिलाफ जन आंदोलन खड़ा न करके अपने दलाल चरित्र की फिर एक बार नुमाइश पेश की। ओबामा के भारत दौरे से पहले ही इस विधेयक को पारित करवाने के लिए मनमोहनसिंह ने कमर कसकर पूरा जोर लगाया था।

हाल के सालों में अंतरराष्ट्रीय पूंजीवादी मानचित्र पर नए खिलाड़ी के रूप में उभरने वाले चीन को घेरने वाली अमेरिकी भू-राजनैतिक रणनीति में भारत सरकार अमेरिका के मोहरे की तरह काम कर रही है। अमेरिका इस क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान दोनों को अपने इशारों पर नचवाते हुए दूसरी तरफ यह सुनिश्चित कर रहा है कि इन दोनों के बीच दुश्मनी बरकरार रहे। वह दोनों देशों को हथियार बेचते हुए, दोनों ही देशों के बाजारों को लूट रहा है। कुल मिलाकर इस पूरे क्षेत्र पर दबदबा कायम करते हुए वह अपनी वैश्विक आधिपत्यवादी रणनीति को लागू कर रहा है। इसके बावजूद भी कि अमेरिका हर दिन अफगानिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में बमबारी कर रहा है, भारत के शासक वर्ग इस पर जरा भी आपत्ति नहीं जताते हुए उसका समर्थन कर रहे हैं। इसके बदले में अमेरिका दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा लागू दखलंदाजी और लूट-खसोट की नीतियों का समर्थन कर रहा है। सांठगांठ की इस राजनीति का हिस्सा ही है ओबामा का यह दौरा और यहां के दलाल शासकों व विभिन्न विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा स्वागत।

संसदीय वामपंथी ओबामा के इस दौरे का साफ तौर पर विरोध करने की बजाए संसद में इस जंगखोर के भाषण को ध्यान से सुनने को बेताब हो रहे हैं। यह कहते हुए कि बुश और ओबामा में फर्क है, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो इस सच्चाई को छिपा रहे हैं कि इन दोनों के बीच फर्क इतना ही है जितना कि नागनाथ और सांपनाथ के बीच है। सहज ही, भाजपा अपने कट्टर दलाल चरित्र के अनुसार कांग्रेस के सुर में सुर मिलाकर ओबामा का स्वागत कर रही है।

प्यारे लोगो! जनवाद के प्रेमियो!! ओबामा का स्वागत करने का मतलब है

संप्रभुता, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वावलम्बन, शांति, न्याय, लोकतंत्र वगैरह मूल्यों के साथ गद्दारी। ओबामा के लिए लाल कालीन बिछाने का मतलब है उसकी युद्धोन्मादी, दुराक्रमणकारी, लूटखोर और आधिपत्यवादी नीतियों के सामने घुटने टेकना। इसलिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी तमाम जनता, क्रांतिकारी व जनवादी संगठनों तथा देशभक्तिपूर्ण ताकतों का आह्वान कर रही है कि वो ओबामा के आने के मौके पर विभिन्न स्वरूपों में अपना विरोध प्रकट करें तथा 'ओबामा! वापस जाओ' का नारा बुलंद करें। हम आह्वान कर रहे हैं कि वो इस मौके पर पर्चों, पोस्टरों व बैनरों से, सभा-सम्मेलनों का आयोजन कर ओबामा के दौरे का विरोध करें; अमेरिकी सम्राज्यवादियों के सामने घुटने टेककर देश की संप्रभुता का मजाक उड़ाने वाली यूपीए सरकार और उसके सुर में सुर मिलाने वाली अन्य दलाल संसदीय पार्टियों की दगाबाजी का कड़ा विरोध करें।

अभय

प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

27 नवम्बर 2010

क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लक्ष्य से नक्सल इलाकों के 'विकास' के नाम से लाई गई एकीकृत कार्य योजना जनता की बुनियादी समस्याओं का हल नहीं करेगी! हजारों करोड़ों रुपए के घोटालों से देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने-खसोटने वाले देशद्रोहियों को कड़ा सबक सिखाओ!!

नक्सल प्रभावित जिलों में 'विकास' के नाम पर केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा बनाई गई 13,742 करोड़ रुपए की 'एकीकृत कार्य योजना' का कल 26 नवम्बर को केन्द्रीय आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने अनुमोदन किया था। दो साल तक चलने वाले इस योजना के पहले चरण में 9 नक्सल प्रभावित राज्यों के 60 जिलों के लिए मौजूदा वर्ष 2010-11 के लिए 25 करोड़ रुपए और वर्ष 2011-12 में प्रत्येक जिले को 30 करोड़ के हिसाब से पैसा आवंटित करते हुए कुल 3,300 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा केन्द्रीय गृहमंत्री चिदम्बरम ने की। उन्होंने बताया कि कैबिनेट कमेटी ने दो सालों बाद इस योजना की समीक्षा करने का फैसला लिया। शासकों का कहना है कि इन गरीब व आदिवासी जिलों में जहां 50 फीसद से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं, बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कर 'विकास' करना उनका लक्ष्य है ताकि नक्सलवाद की 'समस्या' का हल किया जा सके। जिन 'बुनियादी सुविधाओं' की बात ये लोग कह रहे हैं उसमें सड़कें सबसे ऊपर हैं और उसके बाद पंचायत भवन, बिजली, स्कूल भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हैं। एक तरफ 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के नाम से पिछले एक साल में इन इलाकों में शासकों द्वारा दो लाख से ज्यादा विभिन्न अध सैनिक बलों को तैनात कर सैकड़ों आदिवासियों का नरसंहार करते हुए, दूसरी तरफ इन्हीं इलाकों में करोड़ों रुपए का बहाव क्या जनता के हितों में कर रहे हैं? या फिर जनता पर जारी दमनकारी कार्रवाइयों में और ज्यादा तेजी लाने के लिए? इसे समझना कोई बड़ी बात नहीं है। यह घोषणा करते हुए चिदम्बरम ने जोर देकर

कहा था कि आगामी मार्च माह तक आवंटित धन राशि को पूरा खर्च करके 'विकास' दिखाया जाएगा। इस योजना को लागू करने में पुलिस विभाग को भी शामिल करते हुए पुलिस अधीक्षकों को कमेटियों में भागीदार बनाने का फैसला अब तक लागू फासीवादी दमन की नीतियों पर 'विकास' का मुखौटा पहनाने की कोशिश भर है। सड़कों और भवनों का निर्माण क्या 'गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब जनता' के लिए किया जाएगा? या फिर उन सरकारी सशस्त्र बलों की सुविधा के लिए जो जनता के जीने के अधिकार को कुचलते हुए अंधाधुंध हत्याएं कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब इन इलाकों में कोई भी आदिवासी दे सकता है। एक सच्चाई यह है कि अब तक मौजूद विद्यालयों को सरकारी सशस्त्र बल अपने अड्डों में बदलकर यहां पर शिक्षा के प्रसार के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा खुद ही बन गए हैं। इस बात को छिपाकर करोड़ों रुपयों से शिक्षा की सुविधाएं बनाने का दावा करना धोखा ही है। उल्टी, दस्त जैसी छोटी-छोटी बीमारियों से हर साल सैकड़ों, हजारों की संख्या में बेमौत मर रहे आदिवासियों पर कभी नहीं ध्यान देने वाले शासकों के इस कथन को कि वो इस पैकेज से जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे, कोई भी विश्वास नहीं करेगा।

वास्तव में, खासतौर पर पिछले दो महीनों से ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन घोटालों की बात नहीं हुई हो। हजारों करोड़ों का जन धन किस तरह भ्रष्ट राजनेताओं, मंत्रियों, बड़े-बड़े अफसरों, कार्पोरेट मालिकों और नामी मीडिया सम्राटों की जेबों में जा रहा है, देश की जनता साफ तौर पर देख-समझ रही है। माओवादी आंदोलन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है कहकर बार-बार चिल्लाने वाले शासक और उनका ढोल बजाने वाले ढोंगी बुद्धिजीवी खुद कितने बड़े डाकैत हैं, इसे समझने के लिए इतिहास की गहराई में न जाकर कामनवेल्थ गेम्स घोटाला (करीब एक लाख करोड़ रुपए का), 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला (एक लाख छहत्तर करोड़ वाला), आदर्श हाउजिंग सोसाइटी घोटाला, कर्नाटका जमीन घोटाला वगैरह कुछ ताजा उदाहरणों पर नजर डालना काफी होगा। कांग्रेस, भाजपा, डीएमके, जनतादल वगैरह सभी शोषक वर्गों की पार्टियां बिना किसी अपवाद के इस अंधाधुंध लूटखसोट में भागीदार बन गईं। इन सभी घोटालों ने इस सड़ी-गली व्यवस्था को जनता की आंखों के सामने नंगा कर दिया है। व्यवस्थीकृत भ्रष्टाचार से ओतप्रोत इस शोषक व्यवस्था को ढहाने के अलावा कोई चारा नहीं है, इस माओवादी अवधारणा को देश की जनता की स्वीकृति

दिन-ब-दिन बढ़ रही है। दरअसल यही शोषक शासक वर्गों के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

भ्रष्टाचार की यह ताजातरीन तस्वीर जब लोगों की नजरों में इतनी साफ हो, इस आर्थिक पैकेज के तहत दिए जाने वाले करोड़ों रुपए किनकी जेबों में जाएंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वास्तव में यह घोषणा करते समय शासकों को डर लगना चाहिए था कि आज की परिस्थिति में ऐसे आर्थिक पैकेजों से जनता का विकास होने की बात करने से लोग हंस पड़ेंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेकसिंह अहलूवालिया, जिन्होंने इस एकीकृत कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की थी, और चिदम्बरम जिन्होंने इसे स्वीकृति दी, साम्राज्यवादी कार्पोरेट संस्थाओं की पूरी वफादारी से सेवा कर चुके हैं। इस शासक गिरोह की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह अपनी उम्र का आधा से ज्यादा हिस्सा साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाओं की सेवा में गुजार चुके हैं। ऐसे में यह समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि इनके द्वारा बनाई गई योजनाओं से किनके हित पूरे होने वाले हैं। सरकारें एक तरफ देश के आदिवासी इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों की अंध ाधुंध लूटखसोट का रास्ता साफ करते हुए कॉर्पोरेट कम्पनियों के साथ दसियों करोड़ों रुपए के एमओयू पर दस्तखत कर रही हैं जिससे आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। दूसरी ओर, उन समझौतों का जनता के सामने खुलासा करने और उन्हें रद्द करने की मांग, जो देश की जनता और जनवादियों की तरफ से उठाई जा रही है, को अनसुना करते हुए 'विकास' की रट लगाना हास्यास्पद है।

हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी इस जन विरोधी 'एकीकृत कार्य योजना' का कड़ा विरोध करती है। हमारी केन्द्रीय कमेटी मानती है कि यह केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से लागू फासीवादी दमन अभियान का ही हिस्सा है और उसमें सहायता करने वाली है। यह कहना कि इससे पिछड़े इलाकों का विकास होगा, बहुत बड़ा ढोंग है। अगर इन व्यापक वन इलाकों में आदिवासियों और शोषित जनता के विकास के प्रति जरा भी ईमानदारी है तो सरकारों को उन्हें जल-जंगल-जमीन पर अधिकार देना चाहिए; बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े पूंजीपतियों की कम्पनियों के साथ किए गए एमओयू को रद्द कर देना चाहिए; भारी बांधों, खदानों, अभयारण्यों, भारी-भरकम स्टील प्लांटों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के चलते लाखों लोगों को विस्थापित करने वाली सारी योजनाओं को वापस लेना चाहिए; आदिवासियों के नरसंहारों से चलाए

जा रहे ऑपरेशन ग्रीन हंट को फौरन बंद कर देना चाहिए।

हमारी केन्द्रीय कमेटी इस मौके पर मांग करती है कि कामनवेल्थ गेम्स, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श हाउजिंग सोसाइटी घोटाला, कर्नाटका जमीन घोटाला आदि में लिप्त राजनेताओं, मंत्रियों व कॉर्पोरेट घरानों के मालिकों को; और मलेगांव, अजमेर शरीफ, मक्का मस्जिद आदि बम विस्फोटों के लिए जिम्मेदार भगवा आतंकी नेताओं को फौरन गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

अभय

प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

4 दिसम्बर 2010

बाबरी मस्जिद का उसी जगह पर पुनरनिर्माण करो! हिंदू फासीवादी ताकतों को अलग-थलग कर हरा दो!! मालेगांव, मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ, समझौता एक्सप्रेस आदि बम विस्फोट की घटनाओं के लिए जिम्मेदार भगवा आतंकवादियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दो!

आज से 18 साल पहले, 1992 में, दिसम्बर 6 तारीख को संघ गिरोह के हिंदू साम्प्रदायिक फासीवादी गुण्डों ने केन्द्र में सत्तारूढ़ तत्कालीन कांग्रेस सरकार की प्रत्यक्ष/परोक्ष मदद से आयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। करीब 500 सालों से मुसलमानों की प्रार्थनास्थल के रूप में अस्तित्व में रही बाबरी मस्जिद को यह कहकर कि वह पहले राम की जन्म भूमि थी, विवाद खड़ा कर हिंदू साम्प्रदायिक फासीवादियों ने देश में कई दफे साम्प्रदायिक दंगे भड़काकर हजारों मुसलमानों की जानें लीं। हमारे देश में साम्प्रदायिक फासीवादियों का सबसे भयानक हमला था बाबरी मस्जिद का विध्वंस। इसमें प्रत्यक्ष रूप से शिरकत करने वाले एल.के. आडवाणी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, प्रवीण तोगड़िया, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा आदि को हमारे देश की अदालतों ने आज तक कोई सजा नहीं दी। विवादित जमीन के मालिकाने को लेकर 61 सालों से लंबित मामले की सुनवाई करते हुए 30 सितम्बर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने अपनी ब्राह्मणवादी हिंदूवादी विचारधारा के अनुरूप मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की। बिना किसी ऐतिहासिक आधार के और बिना किसी पुरातात्विक सबूत के ही उस स्थल को राम के जन्म-स्थल के रूप में व्याख्यायित किया। बाबरी मस्जिद को हड़पकर उसे तोड़ने और अब मस्जिद की जमीन पर कानूनी रूप से मंदिर बनाने का फैसला सुनाते हुए जमीन को मस्जिद तोड़ने वाली ताकतों को ही सौंप कर भारतीय राज्य ने अपने हिंदू फासीवादी चरित्र को फिर एक बार उजागर किया है। इस फैसले से यह बात फिर एक बार साबित हो गई कि देश की अदालतें लुटेरे वर्ग-अनुकूल और ब्राह्मणवादी हिंदूवादियों की हितैषी हैं तथा मजदूर-किसानों, दलितों, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ इंसाफ

नहीं करने वाली हैं। यह बात फिर एक बार स्पष्ट हो जाती है कि यह अदालतों के फैसलों से हल होने वाला नहीं है, बल्कि मौजूदा व्यवस्था को जड़ से बदलकर नई जनवादी राज्यव्यवस्था की स्थापना करने से ही इसका समाधान हो सकता है।

हाल ही में मालेगांव, अजमेर शरीफ, हैदराबाद मक्का मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस आदि बम विस्फोटों के मामलों में संघ गिरोह के भगवा आतंकी गुटों का हाथ होने के कई सबूत सामने आए हैं। 'अभिनव भारत' आदि छद्म नामों से वीएचपी, आरएसएस, बजरंगदल आदि संगठनों के नेताओं ने कई साजिशों और षड्यंत्रों के तहत बम विस्फोट करवाकर कई बेकसूर लोगों की जानें लीं। जहां भी बम विस्फोट होता है, यहां तक कि मस्जिदों में भी बम विस्फोट होता है, तब भी मुसलमानों को ही दोषी ठहराना हमारे देश में पुलिस और खुफिया संगठनों के लिए आम बात हो गई है। सैकड़ों मुसलमान नौजवानों को बिना वजह गिरफ्तार कर क्रूर यातनाएं देना, फर्जी मुठभेड़ों में मार डालना, झूठे मामलों में फंसाना, आईएसआई के साथ संबंध होने का आरोप लगाकर उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ करना सरकारों की साम्प्रदायिक फासीवादी नीतियों का हिस्सा है। मुसलमान होना ही आतंकवादी होने के बराबर दिखाते हुए मीडिया के जरिए प्रचार कर उनका हर प्रकार से दमन किया जा रहा है। मुम्बई हमलों में शामिल अजमल कसाब को फांसी की सजा देने की मांग करने वालों का संघ गिरोह के हिंदू साम्प्रदायिक हत्यारों के बारे में चुप्पी साध लेना या फिर जोर से आवाज नहीं उठाना एक खतरनाक संकेत है। सरकारें भगवा आतंकियों को गिरफ्तार न करके, कुछेक बार गिरफ्तार करने पर भी सतही छानबीन के बाद फिर से रिहा करते हुए निर्दोष करार दे रही हैं। दूसरी ओर इन हिंदू साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, मीडिया संगठनों, अखबारों और कलाकारों पर संघ गिरोह कई जगहों पर हमले कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की राज्यव्यवस्था में साम्प्रदायिक फासीवादी रुझान रोज-ब-रोज तीव्र रूप धारण करने लगे हैं।

हिंदू साम्प्रदायिक फासीवाद के खिलाफ सभी धर्मों से जुड़े तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों, जनवादियों और प्रगतिशील सोच वालों को संगठित होकर लड़ना चाहिए। हिंदू फासीवादी ताकतों के द्वारा मुसलमानों, ईसाइयों आदि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे हमलों का कड़ा विरोध करना चाहिए। साथ ही साथ, सभी किस्म के धार्मिक कट्टरवाद का विरोध करना चाहिए।

हमारी पार्टी शुरू से यह मांग करती आ रही है कि बाबरी मस्जिद जिस जगह पर थी वह मुसलमानों की है; उस पर मुसलमानों का ही मालिकाना होना चाहिए; बाबरी मस्जिद का फिर से उसी जगह पर निर्माण करना चाहिए; और उसे ढहाने वाले संघ गिरोह के फासीवादी नेताओं को कड़ी सजा देनी चाहिए। हमारी केन्द्रीय कमेटी तमाम जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील व क्रांतिकारी ताकतों, संगठनों और पार्टियों से आग्रह करती है कि वे इस मांग का समर्थन करें। हमारी केन्द्रीय कमेटी तमाम जनता का आह्वान करती है कि 6 दिसम्बर को हिंदू धर्मोन्माद के खिलाफ 'काला दिवस' मनाएं तथा इस मौके पर सभा, सम्मेलनों और जुलूसों का आयोजन करें और काली पट्टियां पहनें।

अभय

प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

24 दिसम्बर 2010

जनता की सेवा षड़यंत्र नहीं है!
जन पक्षधरता देशद्रोह नहीं हो सकता!
लाखों करोड़ों रुपए की जनता की गाढ़ी कमाई को डकारने वाले घोटालेबाज ही देशद्रोही हैं!
देश को साम्राज्यवादियों के हाथों बेचने वाले सौदेबाज ही षड़यंत्रकारी हैं!

मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर बिनायक सेन,

माओवादी नेता कॉमरेड नारायण सन्याल और
व्यापारी पियूष गुहा को देशद्रोह के मामले में आजीवन कारावास; तथा
पत्रिका संपादक असित सेनगुप्ता को
आठ साल के कारावास की सजा सुनाते हुए

छत्तीसगढ़ की फासीवादी अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों के खिलाफ

2 से 8 जनवरी 2011 में विरोध सप्ताह मनाएं!

24 दिसम्बर को रायपुर जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर बिनायक सेन, हमारी पार्टी के पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड नारायण सन्याल और व्यापारी पियूष गुहा को फर्जी मामलों में फंसाकर आई.पी.सी., छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून और गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यू.ए.पी.ए.) के तहत आजीवन कारावास की सजा देते हुए फैसला सुनाया। आई.पी.सी. की धारा 124 (देशद्रोह) और 120-ख (षड़यंत्र) के तहत आजीवन कारावास और छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून व यू.ए.पी.ए. की कई धाराओं के तहत विभिन्न सजाएं निर्धारित करते हुए बी.पी. वर्मा द्वारा सुनाया गया यह फैसला देश के शासक वर्गों की जन विरोधी व फासीवादी नीतियों का घिनौना उदाहरण है।

हमारी पार्टी के पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड नारायण सन्याल के साथ-साथ

पी.यू.सी.एल. के उपाध्यक्ष बिनायक सेन, जो पिछले 30 सालों से जनता की सेवा में निस्वार्थ रूप से समर्पित डॉक्टर तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में सुविख्यात हैं, और कोलकाता के एक व्यापारी पियूष गुहा को आजीवन कारावास की सजा देना देश के शासकों की बेशर्मी भरी करतूत है, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते नहीं थकते हैं। यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि डॉक्टर बिनायक सेन को यह सजा सिर्फ इसलिए दी गई हैं क्योंकि वो सरकार की दमनकारी नीतियों और फासीवादी सलवा जुडूम का शुरू से विरोध करते रहे; काला कानून छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा कानून (सी.एस.पी.एस.ए.) के खिलाफ आवाज उठाते रहे; और जायज जन आंदोलन के समर्थन में खड़े रहे। मई 2007 में जब उन्हें गिरफ्तार कर दो सालों तक जेल में रखा गया था, तब देश भर में तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनवादी तबकों, चिकत्सा जगत् तथा नोबेल लारिएटों की तरफ से बड़े पैमाने पर प्रकट हुए विरोध को भी दरकिनार करते हुए दी गई ये सजाएं देश के फासीवादी शासक गिरोह द्वारा जनवादी, प्रगतिशील और देशभक्तिपूर्ण तबकों को दी जा रही निर्लज्ज और उन्मत्त धमकी है। जन समस्याओं को कानूनी और जनवादी तरीके से उठाना, ईमानदारी से जनता की सेवा करना और सरकारों की जन-विरोधी नीतियों की आलोचना करना - अगर यही देशद्रोह है तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस देश में लागू 'लोकतंत्र' किस ढंग का है और उससे जनता को कितना खतरा है। दुनिया भर में कई भाषाओं में प्रकाशित होने वाली क्रांतिकारी प्रत्रिका - 'ए वर्ल्ड टु विन' का हिंदी संस्करण संभालने वाले असित सेनगुप्ता, जो अवैध गिरफ्तारी के बाद पिछले तीन सालों से जेल में हैं, को भी इसी दिन एक और फैसले में जिला अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायमूर्ति ओ.पी. गुप्ता ने आठ साल की सजा सुनाई, जोकि प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। हाल ही में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रमनसिंह, डी.जी.पी. विश्वरंजन, बस्तर आई.जी. लांगकुमेर और दंतेवाड़ा एस.पी. कल्लूरी के गिरोह ने 'मां दंतेश्वरी आदिवासी स्वाभिमानी मंच' के नाम से पर्चे छापकर जनवादी बुद्धिजीवी हिमांशु कुमार व अरुंधति रॉय के साथ-साथ पत्रकार एन.आर.के. पिल्लै, अनिल शर्मा और यश्वंत राव की हत्या करने की खुलेआम धमकी दी जो उनकी फासीवादी नीतियों का हिस्सा है।

हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता व 73 साल के उम्रदराज कॉमरेड नारायण सन्याल को छत्तीसगढ़ की दमनकारी रमन सरकार ने पिछले पांच सालों से जेल की

कालकोठरी में बंद कर कई झूठे मुकदमों में फंसाकर रखा है। वो 1968 से शुरू कर पिछले चार दशकों से ज्यादा समय से देश की दबी-कुचली जनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट नेता हैं। उन्हें जेल के भीतर गंभीर बीमारियों के साथ-साथ कई प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। आतंकी सोनिया-मनमोहन सिंह-चिदम्बरम-रमन सिंह गिरोह जहां एक तरफ क्रांतिकारी नेताओं को षड़यंत्रकारी तरीके से उठा ले जाकर फर्जी मुठभेड़ों में हत्या कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फर्जी मामलों में फंसाकर काले कानूनों के तहत कठोर सजाएं दिलवा रहा है।

छत्तीसगढ़ के विधायकों को माओवादी प्रचार की सीडी भेजने के मामले में विगत 29 जुलाई को सुनाए गए एक फैसले में हमारी पार्टी कार्यकर्ता कॉमरेड मालती उर्फ शांतिप्रिया व मजदूर सुरेंद्र कोसरिया को छत्तीसगढ़ सरकार ने झूठी गवाहियों के आधार पर दस साल की सजा दिलवाई। झारखण्ड के रांची जेल में बंद हमारी पार्टी के एक और पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड अमिताभ बागची और बंगाल राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड कार्तिक को भी एक फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए सरकार ने उम्र कैद की सजा सुनवाई। आंध्रप्रदेश सरकार ने 29 अक्टूबर को अलिपिरी मामले (आंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू पर किए गए हमले के मामले) में झूठी गवाही दिलवाकर कॉमरेड पाण्डूरंगा रेड्डी उर्फ सागर समेत चार लोगों को सात साल की सजा दिलवाई। और भी कई जगहों पर अनगिनत क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं और आम जनता को इन शोषक वर्गीय अदालतों ने फांसी से लेकर विभिन्न किस्म की सजाएं सुनाईं। वरिष्ठ व उम्रदराज नेता तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कॉमरेड्स सुशील रॉय व कोबड गांधी के साथ-साथ शोभा, पतितपावन हलदार, प्रमोद मिश्र, विजय, आशुतोष, बलराज, चिंतन, बिमान, बिधान, चंडी सरकार, बालगणेश आदि हजारों कॉमरेडों व लोगों को, सांस्कृतिक संगठन 'झारखण्ड अभेन' के नेता जीतन मराण्डी आदि जन नेताओं को लम्बे समय से जेलों में बंदकर, उनकी जमानत की अर्जियों को नामंजूर करते हुए, उन पर एक के बाद एक फर्जी मामला दर्ज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता की जेल में कॉमरेड स्वपनदास को जेल प्रशासन ने चिकित्सा सुविधाओं से वंचित कर कत्ल कर दिया जोकि यू.ए.पी.ए. के तहत पहली हत्या थी।

हमारे देश की प्राकृतिक संपदाओं तथा श्रमशक्ति को वेदांता जैसी साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा टाटा, एस्सार, जिंदल, मित्तल जैसे दलाल पूंजीपतियों के

हाथों लुटवाने की ठान लेकर यू.पी.ए. सरकार ने इस मनमानी लूट की राह में बाधा के रूप में खड़े माओवादी आंदोलन को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित किया। इसके तहत ही वह अपने प्रचार साधनों के जरिए जहरीली दुष्प्रचार-मुहिम चला रही है। अगस्त 2009 से ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ बर्बर हमला चलाया जा रहा है जिसके तहत हजारों पुलिस व अर्धसैनिक बलों को उतारकर, खासकर आदिवासियों का कत्लेआम किया जा रहा है। यह हमला साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के मार्गदर्शन में तथा संपूर्ण समर्थन से चल रहा है। हमारे देश को साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और सामंतवाद के शिकंजे से आजाद कर मजदूर-किसान एकता के आधार पर जनवादी वर्गों की जन सत्ता स्थापित करने के महान लक्ष्य से संघर्षरत हमारी पार्टी को आतंकवादी और देशद्रोही के रूप में चित्रित करने के लिए लुटरे शासक नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। नित नए घोटालों में खुद भागीदार बनकर, जनता के खून-पसीने को चूसकर, लाखों करोड़ों रुपए का जनधन स्विस बैंकों में छिपाने वाले मंत्रियों, राजनेताओं, बड़े पूंजीपतियों और उनके दलालों पर, जो बेखौफ घूमते हैं, देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाता? भोपाल त्रासदी के जिम्मेदारों और दोषियों को बचाने वालों पर षड़यंत्र का मामला क्यों नहीं चलाया जाता? दबी-कुचली जनता की मुक्ति की खातिर संघर्ष करना देशद्रोह कैसे बनता है? जन आंदोलनों के प्रति भाईचारा प्रकट करते हुए अपनी आवाज व कलम उठाने वाले षड़यंत्रकारी कैसे हो सकते हैं?

ये फैसले शासकों की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिससे कि वे अपनी जन-विरोधी, देशद्रोहपूर्ण व अनैतिक नव-उदार आर्थिक नीतियों को बेरोकटोक जारी रख सकें। यह इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में देश में फासीवाद और ज्यादा घातक रूप धारण करने वाला है। जो लोग नादानगी से यह विश्वास रखते हैं या इस धोखे में रहते हैं कि इस देश में जो चल रहा है वह लोकतंत्र है, उनकी इन फैसलों से आंखें खुलनी चाहिए। ऊपरी तौर पर देश का शासक गिरोह माओवादी आंदोलन को अपने हमले का निशाना भले ही घोषित कर रहा हो, दरअसल इस फासीवादी हमले के निशाने पर तमाम प्रगतिशील व जनवादी शक्तियां हैं जो देश के हितों तथा जन की भलाई के प्रति समर्पित हैं। अतः हमारी पार्टी तमाम जनता से यह अपील करती है कि इस हमले के खिलाफ एकजुटता

से खड़े होकर, दृढ़तापूर्वक लड़कर हरा दिया जाए।

अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा लागू काला कानून होमलैण्ड सेक्यूरिटी की तर्ज पर ही देश की कॉर्पोरेट-दलाल सरकारें गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यू.ए.पी.ए.), छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून (सी.एस.पी.एस.ए.), मकोका, सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (ए.एफ.एस.पी.ए.) आदि काले कानूनों के तहत जन आंदोलनों और राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों को कुचलने की कोशिश कर रही हैं। मक्का मसजिद, मालेगांव, अज़्मेर शरीफ आदि बम विस्फोटों में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जानें लेने वाले भगवा आतंकवादियों को तथा एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कामनवेल्थ घोटाला, आदर्श हाउसिंग घोटाला, कर्नाटका जमीन घोटाला आदि अनगिनत मामलों में लिप्त घोटालेबाजों और राजनीतिक दगाबाजों को आज तक किसी भी अदालत ने कोई सजा नहीं सुनाई। यही आदलतें क्रांतिकारियों, जन आंदोलन के नेताओं, जनवादियों, कश्मीर व पूर्वोत्तर क्षेत्र के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों से जुड़े कार्यकर्ताओं को उपरोक्त काले कानूनों के तहत सजाएं सुना रही हैं।

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार और केन्द्र की यूपीए सरकार ने सांठगांठ के साथ अपनी प्रतिक्रियावादी न्यायव्यवस्था के जरिए षड़यंत्रकारी तरीके से जो सजाएं सुनाई हैं, इसकी कड़ाई से निंदा करने तथा सड़कों पर उतरकर आंदोलन चलाने का आह्वान हमारी केन्द्रीय कमेटी तमाम जनवाद-पसंद व देशभक्तिपूर्ण ताकतों, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनकारियों, मानवाधिकार संगठनों व कार्यकर्ताओं, छात्रों, बुद्धिजीवियों, अध्यापकों, लेखकों, कलाकारों, चिकित्सकों, वकीलों, मीडियाकर्मियों, मजदूरों और किसानों से करती है। हम अपील करते हैं कि यू.ए.पी.ए., सी.एस.पी.एस.ए., मकोका और ए.एफ.एस.पी.ए. को फौरन रद्द करने की मांग करते हुए एकजुटता से आंदोलन छेड़ दें। हमारी केन्द्रीय कमेटी विभिन्न देशों के प्रगतिशील, जनवादी व क्रांतिकारी संगठनों, समुदायों और शख़्सों से अपील करती है कि वे भारतीय शासक वर्गों की इस वाहियात कार्रवाई का कड़ाई से खण्डन करें और भारत सरकार के प्रति अपना विरोध विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के जरिए व्यक्त करें। जिस तरह विगत में डॉक्टर बिनायक सेन की अवैध हिरासत की निंदा करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भारत के जन आंदोलनों के समर्थन में खड़ा हुआ था, अब वक्त आ गया है कि उसी प्रकार वह फिर एक बार और ज्यादा दृढ़ता से इस भूमिका को निभाए। हमारी पार्टी का आह्वान है कि इन सजाओं के खिलाफ 2 से 8 जनवरी 2011 में देशव्यापी विरोध-सप्ताह मनाया

जाए जिसके अंतर्गत पत्रकार-वार्ता, बयानों, विरोध प्रदर्शनों, धरना, रास्ता रोको, सभा-सम्मेलनों, हस्ताक्षर अभियान, काली पट्टियां बांधकर और पुतला-दहन आदि कार्यक्रमों को रचनात्मकता से अपनाया जाए; न्याय के लिए संघर्ष छेड़ दें; तथा शासकों के जन-विरोधी व फासीवादी नीतियों का जोर शोर से विरोध करें।

इस मौके पर हमारी केन्द्रीय कमेटी अपनी पार्टी के तमाम कतारों, पीएलजीए बलों तथा क्रांतिकारी जन संगठनों का आह्वान करती है कि वे जनता को बड़े पैमाने पर गोलबंद करके विभिन्न रूपों में विरोध-कार्यक्रम आयोजित करें।

हमारी केन्द्रीय कमेटी यह भी स्पष्ट करती है कि इस विरोध-सप्ताह के दौरान 'बंद' का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि तमाम जनवादी तरीकों में जनता के विरोध-कार्यक्रम होंगे। हम जनता और मीडिया से आग्रहपूर्वक अपील करते हैं कि इसे 'बंद' के रूप में चित्रित करते हुए सरकार व पुलिस द्वारा चलाए जाने वाले प्रचार पर विश्वास न करें।

अभय

प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

15 जनवरी 2011

महंगाई, घोटालों और सरकारी आतंक के खिलाफ...

4 से 6 फरवरी तक देशव्यापी विरोध दिवस तथा 7 फरवरी को 'भारत बंद' सफल बनाओ!

महंगाई आसमान को छू रही है। प्याज, मिर्च, सब्जियां, आटा, दाल आदि खाने-पीने की सभी चीजों के दामों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी जारी है। खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति की दर 18.5 प्रतिशत से ऊपर हो गई। प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो से ज्यादा हो गई जिससे गरीब व मध्यम तबकों के लोग बुरी तरह परेशान हैं। फिर आज, 15 जनवरी की आधी रात से पेट्रोल का दाम ढाई रुपए बढ़ाकर देशवासियों पर जो गाज गिराई गई, इससे तो महंगाई और ज्यादा खतरनाक रूप ध ारण करने वाली है। बात-बात पर 'आम आदमी' की दुहाई देने वाली यूपीए सरकार आज उसी आम आदमी का जीना हराम कर रही है।

हर तरफ हो रही आलोचनाओं और जनता में बढ़ते रोष से बचने के लिए यूपीए सरकार बेसिरपैर की और अजीबोगरीब बयानबाजी कर रही है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने यह बयान देकर सबको चौंका दिया है कि देश में महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि गरीब लोग आजकल ज्यादा खाने लगे हैं। साम्राज्यवादियों के इस पसंदीदा अर्थशास्त्री-प्रधानमंत्री, जिसने अपनी आधी से ज्यादा उम्र आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी आदि की चरण-सेवा में बिताई थी, के मुंह से बुश के लफ्ज़ निकले हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? जिस प्रधानमंत्री के शासनकाल में एक अम्बानी 3,500 करोड़ रुपए का गगनचुंभी महल खड़ा करता है और एक मंत्री पंचसितारा होटल में रहकर काम करता है, उसके शासन में गरीबों का 'ज्यादा खाना' अपराध हो गया! दरअसल वायदा कारोबार (future trading), जमाखोरी, कालाबाजारी, लुंज-पुंज सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आदि महंगाई की बुनियादी वजहों को हल करने में अपनी विफलता को छुपाते हुए वह गरीबों को ज्यादा खाने का दोषी ठहरा रहा है। खुद सरकार द्वारा गठित कई कमेटियों का निष्कर्ष यह है कि देश में गरीबी बढ़ी है; कि प्रतिव्यक्ति खाद्य उपलब्धता पहले से कम हुई है; और कि देश के 83 करोड़ लोग 20 रुपए से भी कम आमदनी पर जीने को मजबूर हैं। सच यह भी है कि हमारे देश की श्रमशक्ति

का 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में काम करता है, लेकिन बढ़ती महंगाई के मुताबिक उनकी मजदूरी बढ़ाने की कोई व्यवस्था यहां नहीं है। ऐसे में, जबकि देश की अत्यधिक आबादी के लिए एक जून की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है, वहीं इन घोटालेबाज नेताओं का यह कहना कि 'गरीब ज्यादा खाने लगे हैं', न सिर्फ देश की गरीबी का भद्दा मजाक है, बल्कि अपनी नाकामियों और काली करतूतों पर परदा डालने की कोशिश भी।

एक तरफ कमरतोड़ महंगाई से जनता त्रस्त है तो दूसरी तरफ हजारों करोड़ों रुपए के जो नित नए घोटाले उजागर हो रहे हैं, वो जनता के घावों पर नमक छिड़क रहे हैं। हाल में देश के सबसे बड़े 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर, जिसमें सरकार को एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का चूना लगा था, गंदा राजनीतिक खेल जारी है। जहां इस घोटाले ने कॉर्पोरेट जगत् के बड़े खिलाड़ियों, मंत्रियों और मीडिया के दिग्गजों की सांठगांठ को नंगा कर दिया, वहीं लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे घोटालों ने सभी संसदीय राजनीतिक दलों को बेनकाब कर दिया। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की संयुक्त संसदीय कमेटी द्वारा जांच कराने की मांग कर संसद के एक पूरे सत्र को ठप्प करके भाजपा ने खुद को घोटालों से पाक साफ दिखाने की विफल कोशिश की। लेकिन कर्नाटका में येदियूरप्पा के घोटाले, खदान माफिया रेड्डी बंधुओं के साथ सुष्मा स्वराज समेत कई भाजपाई नेताओं के सम्बन्ध आदि किसी से छिपे नहीं हैं। मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद आदि बम विस्फोटों के तार भगवा आतंकियों से जुड़े होने के जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे जनता का ध्यान बंटाने के लिए ही भाजपा अब 2जी स्पेक्ट्रम और महंगाई पर हाय तौबा मचा रही है। और उधर कांग्रेस सारा दोष सिर्फ ए. राजा के सिर मढ़कर उसे मंत्री पद से हटाकर यह दिखलाने की कोशिश कर रही है कि मनमोहन और सोनिया घोटालों से पाक साफ हैं। जबकि सच यह है कि इन दोनों की भागीदारी के बिना इतना भारी घोटाला हो ही नहीं सकता था। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के भी बड़े-बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की जनता की गाढ़ी कमाई किन-किन लोगों की जेबों में जा रही है। कई राज्यों में आज जिस प्रकार बड़ी व विदेशी पूंजीपति कम्पनियों के साथ ध ड़ल्ले से एमओयू किए जा रहे हैं, उसमें सैकड़ों-हजारों करोड़ रुपयों की घपलेबाजी आम हो गई है। खासकर नवीन पट्नायक, रमनसिंह, वाईएस राजशेखर रेड्डी (अब मृत), येदियूरप्पा, नितीश कुमार, बुद्धदेब, नरेंद्र मोदी, विलासराव देशमुख, अशोक चवान आदि वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कॉर्पोरेट मालिकों

से भारी-भरकम दलाली कमा ली है।

लुटेरे नेता-मंत्री-अफसरों के तमाम भ्रष्टाचार-घोटालों तथा सरकारों की तमाम जन-विरोधी नीतियों व महंगाई के खिलाफ जनता हर जगह अलग-अलग रूप में तथा विभिन्न स्तर पर संघर्ष कर रही है। पर सबसे संगठित और जुझारू संघर्ष हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में हो रहा है। इसीलिए देश के शासक गिरोह सोनिया-मनमोहन- चिदम्बरम ने माओवादी आंदोलन को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताकर ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से एक देशव्यापी चौतरफा हमला छेड़ दिया। ज्यों-ज्यों वर्तमान शासक गिरोह बड़े-बड़े घोटाले कर महंगाई को बढ़ाने वाली जन-विरोधी नीतियों में तेजी ला रहा है, वह संघर्षरत जनता और उसकी अगुवाई करने वाली भाकपा (माओवादी) पर हमला भी तेज करने लगा है जो पिछले दो महीनों से खास तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृहमंत्री चिदम्बरम इस आशय के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में छह राज्यों के पुलिस अधिकारियों और अध ैसैनिक बलों के आला अफसरों के साथ की गई बैठक में चिदम्बरम ने खुफिया एजेंसियों और बलों के बीच तालमेल ज्यादा बढ़ाने पर जोर दिया। इस तरह हजारों करोड़ों के जन-धन को जन दमन पर खर्च करने का निर्णय लिया।

पश्चिम बंगाल में सामाजिक फासीवादी सीपीएम आने वाले चुनावों को नजर में रखते हुए अपने गुण्डा गिरोह हर्मद बाहिनी और पुलिस-अर्धसैनिक बलों के साथ जंगलमहल व लालगढ़ इलाकों में 140 से ज्यादा कैम्प खोलकर आतंक का तांडव मचा रही है। वो जनता पर रोज हमले कर रहे हैं। जन नेताओं को कत्ल कर रहे हैं। महिलाओं पर बलात्कार की घटनाएं लगातार जारी हैं। 3 दिसम्बर 2010 को पुलिस ने हमारी पार्टी की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड सुदीप चोंगदार, राज्य कमेटी सदस्य कल्पना मैती, बरुन सुर, अनिल घोष समेत कुछ अन्य कॉमरेडों को तथा इसके पूर्व एक और राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड द्विजन हेमब्रम उर्फ अनंतो को गिरफ्तार किया। उन्हें क्रूर यातनाएं देकर झूठे मामले दर्ज कर जेल भेज दिया। खासकर महिला कॉमरेड कल्पना के साथ अमानवीय व अपमानजनक बरताव किया जा रहा है।

बिहार और झारखण्ड में माओवादी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों, यातनाओं, गांवों पर वहशी हमलों और हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। आंध्रप्रदेश में सरकार एक तरफ माओवादी आंदोलन को कुचल डालने के दावे करते हुए ही

फर्जी मुठभेड़ों और जनता पर हमलों का सिलसिला जारी रखी हुई है। 17 दिसम्बर 2010 को विशाखापटनम जिले में किए गए एक हमले में ग्रेहाउण्ड्स ने तीन महिलाओं समेत चार कॉमरेडों की हत्या की। सेज व थर्मल बिजली परियोजनाओं के खिलाफ तथा पृथक तेलंगाना के लिए आंदोलनरत आम लोगों पर सरकारी जुल्म जोरों पर जारी है।

ओड़िशा में पिछले दो महीनों में सरकारी सशस्त्र बलों ने अंधाधुंध हमले कर करीब 25 माओवादी कार्यकर्ताओं तथा आम जनता की हत्या कर दी। वहां से अभी तक जितनी भी 'मुठभेड़' की खबरें आईं, अधिकांश झूठी हैं। 2 जनवरी को कलिंगनगर क्षेत्र में पांच, 9 जनवरी को नियमगिरी इलाके में नौ और 12 जनवरी को क्योंझर जिले में दो माओवादियों के कथित मुठभेड़ों में मारे जाने की घटनाएं सरकारी आतंक के कुछ ताजा उदाहरण हैं। इस साल की शुरूआत में बरगढ़ जिले के दो ग्रामीणों की सरेआम हत्या कर उसे 'मुठभेड़' के रूप में चित्रित किया गया।

दण्डकारण्य के बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की हत्याओं का सिलसिला अभी भी जारी है। 8 अक्टूबर 2010 को महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिले के सांवरगांव के स्कूल पर आईटीबीपी के दरिंदों ने मोर्टार के गोले दागे थे जिसमें दो स्कूली बच्चों समेत छह ग्रामीणों की मौत हुई जबकि 8 अन्य बुरी तरह घायल हुए। अगले ही दिन 9 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में किए गए एक और हमले में पीएलजीए के छह साथी शहीद हुए थे और पुलिस ने वहां दो निर्दोष ग्रामीणों की ठण्डे दिमाग से हत्या की। 23 नवम्बर को दंतेवाड़ा जिले के जेगुरगोण्डा के पास सीआरपीएफ ने 9 ग्रामीणों की हत्या की। सरकारी हिंसा का विरोध करने पर जनवादी बुद्धिजीवियों को भी धमकियां देना, गिरफ्तार कर जेल भेजना और मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. बिनायक सेन, भाकपा (माओवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉ. नारायण सन्याल, व्यापारी पियूष गुहा, पत्रिका सम्पादक असित सेनगुप्ता को सजाएं देना छत्तीसगढ़ सरकार के बढ़ते फासीवादी रुझानों के उदाहरण भर हैं। हालांकि आज यह हमला ऊपर से देखने पर माओवादियों पर केन्द्रित नजर आ रहा है, लेकिन वास्तव में यह हमला सरकारों की नीतियों का विरोध करने वाले हर शख़्स और हर संगठन पर है।

प्यारे देशवासियो! यह वक्त यह सब देखकर हताश या निराश होने का नहीं है, बल्कि एकजुटता के साथ सरकारों की दमनकारी, जन-विरोधी और साम्राज्यवाद-परस्त नीतियों के खिलाफ लड़ने का है तथा घोटालेबाजों, जमाखोरों

और कालाबाजारियों के खिलाफ अपने संघषों को केन्द्रित करना का है।

हमारी केन्द्रीय कमेटी देश की समूची जनता से आह्वान करती है कि बढ़ती महंगाई, घोटालों और सरकारी आतंक के खिलाफ आगामी 4 से 6 फरवरी तक तीन दिनी देशव्यापी विरोध कार्यक्रमों और 7 फरवरी को 24-घण्टे का 'भारत बंद' को सफल बनाया जाए। हम इस मौके पर यह भी स्पष्ट करते हैं कि विरोध कार्यक्रमों के दौरान बंद नहीं रहेगा तथा 'भारत बंद' का पालन छह राज्यों - पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, बिहार, ओड़िशा, छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश में तथा महराष्ट्र के तीन जिलों - गड़चिरोली, गोंदिया व चंद्रपुर और मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में किया जाएगा। हालांकि हम मेडिकल सुविधाओं, छात्रों की परीक्षा, साक्षात्कार आदि को बंद से मुक्त रखेंगे।

अभय

प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

31 मार्च 2011

लीबिया पर अमेरिका-फ्रांस-ब्रिटेन के दुराक्रमणकारी युद्ध का विरोध करो!

लोकतंत्र और आजादी के लिए लड़ रही टुनीशिया, मिस्र, येमेन, बहरीन, अलजीरिया, मोरक्को, जोर्डान आदि देशों की जनता का समर्थन करो!

अरब देशों के अंदरूनी मामलों में साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी, ब्रितानी और फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों की दखलंदाजी का विरोध करो!

पिछले कुछ हफ्तों से अरब दुनिया में जो जन उभार देखने को मिल रहा है, इसने जहां एक तरफ साम्राज्यवाद को, खासकर अमेरिका को हिलाकर रख दिया, वहीं दूसरी तरफ विश्व जनता को बेहद प्रभावित किया है। टुनीशिया से शुरू होकर कई अन्य अरब देशों में फैली इस जन त्सुनामी से डरकर टुनीशिया के राष्ट्रपति बेन अली, जो पिछले 23 सालों से जनता का दमन-शोषण कर रहा था तथा पिछले 30 सालों से मिस्र में राज करते आ रहे होस्नी मुबारक गद्दी छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। और येमेन, बहरीन, अलजीरिया, मोरक्को, जोर्डान आदि देशों में भी जन आंदोलन इसी तर्ज पर चल रहे हैं। अरब जनता चिल्ला-चिल्लाकर कह रही है कि साम्राज्यवादियों से सांठगांठ कर दशकों से जनता पर तानाशाही चलाने वाले तमाम शासक गद्दी छोड़ दें। लाखों अरब जनता, खासकर युवा वर्ग तमाम प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए सड़कों पर आ रहा है। कई हफ्तों तक सड़कें और चौराहें जन समंदर में तब्दील हो गईं। जनता के प्रदर्शनों पर सरकारों द्वारा किए गए हमलों में सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें कुरबान कर दीं। हजारों लोग घायल हो गए। अब जबकि लीबिया पर अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देशों ने दुराक्रमणकारी युद्ध छेड़ दिया, तो अरब दुनिया में घटनाक्रम ने एक अहम मोड़ ले लिया।

लीबिया में गद्दाफ़ी की हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए विद्रोह को दबाने के लिए लीबिया सरकार को अपने सैन्य बलों का प्रयोग करने से रोकने के नाम पर सुरक्षा परिषद ने 'उड़ान-वर्जित क्षेत्र' (नो-फ्लाई ज़ोन) का प्रस्ताव किया।

सुरक्षा परिषद में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला, जबकि रूस, चीन, जर्मनी, ब्राजील और भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया। वीटो अधिकार प्राप्त रूस और चीन ने इस प्रस्ताव को रोकने की कोशिश नहीं की। प्रस्ताव का विरोध न करने वाले इन देशों ने स्पष्ट तौर पर लीबिया पर नाटो की सैन्य कार्रवाई का परोक्ष समर्थन किया। इस हमले का खण्डन न करते हुए सिर्फ चिंता जाहिर कर मनमोहनसिंह सरकार देश और दुनिया की जनता को धोखा देने की कोशिश कर रही है। इज़्राएल के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए दर्जनों प्रस्तावों को रद्दी के टोकरे में डालकर जब यहूदीवादी शासकों ने अनगिनत मौकों पर फिलिस्तीनियों की अंधाधुंध हत्याएं कीं, तब उस पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों ने जरा भी आपत्ति नहीं की थी। (बल्कि अमेरिका ने तो इज़्राएल के लिए अपने वीटो अधिकार का अंधाधुंध इस्तेमाल किया।) लेकिन लीबिया के मामले में तो इन देशों ने प्रस्ताव पर श्याही सूखी ही नहीं थी कि आनन-फानन में उस पर अमल करते हुए बमों की बारिश शुरू कर दी। कथित रूप से अंतरराष्ट्रीय अभियान बताए जाने वाले इस दुराक्रमणकारी हमले के पहले ही दिन फ्रांस के 18 बमवर्षक विमानों ने कई लक्ष्यों पर 40 बम गिराए। अमेरिकी और ब्रितानी नौसेनाओं ने लीबिया की सुरक्षा व्यवस्था को लक्ष्य बनाकर कई क्रूइज़ मिस्साइलों का प्रयोग किया। अमेरिकी वायुसेना के 18 बी-2 विमानों ने 100 से ज्यादा मिस्साइलों का प्रयोग किया। कई लक्ष्यों पर बम गिराए। गद्दाफ़ी की सेनाओं द्वारा संभावित कत्लेआम को रोकने के बहाने शुरू किए गए इस युद्ध में पिछले तीन हफ्तों में सैकड़ों नागरिक मारे गए। इस बात पर कि किनके बमों से मारे जाएंगे, लीबियाइयों की जानों (मौतों) की कीमत बदल जाएगी, ऐसा दुनिया को यकीन दिलवाने की हरकत से ज्यादा घटियापन और कुछ नहीं हो सकता! मीडिया को खुद ही कहना पड़ा कि मारे गए लोगों में कई बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल साम्राज्यवादियों के मुखपत्र की तरह काम करने वाला मीडिया सच्चाइयों को तोड़-मरोड़कर गलत सूचनाओं का प्रसार कर रहा है। इस दुराक्रमणकारी युद्ध में मीडिया ने फिर एक बार अपने वर्गीय स्वभाव का परिचय दिया है।

खुद को निष्पक्ष संगठन बताने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि साम्राज्यवादी देशों की कठपुतली के रूप में इस मौके पर फिर एक बार साफ तौर पर साबित हो गई। उसके महासचिव बानकी मून ने खुद को अमेरिका

के पैरों के पास पूंछ हिलाने वाले कुत्ते के रूप में साबित किया। जब दिसम्बर 2008 में गाज़ा पर इज़्राएल ने अमानवीय हमले किए थे जिसमें 1,417 फिलिस्तीनी – जिनमें अत्यधिक बच्चे और महिलाएं थीं – मारे गए थे और कई हजार लोग घायल हो गए थे; जब इज़्राएली सेना ने गैर-कानूनी ढंग से सफेद फॉस्फरस जैसे बेहद खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया था जिससे गाज़ा के कई निवासी कैंसर का शिकार हुए थे; जब उसने एफ-16 विमानों का प्रयोग कर 'टार्गेटेड किल्लिंग्स' का सिलसिला चलाया; बिजली, पानी जैसी न्यूनतम जरूरतों से भी वंचित कर जब उसने 15 लाख गाज़ा के लोगों को 'खुले जेल' जैसे हालात में जीने को मजबूर किया तब राष्ट्र संघ ने 'उड़ान वर्जित क्षेत्र' का प्रस्ताव करने का साहस नहीं किया। जब नव-नात्सी राजपक्षे सरकार ने एलटीटीई का सफाया करने के लिए विनाशकारी युद्ध शुरू कर नागरिक क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों पर कई टन बम गिराए थे; जब उसने युद्ध के सिर्फ आखिरी दो दिनों के अंदर 20 हजार लोगों को मौत की नींद सुला दी थी; मारी गई या पकड़ी गई महिला टाइगरों पर सिंहली अंधराष्ट्रवादी सेनाओं ने अकथनीय अत्याचार किए थे तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ भी नहीं किया था। अपनी आजादी के लिए संघर्षरत कश्मीर की जनता पर दमनचक्र चलाते हुए भारत सरकार पिछले 25 बरसों से 80 हजार से ज्यादा कश्मीरियों का कत्लेआम करती आ रही है तो संयुक्त राष्ट्र संघ कुंभकर्ण की नींद सो रहा था जो अब यह कह रहा है कि उसने लीबिया में गद्दाफ़ी के खिलाफ लड़ रही जनता को बचाने के लिए कमर कस ली है। शर्म है! कुल मिलाकर देखा जाए, तो दर्जनों मौकों पर अमेरिका, इज़्राएल और पश्चिमी देशों के हितों को कथित रूप से जब नुकसान पहंचता है, तब राष्ट्र संघ ने जो दिलचस्पी या तत्परता दिखाई, उत्पीड़ित देशों व राष्ट्रीयताओं के मामले में कभी नहीं दिखाई।

दरअसल लीबिया युद्ध खुद अपने आप में संयुक्त राष्ट्र संघ के 'उड़ान-वर्जित क्षेत्र' प्रस्ताव के खिलाफ है। लीबिया को अपनी वायु सेना का इस्तेमाल कर विद्रोहियों पर हमले करने से रोकने के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा किए गए प्रस्ताव को लागू करने का दावा करते हुए लीबिया पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जो अंधाधुंध बमबारी शुरू की वह दुराक्रमण के अलावा कुछ नहीं है। गद्दाफ़ी को गद्दी से उतारकर अपने लिए अनुकूल किसी शासक गिरोह को सत्ता पर बिठाकर लीबिया में मौजूद तेल संपदा को लूटना ही उनका असली मकसद है। बहरीन में जन विद्रोह को दबाने के लिए पिछले दरवाजे से साउदी अरब की सेनाओं को

उतरवाने वाले ओबामा का यह कहना कि लीबियाई विद्रोहियों को बचाने के लिए ही उन्हें यह बमबारी करनी पड़ रही है, छिछोरापन की पराकाष्ठा है। अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में आए दिन अंधाधुंध ड्रोन हमले करते हुए सैकड़ों लोगों की जानें ले रहे 'नोबेल शांति पुरस्कार' से नवाजे गए इस रक्त-पिपासू को दरअसल जनता के प्राणों के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। साउदी अरब, येमेन, जोर्डान आदि देशों में दलाल शासकों के खिलाफ जिनका वे अब तक समर्थन करते रहे, संघर्षरत जनता को सशस्त्र बलों द्वारा गोली मार देने पर भी चुप्पी साधने वाले पश्चिमी देशों का यह कहना कि गद्दाफ़ी को सत्ता से हटा देना चाहिए, उनके दोगलेपन का साफ सबूत है। सोलह आणे की साम्राज्यवादी दोहरी नीति है!

पश्चिमी साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी से सांठगांठ करने वाले दलाल शासक - टुनीशिया का राष्ट्रपति बेन अली, मिस्र का राष्ट्रपति होस्नी मुबारक, येमेन का राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह, बहरीन का अमीर इसा अल खलीफा, जोर्डान का राजा अब्दुल्ला वगैरह - कई दशकों से अपने-अपने देशों में तानाशाही चला रहे हैं। नाम के वास्ते चुनाव होने पर भी उसमें कितना फर्जीवाड़ा होता होगा इसे समझने के लिए बस टुनीशिया का एक उदाहरण काफी है - राष्ट्रपति बेन अली को हर दफे 97 से 99 प्रतिशत वोट मिलते थे?! जनता को किसी भी प्रकार के नागरिक और राजनीतिक अधिकार नहीं हैं। पुलिस व खुफिया अमले जनता की हर गतिविधि को नियंत्रित करते हुए दमन करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का विरोध न उठने पाए। इन सभी देशों में बेरोजगारी का तांडव जारी है। मिसाल के तौर पर येमेन में 40 प्रतिशत बेरोजगारी है। दूसरी ओर यहां के शासकों को तेल स्रोतों पर मालिकाना है जिसके फलस्वरूप उन्होंने अनगिनत संपदाएं इकट्ठी कर रखी हैं। अरबों डॉलर का धन विदेशी बैंक में छुपाकर रखा है। टुनीशिया से भागते-भागते बेन अली अपने साथ डेढ़ टन सोना भी ले उड़ा जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक-एक तानाशाह ने जनता को लूटकर कितना धन इकट्ठा किया होगा। दूसरी ओर 2008 से विश्व अर्थव्यवस्था को झकझोरने वाले संकट का असर भी अरब देशों पर पड़ रहा था जिससे जनता अकथनीय मुश्किलों से परेशान है। आबादी का आधा से ज्यादा हिस्सा रोजाना दो डॉलर से कम आमदनी पर दुभर जिंदगी जी रहा है। अमेरिका द्वारा शुरू किए गए 'आतंक के खिलाफ युद्ध' के तहत इन देशों के तानाशाह अल कायदा को कुचलने के नाम

पर जन धन का अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। येमेन ने 75 करोड़ डॉलर पर आतंकवाद-विरोधी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। जनता को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती कर जन धन का इस तरह दुरुपयोग करना भी जनता को नागवार गुजरा। अभी तक धर्म के नाम से तथा शिया और सुन्नियों बीच तथा विभिन्न कबीलों के बीच मौजूद अंतरविरोधों का फायदा उठाते हुए साम्राज्यवादियों ने इन तानाशाहों का हर तरह से समर्थन किया। और जनता पर उनके शोषण, उत्पीड़न समेत सभी दमनात्मक कदमों का समर्थन किया। लेकिन जन उभार की तीव्रता को भांपकर इन बूढ़े घोड़ों का पिंड छुड़ाकर नए घोड़ों को तलाश लेना बेहतर समझा। चुपके से बेन अली और मुबारक को सत्ता से हटवाकर वहां के सैन्य जनरलों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण करवा दिया। वहीं दूसरे देशों में पश्चिमी देश अभी भी शासकों के ही पक्ष में खड़े हैं। 22 अरब देशों का गठबंधन अरब लीग इस पूरे संदर्भ में पश्चिमी देशों के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। अरब राष्ट्रवाद या अरब जनता की साम्राज्यवाद-विरोधी आकांक्षाओं का वह जरा भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है।

जनता की जनवादी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले तथा तमाम जनता को एकजुट कर साम्राज्यवाद का मुखर विरोध करने वाले शासक ही अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं और अपने देश की सम्प्रभुता को टिकाए रख सकते हैं। जनता पर तानाशाही चलाने वाले शासक, चाहे वह गद्दाफ़ी हो या फिर कोई और, साम्राज्यवाद से समझौताहीन संघर्ष नहीं कर सकते। जनता को साम्राज्यवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़े नहीं रख सकते। अपार तेल संसाधनों से समृद्ध पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका पर अपना दबदबा कायम करने के लिए साम्राज्यवादी शुरू से कई साजिशों, षड़यंत्रों और दुराक्रमणकारी युद्धों को अंजाम देते आ रहे हैं। ऐसे तानाशाहों का जो उनके सामने घुटने टेकते हुए उनके हितों को तवज्जो देते हैं, वे समर्थन करते हैं। ऐसे तानाशाहों के प्रति जिनके बारे में वे समझते हैं कि उनके हितों को कहीं न कहीं नुकसान कर सकते हैं, वे 'यूज़ एण्ड थ्रो' (इस्तेमाल करो और फेंक दो) वाली नीति लागू करते हैं।

अरब देशों की जनता से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का आह्वान :

अरब देशों की जनता को चाहिए कि वह तानाशाहों और साम्राज्यवादियों के

खिलाफ अपने आंदोलनों को दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखें। साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा इन आंदोलनों का अपहरण करने की कोशिशों का मजबूती से मुकाबला करना चाहिए। सत्ता से हट चुके तानाशाहों का स्थान ग्रहण करने वाले सैन्य परिषदों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हमारी पार्टी अरब जगत् की समूची जनता को सावधान करती है कि वे उन सैन्य जनरलों से, जिन्होंने अभी तक तानाशाहों का साथ दिया था, यह उम्मीद न रखें कि वे लोकतंत्र की गारंटी कर सकते हैं। मजदूरों और किसानों समेत सभी जनवादी तबकों, मध्यम वर्ग, देशभक्त व साम्राज्यवाद-विरोधी ताकतों को एकजुट होना होगा। मजदूर वर्ग के नेतृत्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष करने के अलावा अरब जनता के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। अरब दुनिया के घटनाक्रम ने इस सच्चाई को फिर एक बार साबित कर दिया कि उत्पीड़ित जन समुदायों की वास्तविक मुक्ति के लिए मार्क्सवादी विचारधारा का मार्गदर्शन और सर्वहारा के अग्रणी दस्ते के रूप में क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व बेहद जरूरी हैं। विभिन्न देशों को औपचारिक स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद एक जमाने के उपनिवेशवाद का स्थान लेने वाला नव-उपनिवेशिवाद कितने दूभर हालात पैदा कर सकता है, इसे अरब दुनिया की जनता ने पिछले 40-50 सालों में अपनी आंखों से देखा है। अगर नव-उपनिवेशवाद का खात्मा कर असली आजादी हासिल करनी है तो अरब जनता को अपने पैरों पर खड़े होकर साम्राज्यवाद के खिलाफ दृढ़तापूर्वक लड़ना होगा। लीबिया पर अन्यायपूर्ण युद्ध छेड़ने वाले अमेरिकी, ब्रितानी और फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों के खिलाफ एकजुटता से लड़ना चाहिए। भाकपा (माओवादी) यह आशा करती है कि अलग-अलग देशों में साम्राज्यवादियों का समर्थन प्राप्त दलाल तानाशाहों के खिलाफ लड़े जाने वाले संघर्षों का ऐसा विकास हो जो साम्राज्यवाद का मुखरता से विरोध करते हों, उसकी दखलंदाजी और उसके द्वारा थोपे जाने वाले अन्यायपूर्ण युद्धों का दृढ़ता से प्रतिरोध करते हों। तभी अरब दुनिया तानाशाहों और साम्राज्यवादियों के शिकंजे से मुक्ति प्राप्त कर सकेगी।

भारत की जनता और विश्व जनता से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का आह्वान :

आजादी और लोकतंत्र के लिए अरब देशों की जनता द्वारा किए जा रहे आंदोलन पूर्णतः न्यायपूर्ण हैं। इसके बावजूद भी कि आंदोलनकारी ताकतों में धार्मिक कट्टरपंथी और अन्य प्रतिक्रियावादी कुछ हद तक मौजूद हों, ये आंदोलन

लोकतांत्रिक और प्रगतिशील हैं। इन आंदोलनों का तहेदिल से समर्थन करना चाहिए। अरब क्षेत्र के मामलों में साम्राज्यवादियों की दखलंदाजी तथा लीबिया पर पश्चिमी साम्राज्यवादियों द्वारा थोपे गए अन्यायपूर्ण युद्ध का एक स्वर में विरोध करना चाहिए।

- **लीबिया पर अमेरिका के नेतृत्व में जारी नाटो के अन्यायपूर्ण युद्ध को फौरन रोक दो!**
- **लीबिया के अंदरूनी मामलों में दखल देने का अधिकार साम्राज्यवादियों को कतई नहीं है!**
- **अरब दुनिया के मामलों में साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की हस्तक्षेप भरी नीतियों का पर्दाफाश करो!**
- **अरब देशों में जारी जायज जन आंदोलनों का समर्थन करो!**

अभय

प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

5 अप्रैल 2011

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करो!

शोषण-उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, हिंसा, अत्याचार और अपमान से भरी मौजूदा अर्ध-औपनिवेशिक व अर्ध-सामंती व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंककर जनता की जनवादी राजसत्ता की स्थापना हेतु जनयुद्ध को तेज करो!

पांच राज्यों – असम, तमिलनाडू, केरल, पांडिच्चेरी और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए चुनावों का ढकोसला शुरू हो गया। जहां सारा देश भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, संसाधनों की लूट, विस्थापन, पर्यावरण का विनाश आदि समस्याओं से दो चार है, वहीं सभी संसदीय पार्टियों ने एड़ी-चोटी का जोर लगा रखा है ताकि जनता को फिर एक बार धोखा देकर इन राज्यों में सत्ता हथियाई जा सके। देश में साम्राज्यवाद-निर्देशित आर्थिक नीतियों को लागू करने में आगे रहने वाली प्रमुख शोषक वर्गीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा समेत; सीपीएम जो पिछले 30 सालों से पश्चिम बंगाल में फासीवादी शासन लागू करती आ रही है; डीएमके और अन्ना डीएमके जो भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए खासा बदनाम हैं; असम की जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ गद्दारी करने वाला असम गण परिषद वगैरह पार्टियां मुख्य रूप से इन राज्यों में सत्ता पर कब्जा करने के लिए मैदान में हैं। सभी नेता धन बल, बाहु बल, जाति, धर्म आदि हथियारों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से भिड़ रहे हैं ताकि वोट बटोर लिए जा सके। फूहड़ता की हदें पार कर मतदाताओं को साड़ियों से लेकर कम्प्यूटर तक कुछ भी दे देने का आश्वासन देने में एक दूसरे को मात दे रहे हैं। करोड़ों रुपए का धन बहाकर 'वोटों को खरीदने' की कोशिशों में लगे हुए हैं।

पिछले 30 सालों से पश्चिम बंगाल में सामाजिक फासीवादी शासन चलाती आ रही सीपीएम ने सामंती, साम्राज्यवादी व दलाल नौकरशाह पूंजीवादी लूटखसोट का समर्थन कर खुद को जनता की नजरों में नंगा कर लिया। टाटा, जिंदल जैसे दलाल पूंजीपतियों के हित में तथा एसईजेड के नाम से किसानों की जमीनें छीनने

की कोशिशों के खिलाफ नंदीग्राम और सिंगूर में आंदोलन छेड़ने वाली जनता पर तथा लालगढ़ इलाके में पुलिसिया अत्याचारों के खिलाफ उमड़े जन सैलाब के ऊपर सीपीएम ने पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अपनी गुण्डा सेना 'हर्मद बाहिनी' के जरिए बर्बर दमन, अमानवीय हत्याकाण्ड और महिलाओं के साथ अत्याचारों का जो सिलसिला चलाया, वह इतिहास में काले धब्बा बनकर रह जाएगा। सीपीआई, फार्वर्ड ब्लॉक जैसी वाम मोर्चे की घटक पार्टियां सीपीएम की जन विरोधी नीतियों का समर्थन करने वाली दिवालिया पार्टियों के रूप में जनता में नंगी होती जा रही हैं। सीपीएम के प्रति सभी वर्गों की जनता में सुलग रहे असंतोष और गुस्से का फायदा उठाकर ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस सत्ता हथियाने के लिए एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरकर आई है। इससे सीपीएम इस बार सत्ता के सुख से हाथ धोने का खतरा झेल रही है। आज ममता बनर्जी की कथनी चाहे जो भी हो, कल चुनाव जीतने के बाद जो शासन वह चलाएगी, वह सीपीएम से बुनियादी रूप से भिन्न नहीं रहेगा। यह बात स्पष्ट है कि कांग्रेस से गठबंधन के बल पर ममता जो शासन लाएगी वह सामंतवाद व कार्पोरेट अनुकूल और जन विरोधी नीतियों की धारवाहिकता के रूप में ही होगा जिसे सीपीएम समेत तमाम अन्य शासक वर्गीय पार्टियां लागू करती आ रही थीं। कांग्रेस, भाजपा और सीपीएम की तरह तृणमूल भी वही पार्टी है जो सामंती व दलाल पूंजीपति वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है और जो साम्राज्यवाद के सामने नतमस्तक है। इसलिए बंगाल की जनता के सामने एक रास्ता बचता है कि वे इन ढोंगी चुनावों का बहिष्कार कर, लालगढ़ जनता के उज्ज्वल संघर्ष की प्रेरणा से माओवादी जनयुद्ध को केन्द्र में रखते हुए जुझारू जन संघर्षों का निर्माण करें। असली विकल्प यही है कि ऐतिहासिक लालगढ़ आंदोलन के परिणामस्वरूप भ्रूण रूप में अस्तित्व में आई वैकल्पिक जन राजसत्ता का और ज्यादा सुदृढ़ व जुझारू ढंग से विस्तार किया जाए।

तमिलनाडू मुख्यमंत्री करुणानिधि, पूर्व टेलिकॉम मंत्री ए. राजा और उनके डकैतों का गिरोह जिसने राज्य में सत्ता और केन्द्र में यूपीए गठबंधन में भागीदारी का फायदा उठाते हुए लाखों करोड़ रुपए के घोटाले किए थे, अब फिर से प्रदेश में सत्ता हथियाने के लिए करोड़ों रुपए बहा रहा है। करुणानिधि सरकार ने तकरीबन 70 एसईजेड को मंजूरी देकर हजारों हेक्टेयर जमीनें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले कर दीं। किसानों और मजदूरों की जिंदगी दूभर बना दी। अकेले तिरपुर

शहर में पिछले दो सालों में 25 हजार मजदूरों की नौकरियां छीन ली गईं जिसके परिणामस्वरूप दो हजार कपड़ा-मजदूरों ने खुदकुशी कर ली। वर्तमान में डीएमके के प्रति जनता में बढ़े हुए असंतोष का फायदा उठाते हुए जयललिता की अगुवाई वाली अन्ना द्रमुक किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है। लेकिन गौरतलब है कि जयललिता भी कम बड़ी चोर नहीं है जिसका विगत में सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हजारों करोड़ रुपए की सम्पत्तियां हासिल करने का इतिहास रहा है। तमिल राष्ट्रीयता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने का दम्भ भरने वाली डीएमके और अन्ना डीएमके दोनों ही ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने श्रीलंका में सिंहली अंधराष्ट्रवादी राजपक्षे सरकार द्वारा एलटीटीई का सफाया करने के लक्ष्य से किए गए अन्यायपूर्ण युद्ध और तमिलों के कत्लेआम का परोक्ष रूप से समर्थन किया था। अत: तमिलनाडू की जनता के सामने यही विकल्प है कि वह उक्त दो पार्टियों के साथ-साथ उनकी सभी सहयोगी पार्टियों को नकार कर जन आंदोलनों और क्रांतिकारी संघर्षों को तेज कर दे।

केरल में सीपीएम की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ वाम मोर्चे की सरकार कई घपलेबाजियों व घोटालों में लिप्त होकर कॉर्पोरेट वर्गों के हितों की रक्षा करते हुए जनता में खासी बदनाम हो चुकी है। जनता के असंतोष का फायदा उठाते हुए वहां पर कांग्रेस-नीत गठबंधन यूडीएफ किसी न किसी तरीके से सत्ता पर काबिज होने के लिए कई पापड़ बेल रहा है। असम में असम गण परिषद, जिसका विगत में असमिया जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आंदोलन चलाने का इतिहास रहा है, आज राष्ट्रीय हितों के साथ गद्दारी कर सत्ता की होड़ में लगा हुआ है। उल्फा, बोडो आदि न्यायपूर्ण राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का दमन करने में उसने कांग्रेस के साथ सांठगांठ कर रखी है।

खासकर पिछले कुछ समय से देश में आए दिन घपलों और घोटालों के खुलासे होने लगे हैं, जिससे देश की राजनीतिक व्यवस्था का असली रूप दिन-ब-दिन साफ तौर पर सामने आ रहा है। हाल में उजागर होने वाले 2जी स्पेक्ट्रम आदि घोटालों से यह बात और ज्यादा स्पष्ट हो गई कि किस तरह सभी पार्टियों के मंत्री, नेता, कॉर्पोरेट घरानों के मालिक और मीडिया सम्राट सांठगांठ कर लाखों करोड़ रुपए डकार रहे हैं। जहां एक तरफ अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करने वाली विभिन्न तबकों की जनता, जन आंदोलनों और क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलने के लक्ष्य से लुटेरे शासक अपने सशस्त्र बलों के जरिए दमन

अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फासीवादी कानूनों को तैयार कर जनता और आंदोलनकारियों को बिना किसी सुनवाई के सालों तक जेलों में बंद कर रहे हैं तथा उन्हें कठोर सजाएं दिलवा रहे हैं। कथित रूप से संविधान द्वारा प्राप्त जीने के अधिकार समेत जनता के तमाम बुनियादी अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

इन चुनावों को 'सुचारू रूप से' (यानी हिंसा, अत्याचार, जनता पर गोलीबारी, गिरफ्तारियां और फर्जी मतदान के रूप में समझ लेना चाहिए) संपन्न कराने के लिए केन्द्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 800 से ज्यादा कम्पनियां तैनात कर दीं। गौरतलब है कि इनमें से 600 से ज्यादा कम्पनियां पश्चिम बंगाल में भेजी जा रही हैं जहां माओवादी आंदोलन अपेक्षाकृत मजबूत है। चुनावों से काफी पहले से ही सीपीएम ने अपने गुण्डों की सेना हर्मद वाहिनी के हजारों हथियारबंद गिरोहों को खासकर जंगलमहल इलाके के दर्जनों गांवों में लगा दिया। इन हथियारबंद गुण्डा गिरोहों और संयुक्त बलों के पाशविक अत्याचार और अकथनीय हिंसा पहले से जारी है। इसका मतलब यह है कि वोट डालने से इनकार करने वाली जनता को बंदूक की नोक पर मतदान केन्द्रों पर हांक ले जाने तथा अभूतपूर्व स्तर पर भारी फर्जी मतदान करने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में सीपीएम बड़े पैमाने पर हिंसा और आतंक मचाने के लिए मुस्तैदी से तैयार है ताकि वह किसी न किसी तरीके से सत्ता पर बने रह सके।

सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी या गठबंधन रहे या फिर जो भी पार्टी या गठबंध न चुनाव जीतकर सत्ता में आना चाहता हो, वे सभी सामंतों, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों के हितों को ही पूरा करेंगे न कि मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, छात्रों, महिलाओं, दलितों आदि उत्पीड़ित वर्गों/तबकों की भलाई के लिए काम करेंगे जो आबादी का 95 प्रतिशत हैं। यह सच्चाई पिछले 64 सालों के तथाकथित स्वतंत्र भारत के इतिहास में साबित हो चुकी है। दरअसल यह चुनाव ही सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। यह लुटेरे वर्गों के शासन को पुख़्ता करने वाला एक कवायद है। इन चुनावों से ज्यादा से ज्यादा शासक गिरोह के रंग में या उसकी पार्टी में बदलाव आ सकता है, मौजूदा व्यवस्था में कोई बुनियादी बदलाव कतई नहीं आएगा। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी जनता की बुनियादी समस्याओं का हल नहीं होगा। चुनावों में पूंजी के तौर पर पैसा ही लगाया जाता है। संसद और विधानसभा का संचालन भी पैसे वाले ही करते हैं। चुनाव जीतने के बाद भी कई गुना पैसा कमाते हैं। चुनाव लड़ने वाले सभी पार्टियों के उम्मीदवारों में हत्या,

अपहरण, बलात्कार जैसे संगीन जुर्मों में लिप्त आपराधिक चरित्र वालों की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी उनके स्वभाव को प्रतिबिम्बित कर रही है। इसीलिए हमारी पार्टी यह स्पष्ट करती है कि संसद और विधानसभाएं 'सुअरबाड़ों' के अलावा कुछ नहीं हैं। मौजूदा व्यवस्था को जड़ से बदले बिना जनता की जिंदगियां नहीं बदलेंगी। नई जनवादी क्रांति को सफल बनाकर मजदूर-किसान एकता के आधार पर तमाम शोषित जनता की जनवादी राजसत्ता का निर्माण करना ही एक मात्र विकल्प है। हमारी केन्द्रीय कमेटी तमाम जनता का आवाहन करती है कि वह इसके लिए हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी जनयुद्ध में शामिल हो।

प्यारे लोगो!

फिलहाल पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करें। 'लोकतंत्र' बताए जाने वाले देश में वोट डालने के अधिकार के साथ-साथ वोट नहीं डालने का अधिकार भी होना चाहिए। इस अधिकार के हनन के खिलाफ संघर्ष करें। सशस्त्र पहरे में जनता को बलपूर्वक मतदान केन्द्रों में हांक ले जाने के खिलाफ आवाज उठाएं। भ्रष्टाचार-घोटालों से सड़-गल चुकी इस ढोंगी संसदीय जनवादी व्यवस्था को ठुकरा दें। दण्डकारण्य, बिहार-झारखण्ड, ओड़िशा, बंगाल आदि जगहों पर हमारी पार्टी के नेतृत्व में प्राथमिक स्तर पर आकार ले रही जनता की जनवादी राज्य व्यवस्था का स्वागत करते हुए देश के चारों ओर जनता की राजसत्ता की स्थापना के लिए कमर कस लें।

अभय

प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

13 अप्रैल 2011

व्यवस्थीकृत हो चुके भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए जन संघर्षों को तेज करो!

हाल के दिनों में उजागर हुए 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कामनवेल्थ घोटाला, आदर्श हाउजिंग सोसायटी, कर्नाटका जमीन खरीद, एस-बैंड स्पेक्ट्रम आदि घोटालों ने भ्रष्टाचार को फिर एक बार एक बड़ी समस्या के रूप में सामने लाया। मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, महिलाएं, मुख्य रूप से शहरी मध्यम वर्ग आदि सभी वर्गों और सभी तबकों की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना गुस्सा और नाराजगी प्रकट कर रही है। जनता में भ्रष्टाचार, भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों तथा उन पार्टियों के नेताओं के प्रति संचित गुस्से का नतीजा ही था हाल में अन्ना हजारे द्वारा की गई भूख हड़ताल को देश भर में जनता से मिली प्रतिक्रिया। जहां उनकी अनशन का लक्ष्य जन लोकपाल विधेयक ही था, वहीं देश के चारों कोनों से व्यक्त हुई जनता की आकंक्षा तो भ्रष्टाचार का जड़ से सफाया करने की है। लोकपाल विधेयक तैयार करने हेतु कमेटी का गठन कर उसमें आधे सदस्यों का चयन नागरिक समाज में से करने का सरकार ने जो फैसला लिया, इससे इस समस्या का हल हो गया या हो जाएगा, ऐसा मानना नादानगी ही होगी।

दरअसल आज भ्रष्टाचार के इतने गहरे तक जड़ें जमा लेने और बेहिसाब बढ़ जाने का यह कारण नहीं है कि यहां इसे रोकने का कोई कारगर कानून-कायदा ही मौजूद नहीं है। कानून चाहे जितने भी हों, चूंकि उन पर अमल करने और करवाने वाली व्यवस्था पर ही लुटेरे वर्गों का कब्जा है, इसीलिए यह बदहाली व्याप्त है। एक जमाने के जीप घोटाला और लॉकहीड विमान खरीदी घोटाले से लेकर राजीव गांधी के समय का बोफोर्स घोटाला आदि अनगिनत घोटालों का लम्बा इतिहास रहा है हमारे देश में। चंद करोड़ रुपयों से शुरू कर आज लाखों करोड़ रुपए के घोटाले सामने आ गए हैं। कांग्रेस, भाजपा

जैसी मुख्य संसदीय पार्टियों से लेकर आरजेडी, बीएसपी, एसपी, डीएमके, अन्ना डीएमके, तेलुगुदेशम वगैरह सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियों के नेता व मंत्री तथा उनके पिट्ठू प्रशासनिक अधिकारी सभी का दामन भ्रष्टाचार से दागदार है। देश में पहले से मौजूद कानूनों पर ठीक से अमल कर और विभिन्न भ्रष्टाचार-विरोध ी विभागों का ठीक से संचालन कर ऐसे भ्रष्टाचार-घोटालों को रोका जा सकता है तथा उसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजाएं दिलवाई जा सकती हैं। लेकिन पिछले 64 सालों के 'आजाद' भारत के इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें भ्रष्ट राजनेताओं, मंत्रियों, कार्पोरेट घरानों के मालिकों और नौकरशाहों को कभी कोई सजा मिली हो। जनता और विपक्ष के दबाव के कारण विरल मौकों पर किसी को गिरफ्तार कर किया भी गया तो सालों साल तक खिंचने वाली अदालती कार्रवाई के बाद मामलों को रफा-दफा कर दिया जाता है। बिना किसी सजा के या नाम मात्र की सजा से बरी भी कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौजूदा न्यायव्यवस्था भी देश की शोषक राज्य मशीनरी का अभिन्न अंग है। यह उम्मीद रखना कि कानूनों या न्यायालयों के जरिए भ्रष्टाचार का अंत हो जाएगा, मरीचिका में पानी की उम्मीद रखने के बराबर होगा।

सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि भ्रष्टाचार चंद बुरे लोगों या लोभियों के आचरण से उपजा हुआ मामला नहीं है। भ्रष्टाचार व घोटाले उस पूंजीवादी व्यवस्था का विकृत परिणाम है जिसका मूलमंत्र ही मुनाफे के पीछे भागना है। हालांकि पूंजीवाद ऊपर से लोकतंत्र का चोला ओढ़ा हुआ रहता है तथा आजादी, समानता आदि मूल्यों की रट लगाया करता है, लेकिन वास्तव में वह दूभर श्रम-शोषण, रिश्वतखोरी, दलालखोरी आदि अव्यवस्थाओं से भरा रहता है। इसलिए भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं को जड़ से खत्म करने का मुद्दा व्यवस्था-परिवर्तन से जुड़ा हुआ सवाल है। यह मानकर चलना एक कोरा भ्रम ही होगा कि देश में मौजूद अर्धऔपनिवेशिक व अर्धसामंती व्यवस्था को बनाए रखते हुए ही चंद बेहतर कानूनों के सहारे से इस समस्या का पूरी तरह समाध

ान किया जा सकता है।

दरअसल घोटालों के रूप में जो उजागर होते हैं, उनसे कई गुना ज्यादा रोशनी में आए बिना ही रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आंध्रप्रदेश के मृत मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रमनसिंह, ओड़िशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, झारखण्ड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, अर्जुन मुण्डा, कर्नाटका मुख्यमंत्री येदियूरप्पा समेत और कई नेताओं ने जिस प्रकार माइनिंग माफिया से हाथ मिलाकर दलाली खाई और कई बड़ी कम्पनियों के साथ गुप्त एमओयू कर दलाली के रूप में हजारों करोड़ रुपए अवैध रूप से जो कमाए, उसके बारे में यहां तक कि अखबारों ने भी चर्चा की है। सरकारों द्वारा लागू उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण की नीतियों ने ही इस तरह के कई भ्रष्टाचार-घोटालों के लिए तथा देश की सम्पदाओं की मनमानी लूटखसोट के दरवाजे खोल रखे हैं। इस पृष्ठभूमि में इन साम्राज्यवाद-परस्त नीतियों का विरोध किए बिना तथा उनके खिलाफ संघर्ष छेड़े बिना ही भ्रष्टाचार का अंत कर पाने की आस लगाए बैठना या कर पाने का दावा करना जनता को गुमाराह करना ही है।

लोकपाल विधेयक के लिए सरकार द्वारा सांझी कमेटी की घोषणा की जाने के बाद अन्ना हजारे ने तो अपनी अनशन तोड़ दी, लेकिन जनता को इससे इंसाफ नहीं मिला जो देश भर में उनकी हड़ताल के साथ खड़ी हुई थी। दरअसल सरकार ने यह मांग अन्ना की भूख हड़ताल से डरकर पूरी नहीं की, बल्कि उनके समर्थन में उभर कर आए जनता के आक्रोश को ठण्डा करने के लिए की। उससे भी बड़ी बात यह है कि चूंकि शासक वर्ग भली भांति जानते हैं कि इस तरह के काननों से मौजूदा व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इसीलिए उन्होंने बेखौफ होकर लोकपाल विधेयक के लिए कमेटी की घोषणा की।

भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में आगे आई जनता का भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी स्वागत करती है। भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष

का हमारी पार्टी तहेदिल से समर्थन करती है। हमारी पार्टी का यह विश्वास है कि जनता के सांझे, संगठित और जुझारू संघर्षों के जरिए ही भ्रष्टाचार का अंत करना संभव हो सकेगा। हमारी पार्टी देश की जनता से आग्रह करती है कि वह सरकार द्वारा घोषित सतही कानूनों और कानून तैयार करने के लिए कमेटियों के गठन की घोषणाओं से संतुष्ट होकर अपने संघर्ष को समाप्त न करे, बल्कि संघर्ष की राह पर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। मजदूरों, किसानों, छात्रों, बुद्धिजीवियों, कर्मचारियों, जनता की भलाई चाहने वाले गांधीवादियों समेत तमाम देशभक्त तबकों का हमारी पार्टी आह्वान करती है कि वे देश में कैंसर की तरह फैल चुके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाकर सड़कों पर उतर आएं। हमारी पार्टी की अपील है कि यह नारा बुलंद किया जाए कि उन डकैतों और महाचोरों को सत्ता में एक पल के लिए भी बने रहने का हक नहीं है जो अंतहीन भ्रष्टाचार व घोटालों में लिप्त होकर देश की जनता का खून-पसीना चूसते हुए लाखों करोड़ों रुपए का काला धन स्विस बैंकों में छुपा रहे हैं।

अभय

प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

28 अप्रैल 2011

जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र के खिलाफ आंदोलनरत जनता पर पुलिस की गोलीबारी और गिरफ्तारियों की निंदा करो!

जैतापुर संयंत्र समेत देश में प्रस्तावित सभी परमाणु बिजली संयंत्रों को रद्द करने के लिए संघर्ष करो!

18 अप्रैल 2011 को जैतापुर के 9,900 मेगावाट वाले प्रस्तावित परमाणु बिजली संयंत्र के खिलाफ आंदोलन कर रही जनता पर पुलिस ने गोलीबारी की जिसमें परमाणु-विरोधी कार्यकर्ता तबरेज़ सोयेकर (32) की मौत हुई जो नाटे गांव का निवासी था और अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला आदमी था। आठ अन्य प्रदर्शनकारी बुरी तरह घायल हो गए। विरोध-प्रदर्शनकारियों ने एक अस्पताल पर हमला कर दिया ताकि वहां पर सरकारी शव-परीक्षण को रोका जा सके क्योंकि उन्हें यह भरोसा नहीं था कि सरकार निष्पक्ष शव-परीक्षण करवाएगी। जापान में फुकुशिमा परमाणु बिजली संयंत्र में हुए परमाणु हादसा के बाद तेजी पकड़ने वाले इस चार साल पुराने आंदोलन ने अच्छा-खासा अनुभव प्राप्त किया था जिससे सरकार की संवेदनहीनता को समझा जा सके।

बढ़ रहे विरोध प्रदर्शनों की अनदेखी करते हुए तथा पीड़ितों को मुआवजा देने या आश्वस्त करने की कोई कोशिश नहीं करते हुए पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश और महाराष्ट्र सरकार (जो साम्राज्यवादियों के पालतू कत्ते हैं) ने अपना मंतव्य दोहराया कि वे 'दुनिया के इस बहुत बड़े परमाणु बिजली सुमदाय' के निर्माण को जारी रखेंगे जिसमें छह रिएक्टर होंगे। दरअसल, सरकार ने फुकुशिमा त्रासदी को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए 'किसी भी कीमत पर' परमाणु बिजली पार्क को बनाने की जो नीति अपनाई, उसके खिलाफ हुआ था उपरोक्त विरोध प्रदर्शन।

पुलिस ने करीब 100 लोगों और जाने-माने कार्यकर्ताओं को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया, जो भारत के हर कोने (महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडू, झारखण्ड,

पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्यप्रदेश) से इकट्ठे हुए थे ताकि 23 से 25 अप्रैल तक तारापुर से, जहां भारत का पहला परमाणु बिजली प्लांट की स्थापना हुई, जैतापुर तक प्रस्तावित राष्ट्रीय परमाणु-विरोधी यात्रा में भाग लिया जा सके। दरअसल, फुकुशिमा के बाद परमाणु बिजली परियोजनाओं के खिलाफ देश में चारों तरफ, खासकर हरियाणा, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश में कुछ नए और कुछ पहले से चले आ रहे विरोध-प्रदर्शनों का एक सिलसिला ही चल पड़ा। लेकिन इससे हमारे बहरे शासकों के कान में जूं तक नहीं रेंगी।

इस परमाणु संयंत्र के तहत पांच गांव - मडबन, निवेली, करेल, मितगावणे और सखारी नाटे आते हैं जो महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के जैतापुर क्षेत्र में स्थित हैं और यह भूकम्प के प्रभाव में आ सकने वाला क्षेत्र है। यहां पर 968 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया। इस संयंत्र से 40 हजार जनता प्रभावित होगी जिसमें 16 हजार आबादी मछवारों की है।

फुकुशिमा हादसे के बाद जहां कई देश अपने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर दोबारा विचार कर रहे हैं, वहीं भारत सरकार अपने परमाणु कार्यक्रम पर अड़िग है। इस सचाई को छिपाकर कि भारत के रिएक्टरों को दुनिया के सबसे अक्षम और खतरनाक माने जाते हैं, कुछ जन-विरोधी वैज्ञानिक जनता को गुमराह करने के लिए सफेद झूठ बोल रहे हैं कि भारत के सुरक्षा मानक जापान से भी बेहतर हैं! जयराम रमेश जो अभी तक खुद को पर्यावरणवादी मंत्री कहते नहीं थकते थे, अब यह कहते हुए कि परमाणु ऊर्जा का कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने अपना असली कॉर्पोरेट-अनुकूल चेहरा दिखा दिया है। वह अब मनमोहनसिंह की भाषा बोल रहे हैं जिन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद भारत-अमेरिका परमाणु करार पर दस्तखत कर परमाणु कम्पनियों से मिली अरबों रुपए की दलाली से वोट खरीदे थे। जब समूची दुनिया विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को तलाश रही है, ये मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इसका कोई विकल्प नहीं है, मानों हम सब भारतीय बेवकूफ हों जो इस बकवास पर विश्वास करें। अगर घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र की बिजली की बुनियादी जरूरतें पूरी करनी हैं तो यहां सब कुछ संभव है। लेकिन ऐसे देश में जहां मुकेश अम्बानी का एक महीने का बिजली बिल 71 लाख रूपए का है और जहां बिजली की भारी खपत की जरा भी परवाह किए बिना दिन और रात के क्रिकेट मैच खेले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कृषि संकट में फंसे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं जिसका एक कारण बिजली की किल्लत भी है।

लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में मद्धिम रोशनी देने वाली एक बत्ती तक नहीं है। ऐसे में यह कयास लगाया जा सकता है कि मंत्री महोदय किन लोगों की ऊर्जा की जरूरतों की बात कर रहे हैं। केन्द्र और राज्यों की दलाल सरकारों ने भारत के व्यापक ग्रामीण और वन क्षेत्रों में मौजूद अपार खनिज भण्डारों का उत्खनन करने के लिए सैकड़ों एमओयू पर दस्तखत कर रखे हैं। खदानों और विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत है। कार्पोरेट कम्पनियों की इन जरूरतों ने ही जयराम रमेश, मनमोहनसिंह जैसे लोगों को पागल बना दिया है जो जनता के जबर्दस्त विरोध के बावजूद भी बिजली संयंत्रों को बनाने पर आमादा हैं। जनता की आजीविका, देश के पर्यावरण की सुरक्षा आदि मुद्दे जो विरोध -प्रदर्शनकारी उठा रहे हैं वो इनके लिए बेतुके हैं। एक मात्र समाधान जो वो जानते हैं वह है उन्हें 'कानून और व्यवस्था' की समस्या के रूप में देखना।

और तो और, हम यह कभी नहीं जान पाएंगे (बशर्तेकि कोई और विकी 'लीक' सामने न आ जाए) कि हमारे दलाल शासकों ने फ्रांस की कम्पनी 'आरेवा' से कितनी दलाली ले रखी होगी जिससे हम रिएक्टर आयात कर रहे हैं जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे परमाणु-अनुकूल देशों ने इस कम्पनी को डिजाइन क्लियरेन्स देने से इनकार कर दिया। दुनिया में अभी तक एक भी इवोल्यूशनरी प्रेशराइज्ड रिएक्टर (ईएफआर) का न तो निर्माण हुआ और न ही उसकी सुरक्षा की जांच हो पाई जिससे ये बिल्कुल ही अविश्वसनीय और असुरक्षित विकल्प माने जाते हैं। फिर भी अपने साम्राज्यवादी आकाओं के तलवे चाटने वाले हमारे शासक उन्हें खरीदने के लिए उतावले हो रहे हैं जबकि वो मानवीय और पर्यावरणीय क्षति का जरा भी अंदाजा नहीं लगा रहे हैं।

फुकुशिमा हादसे ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और उसका संहारक परमाणु विकिरण का प्रभाव दसियों हजार सालों तक रहेगा। स्वतंत्र यूरोपियाई चिकित्सा विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि रिएक्टर के 200 किलोमीटर के दायरे में 4 लाख से ज्यादा लोग कैंसर से ग्रस्त होंगे और इस संयंत्र का विकिरणीय प्रदूषण पूरी दुनिया में फैल जाएगा। 25 साल पहले चेर्नोबिल में हुए परमाणु हादसे के बाद चार लाख लोगों को खाली कराया गया था। अन्य दसियों लाख लोग अभी भी लगातार प्रदूषित वातावरण में डर के साये में जीने को मजबूर हैं कि कभी भी उन्हें कैंसर जकड़ ले सकता है और उनकी कई आने वाली पीढ़ियां गंभीर बीमारियों के साथ जन्म ले सकती हैं। अभी तक करीब दस लाख लोग उसके

विलम्बकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभावों से मारे जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। अगर जैतापुर में कोई बड़ा हादसा होगा तो समूचे रत्नगिरी जिले को पूरी तरह खाली करवाना पड़ेगा और पुणे व मुम्बई समेत समूचा पश्चिम महाराष्ट्र दसियों हजार सालों तक विकिरणीय प्रदूषण से ग्रस्त रहेगा।

जैतापुर की कोंकणी जनता जो इन सभी दुष्प्रभावों से, खासकर फुकुशिमा के बाद अच्छी तरह वाकिफ है, इस परमाणु संयंत्र के खिलाफ दृढ़तापूर्वक संघर्ष कर रही है। सरकार ने इस संघर्ष को दबाने के लिए एक बर्बर दमन अभियान छेड़ दिया। लाठीचार्ज, धारा 144 और धारा 37(3) को लागू करना जिसके तहत लोगों की सभी किस्म की गोलबंदी पर प्रतिबंध रहेगा, मारपीट, अंधाधुंध गिरफ्तारियां, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर करना (जिसमें एक हत्या का प्रयास भी है!) और अब पुलिसिया गोलीबारी। इस क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के खिलाफ रत्नगिरी जिला छोड़ने का आदेश जारी किया गया। नारायण राणे ऐसी ध मकियां भी दे रहे हैं कि जो लोग जिले में कदम रखेंगे वो जिंदा लौटकर नहीं जाएंगे! पुलिस ने मीडिया को यह भी बताया कि वह इस आंदोलन पर कड़ी नजर रख रही है ताकि 'नक्सलवादियों के साथ संभावित सम्बन्धों' का पता लगाया जा सके, जोकि उसकी चिर-परिचित धमकी है। इस संघर्ष का समर्थन करने वाले इस क्षेत्र के जाने-माने नागरिकों के जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन इन सभी कार्रवाइयों से जैतापुर आंदोलन का हौसला कम नहीं हुआ जो पूरे भारत में विभिन्न ज्वलंत मसलों को लेकर लड़े जा रहे समझौताहीन संघर्षों में एक और मिसाल बनकर शामिल हो रहा है।

पिछले चार सालों के दौरान जब यह आंदोलन चल रहा था, चुप्पी साधकर रहने वाली शिवसेना ने अब इसमें प्रवेश किया क्योंकि वह इसमें कोंकण इलाके में नारायण राणे के दल बदलने के बाद खोई हुई जमीन को फिर से पाने की संभावना देख रही है। राजनीतिक रूप से सचेतनशील जैतापुर जनता को चाहिए कि वह इन अवसरवादियों को, जिन्होंने एनरॉन को अरब सागर में फेंक देने का दावा किया था और सत्ता में आने के बाद बात बदल दी थी, अपने स्वार्थ हितों के लिए इस संघर्ष को गुमराह करने का कोई मौका न दे। परमाणु करार के मुद्दे पर अपने आपको चैम्पियन के रूप में पेश करने वाली सीपीएम, परमाणु ऊर्जा को एक मात्र विकल्प के रूप में चुनने वाले सरकारी के फैसले के खिलाफ मजबूत हो रहे इस मोर्चे पर कहीं नहीं दिख रही है। आंध्रप्रदेश में तेलुगुदेशम जैसी विपक्षी

पार्टियां हालांकि बिजली संयंत्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की गोलीबारी में मारे जाने वाले लोगों पर घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, लेकिन जब एक बार वे सत्ता में आएंगी तो यही काम करेंगे क्योंकि उनका पुराना रिकॉर्ड यही बता रहा है। जहां एक तरफ परमाणु बिजली संयंत्रों का विरोध करने वाली सभी तरह की ताकतों को एकजुट कर एक विशाल आधार पर संघर्ष को व्यापक बनाने की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ अपने स्वार्थ हितों या वोट बैंक की राजनीति के लिए संघर्ष को असल मुद्दे से भटका देने की सभी किस्म की साजिशों के प्रति जनता को सतर्क रहने की जरूरत है।

भाकपा (माओवादी) यह मांग करती है कि जैतापुर परमाणु पार्क समेत भारत में प्रस्तावित सभी परमाणु बिजली संयंत्रों को रद्द किया जाए। परमाणु प्लांट से उत्पन्न होने वाले खतरों से अपनी जिंदगियों और पर्यावरण को बचाने के लक्ष्य से लड़ रही कोंकणी जनता के न्यायपूर्ण आंदोलनों को दबाने के लिए सरकार द्वारा प्रयोग किए जा रहे दमनकारी कदमों का हमारी पार्टी खण्डन करती है। 18 अप्रैल को हुई गोलीबारी की न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की मांग करते हैं। परमाणु-विरोध ी कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाए गए सभी फर्जी मुकदमों, अवैध जिला-बदर आदेश और प्रतिबंधों को वापस लिया जाए। दरअसल रत्नगिरी के लोगों को यह घोषणा करनी चाहिए कि नारायण राणे जैसे लोगों को, जो संसाधनों से समृद्ध कोंकणी तटवर्ती इलाके को साम्राज्यवादियों को बेचने और उनकी आजीविका को तबाह करने पर आमादा हैं, इस इलाके में कदम रखने का कोई अधिकार नहीं है, न कि परमाणु-विरोधी कार्यकर्ताओं को जो उनके लिए निस्वार्थपूर्ण ढंग से लड़ रहे हैं।

आइए, हम यह घोषणा करें कि हमें किस तरह का विकास या ऊर्जा के स्रोत चाहिए यह तय करने का अधिकार देश की जनता को ही होना चाहिए, न कि भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं को जो साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की नमकहलाल नौकरों की तरह काम करते हैं। आइए, हम कोंकणी जनता के परमाणु संयंत्र विरोध ी संघर्ष का दृढ़तापूर्वक समर्थन करें और शासक वर्गों द्वारा बढ़ाए जा रहे बिजली के असुरक्षित और खतरनाक विकल्प के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान का निर्माण करें। हमें तबरेज़ जैसों की कुरबानियों को व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए, जैसा कि रत्नगिरी की जनता ने घोषणा की।

आज हमारा देश इस बात का गवाह है कि चारों तरफ जल-जंगल-जमीन,

सच्चा लोकतंत्र, विकास, आत्मनिर्भरता आदि को केन्द्र में रखते हुए जनता के जुझारू संघर्षों का एक बाढ़ सा आया हुआ है। जनता इन संघर्षों को (कुछ को तो कई सालों से) शांतिपूर्ण और जुझारू तरीके से तथा भीषण दमन के बावजूद भी पीछे न हटते हुए संचालित कर रही है। ये सभी संघर्ष परस्पर प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। वक्त का तकाज़ा है कि इन सभी संघर्षों को एक दूसरे के भाईचारे में और आपसी समर्थन में मजबूती से खड़े होकर एक साझा मंच में लाना चाहिए ताकि साम्राज्यवादियों, भारत के बड़े कॉर्पोरेट दैत्यों तथा सामंती सरदारों के खिलाफ लड़ा जा सके जो इन जन-विरोधी नीतियों को लागू कर रहे हैं और संघर्षरत जनता का दमन कर रहे हैं। भारत के तमाम संघर्षरत जन समुदायों का एक विशाल, समवेत और जुझारू आंदोलन ही इस देश और जनता को दरिद्रता के अंधेरे गर्त से बचा सकता है जिसमें जनता के दुश्मन हमें धकेलने की साजिश रच रहे हैं।

अभय

प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

4 मई 2011

ओसामा नहीं; बल्कि युद्धोन्मादी, कसाई और खून का प्यासा ओबामा ही दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है जिससे विश्व शांति को खतरा है!

अल क़ायदा से नहीं; बल्कि अमेरिकी साम्राज्यवाद से ही सबसे बड़ा खतरा है, न सिर्फ दुनिया के समूचे उत्पीड़ित राष्ट्रों और अवाम को, बल्कि अमेरिकी नागरिकों को भी!

दुनिया का दरोगा सीआईए द्वारा एक कोवर्ट ऑपरेशन में मारे गए ओसामा बिन लादेन की बर्बर हत्या का विरोध करो!

2 मई को अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने हेलिकॉप्टरों से हमला कर अल क़ायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन की हत्या की। पाकिस्तान के एब्बोटाबाद शहर के एक बंगले पर अमेरिका ने रात के अंधेरे में बम गिराए जिसमें ओसामा ने शरण ली हुई थी। पाकिस्तानी सरकार को इस बाबत सूचना तक न देकर अमेरिका ने पाकिस्तान की संप्रभुता का मजाक उड़ाया। उन्होंने पाकिस्तानी राडॉरों को जाम कर दिया और चार हेलिकॉप्टरों को उसके आसमान पर उड़ाया। उस मकान पर धमाके कर अपने 'अचूक ऑपरेशन' को अंजाम दिया। इस हमले में एक महिला और दो अन्य पुरुष भी मारे गए और बताया जा रहा है कि ओसामा की पत्नी भी घायल हो गईं। चालीस मिनट तक चले इस ऑपरेशन में उनकी बच्ची इत्तेफाक से बच गई। निर्दयी ओबामा प्रशासन ने ओसामा के शव के साथ भी संवेदनहीनता बरतते हुए उसे उनके परिवार वालों को सौम्पने की बजाए अरब सागर में फेंक दिया! यह दुनिया भर में मुसलमानों के घावों पर नमक छिड़कने के बराबर है क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इससे वे कितना अपमान और गुस्सा महसूस करेंगे।

ज्यों ही ओबामा ने अल क़ायदा के प्रमुख की मौत की उल्लासपूर्ण घोषणा की, अमेरिकी सरकार की फासीवादी सहयोगियों, यानी साम्राज्यवादी देशों के राष्ट्राध्यक्षों और तीसरी दुनिया के दलाल शासकों ने खुशी से फूले न समाते हुए इसे आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध में एक महान उपलब्धि बताई। भारत के दलाल शासक वर्गों ने मौके का फायदा उठाते हुए आरोप लगाए कि पाकिस्तान अपनी ध रती पर इतने 'खतरनाक आदमी' को शरण दे रहा था। सार्क के एक सदस्य देश पर उसकी संप्रभुता का जरा भी कद्र किए बगैर किए गए इस एकतरफा हमले की निंदा में एक शब्द तक नहीं कहा। इस बात पर एक प्रश्न तक नहीं उठाया कि इस उप-महाद्वीप की धरती पर अमेरिकी युद्ध मशीनरी को क्या काम था। भारत के दलाल शासक वर्गों के इस पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि उन्होंने तीसरी दुनिया में कई बार साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिका और नाटो द्वारा उन देशों की संप्रभुता पर हमला करते हुए किए गए दुराक्रमणकारी युद्धों और दखलंदाजियों का खुला और छिपा समर्थन किया था और वे अमेरिकी साम्राज्यवादियों के आगे हमेशा घुटने टेकते रहे।

2001 में अफगानिस्तान पर नाटो के युद्ध के बाद से आतंक के खिलाफ अपने तथाकथित युद्ध में पाकिस्तानी सरकार का 'समर्थन हासिल करने' के लिए अमेरिका अपनी बाह-मरोड़ और धौंस जमाने की नीति में आए दिन बढ़ोत्तरी कर रही है। इस युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका का विस्तारित पिछवाड़ा बना हुआ है। यह ऑपरेशन इस युद्धोन्मादी धौंसिया के अनगिनत अंधाधुंध हमलों का एक ताजा उदाहरण है और यह खासकर पिछले दस सालों में उसके द्वारा पाकिस्तान में अनगिनत बार की गई बेरोकटोक दखलंदाजियों की धारावाहिकता भर है। पाकिस्तान के दलाल शासक उसके आगे इस कदर नतमस्तक हो गए कि इस प्रकार की आक्रामक कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तानी सरकार ने सभी अंतराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए किए गए इस हमले का खुलकर खण्डन तक नहीं किया। समूचे पाकिस्तान में उठ खड़े हुए व्यापक आंदोलनों से बने दबाव के चलते ही उसने दबी जुबान से यह बात कही कि यह हमला अवैध था और इसे उसकी जानकारी के बगैर अंजाम दिया गया था। लेकिन जब मालिक ने यह कहा कि 'तो क्या है? हम माफी नहीं मांगने वाले हैं' तो इस नौकर का मुंह बंद हो गया। अमेरिकी साम्राज्यवादियों के सामने दुम हिलाते हुए इसने जिस प्रकार पूरी तरह घुटने टेक रखे हैं, इसे देखते हुए यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुनिया का नम्बर एक आतंकवादी ओबामा आए दिन पाकिस्तान के पश्तूनी कबीलाई

इलाकों में अनगिनत ड्रोन हमले कर रहा है जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिकों (जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं) की मौत हो रही है। दर्जनों संभावित खून के प्यासे रेमण्ड डेविस पाकिस्तान की सड़कों पर बेधड़क घूम रहे हैं जिन्हें आम पाकिस्तानी नागरिकों का खून बहाने में जरा भी संकोच नहीं है। फिर भी ये बेशर्म और बेहया पाकिस्तानी शासक वर्ग इस हत्यारे 'नोबेल शांति पुरस्कार विजेता' के लिए लाल कालीन बिछाने में मशगूल हैं जो पाकिस्तानियों के खून से सना है।

कथित तौर पर ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल क़ायदा द्वारा किए गए 9/11 के हमलों के बाद से तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के नेतृत्व में अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने दुनिया भर में वहशियाना मुस्लिम विरोधी दुष्प्रचार शुरू किया। अफगानिस्तान और इराक में दुराक्रमणकारी युद्ध किए। इन अन्यायपूर्ण युद्धों में लाखों आम जनता हताहत हुई। कहने की जरूरत ही नहीं है कि महिलाओं और बच्चों के साथ कितनी बर्बरता बरती गई। आतंकवाद पर युद्ध के नाम पर दुनिया भर में मुसलमानों को निशाने पर लिया गया और उन पर बेहद अत्याचार किए गए। अल क़ायदा को इस 'आतंकवाद' के चेहरे के रूप में दिखाया गया और ओसामा को अमेरिका और दुनिया का नम्बर एक दुश्मन बताकर बढ़ा-चढ़ाकर प्रचारित किया गया। अल क़ायदा को हरेक आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया ताकि मुसलमानों के खिलाफ जारी सभी किस्म के अत्याचारों को जायज ठहराया जा सके। ओसामा और अल क़ायदा के दूसरे नेताओं की धरपकड़ की मुहिम चलाई गई और तथाकथित 'आंतकवाद पर युद्ध' में अरबों डॉलर बहा दिए गए। अफगानिस्तान और इराक में कठपुतली सरकारों की स्थापना की गई और पाकिस्तान की स्थिति करीब-करीब उपनिवेश जैसी बन गई। मुस्लिम जन समुदायों को 'आतंकवाद पर युद्ध' का दैत्य रौंद रहा है जिसमें लाखों लोगों को कुचला जा रहा है।

इतिहास में यह बात कई बार साबित हो चुकी है कि एक नेता को मारकर आप किसी संगठन को खत्म नहीं कर सकते। जब तक कि उसकी बुनियादी वजहों को, जैसे कि इस मामले में अंधाधुंध साम्राज्यवादी शोषण, उत्पीड़न, दखलंदाजी और अपमान हैं, दूर नहीं करेंगे तब तक इसे आप हल नहीं कर सकते। साम्राज्यवादियों के खिलाफ, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों और इज्राएली यहूदीवादियों के खिलाफ मुस्लिम जनता के दिलों में सुलग रहे गहरे आक्रोश और असंतोष की अभिव्यक्ति कई रूपों में सामने आ रही है जिसमें अल क़ायदा एक

है। अरब दुनिया में उठ रहे जन उभार इस आक्रोश की – जो उनके देशों के तानाशाहों और साम्राज्यवाद के खिलाफ है – एक और अभिव्यक्ति है। साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में अल क़यदा जैसे संगठनों द्वारा लागू कुछ तरीकों से आम लोगों को क्षति हो रही है और जिन तरीकों से निर्दोष लोगों की मौत होती है उसका खण्डन करना जरूरी है। लेकिन हमें इन्हें संदर्भ से अलग कर नहीं देखना चाहिए और इन्हें 'अमेरिका से निहायत नफरत करने वाले' कुछ सिरफिरों की कार्रवाइयों के रूप में नहीं देखना चाहिए जैसा कि अमेरिकी सरकार चाह रही है कि उसके नागरिक इसे विश्वास करें। **अगर साम्राज्यवादी दखलंदाजियां और दुराक्रमणकारी युद्ध नहीं होते तो अल क़ायदा नहीं होता। अगर बुश और ओबामा जैसे हत्यारे नहीं होते तो आसामा भी नहीं होता।**

भाकपा (माओवादी) समूची जनता का आह्वान करती है कि वह अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा की गई ओसामा बिन लादेन की बर्बर हत्या का खण्डन करे। हमारी मांग है कि 'आतंकवाद पर युद्ध' के नाम से मुसलमानों पर जारी सभी किस्म के हमलों को फौरन बंद किया जाए।

भाकपा (माओवादी) दृढ़तापूर्वक दोहराती है कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद ही ऐसी एक मात्र विचारधारा है जो दुनिया में हर किस्म के शोषण और उत्पीड़न का अंत कर सकती है। सिर्फ सर्वहारा और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में उत्पीड़ित राष्ट्र और जन समुदाय, जोकि तानाशाहों, 'लोकतंत्र' के नाम पर चलाई जा रही बुर्जुआई तानाशाहियों और साम्राज्यवाद द्वारा दबे-कुचले जा रहे हैं, सम्पूर्ण मुक्ति हासिल कर सकते हैं। अल क़ायदा या उस जैसे दूसरे संगठनों की कितनी भी कार्रवाइयों से साम्राज्यवादियों के दुराक्रमण और दखलंदाजी से आजादी या संप्रभुता जीती नहीं जा सकती। फिलिस्तीनियों के संघर्षों समेत अरब दुनिया में उठ रहे जन-उभार जब तक अपने देशों में साम्राज्यवाद, सामंतवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के खिलाफ जनयुद्धों के रूप में संगठित नहीं होंगे तब तक उनके संगठनों द्वारा जारी अथक संघर्ष और उनकी अनमोल क़ुरबानियां सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंचेंगी।

भाकपा (माओवादी) दुनिया के समूचे उत्पीड़ित राष्ट्रों और जन समुदायों का आह्वान करती है कि वे साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के हमलों का विरोध करें जो अन्यायपूर्ण तरीके से आतंकवाद के खिलाफ तथाकथित

युद्ध शुरू कर दुनिया भर में मुस्लिम जन समुदायों पर हमले कर रहे हैं। **हम अमेरिकी नागरिकों से यह समझने की अपील करते हैं कि तथाकथित आतंकवादी नहीं, बल्कि उनके अपने शासकों द्वारा तीसरी दुनिया के देशों में लागू बर्बर साम्राज्यवादी नीतियां ही अमेरिकी नागरिकों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही हैं; आप्रवासी नहीं, बल्कि पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था ही बारम्बार पैदा होने वाले वित्तीय संकटों के लिए जिम्मेदार है जिससे उनके हित खतरे में पड़ रहे हैं या उनके बीच बेरोजगारी बढ़ रही है। हम अमेरिकी जन समुदायों से आग्रह करते हैं कि वे हमारे सांझे दुश्मन के खिलाफ उसके घरेलू मैदान में अपनी आवाज बुलंद करें। आप अपने देश के शासकों द्वारा दबी-कुचली जा रही जनता के जायज संघर्षों का समर्थन कर खुद की मुक्ति का रास्ता भी सुगम बना सकेंगे। हमें उम्मीद है कि इजारेदार पूंजी के खिलाफ अमेरिका समेत सभी साम्राज्यवादी देशों के मजदूर वर्ग व जन समुदाय के संघर्ष तथा उत्पीड़ित राष्ट्रों और तीसरी दुनिया के जन समुदायों के संघर्ष एकताबद्ध होंगे और एक भारी तूफान का शक्ल ले लेंगे जिसमें हमारा सांझा दुश्मन निश्चित रूप से तबाह हो जाएगा।**

भाकपा (माओवादी) खासतौर पर दक्षिण एशिया के जन समुदायों का आह्वान करती है कि वे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो बलों की बर्बरता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और उनकी फौरन वापसी की मांग करें। पाकिस्तान की धरती पर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के हमलों के खिलाफ तथा साम्राज्यवादी धौंस व दखलंदाजी के खिलाफ संघर्षरत पाकिस्तान के अवाम का समर्थन करें।

आइए, हम सब इस बात को समझ लें कि अमेरिकी साम्राज्यवाद विश्व जनता का नम्बर एक दुश्मन है जिससे विश्व शांति, तीसरी दुनिया के देशों की संप्रभुता और उनके विकास को खतरा है। आइए, हम साम्राज्यवादियों और अपने देशों में मौजूद उनके दलालों को उखाड़ फेंक दें ताकि हम शोषण और उत्पीड़न से पूरी तरह मुक्त जिंदगी जी सकें तथा इज्जत से सिर उठाकर जी सकें।

अभय

प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

11 मई 2011

बिहार में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए माओवादी नेताओं को बिना शर्त रिहा करो!

भाकपा (माओवादी) के केन्द्रीय नेताओं की गिरफ्तारी, देश के शासक गिरोह द्वारा जनता के ऊपर जारी अन्यायपूर्ण युद्ध तथा उसके अंतर्गत ही उत्तरप्रदेश के किसानों पर जारी दमन के खिलाफ

21-22 मई को 'भारत बंद' सफल बनाओ!

29 अप्रैल को बिहार के कटिहार जिले के ग्राम बारसोई में केन्द्रीय तथा आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों की खुफिया संस्थाओं ने सुनियोजित हमला कर हमारी पार्टी के तीन केन्द्रीय कमेटी सदस्यों समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कॉमरेडों में केन्द्रीय कमेटी के सदस्य पुलेंदु शेखर मुखर्जी उर्फ साहेब दा, वारणासी सुब्रह्मण्यम् उर्फ विमल उर्फ श्रीकांत, विजय कुमार आर्य उर्फ जसपाल जी के अलावा बिहार-झारखण्ड स्पेशल एरिया के अंतर्गत उत्तर बिहार-उत्तरप्रदेश रीजनल ब्यूरो सचिव अभिमन्यु उर्फ उमेश यादव, नोखेलाल चौधरी, श्यामजी ऋषि, और आश्रयदाता अनिरुद्ध रविदास शामिल हैं। क्रांतिकारियों की ढूंढ़-ढूंढकर हत्या करने के लिए कुख्यात आंध्रप्रदेश एसआईबी पिछले कुछ महीनों से कॉमरेड सुब्रह्मण्यम् का पीछा कर रही थी। पिछले साल जुलाई के आखिर में वे उसके हमले से बाल-बाल बच गए थे। जब ये कॉमरेड एक बैठक के सिलसिले में इकट्ठे हुए थे, उसी मौके पर केन्द्र-राज्य खुफिया संस्थाओं द्वारा दी गई पक्की सूचना के आधार पर बिहार के एसटीएफ अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया।

पार्टी में साहेब दा, गगन दा, आकाश दा आदि नामों से बुलाए जाने वाले 67 वर्षीय वरिष्ठ माओवादी नेता कॉमरेड पुलेंदु शेखर मुखर्जी पिछले 45 सालों से क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कलकत्ता शहर में पैदा होने वाले साहेब

दा नक्सलबाड़ी आंदोलन की प्रेरणा से उच्च शिक्षा को छोड़कर क्रांतिकारी संघर्ष में कूद पड़े थे और जनयुद्ध को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपने लम्बे क्रांतिकारी सफर में उन्होंने बंगाल समेत देश के विभिन्न इलाकों में क्रांतिकारी आंदोलन के निर्माण के लिए तथा सच्चे क्रांतिकारियों व कम्युनिस्ट संगठनों की एकता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। दमा, पेट का अल्सर आदि बीमारियों से बुरी तरह पीड़ित होकर भी वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहे।

विमल नाम से आंध्रप्रदेश के क्रांतिकारी खेमे में तथा श्रीकांत के नाम से देश भर में पार्टी कतारों में मशहूर कॉमरेड वारणासी सुब्रह्मण्यम् ने विशाखापटनम के आंध्र विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा पूरी करके क्रांतिकारी गतिविधियों में कदम रखा था। 1970 के दशक में उन्होंने रैडिकल छात्र संगठन और बाद में रैडिकल युवा संगठन व सिंगरेणी मजदूर संघ का नेतृत्व किया था। पार्टी के आह्वान पर उत्तर भारत में जाकर उन्होंने वहां के कई राज्यों में क्रांतिकारी आंदोलन के निर्माण के लिए अथक प्रयास किए। अपनी गंभीर अस्वस्थता की परवाह किए बगैर वे विभिन्न स्तरों और विभिन्न मोर्चों पर उल्लेखनीय कार्य करते रहे।

विजय कुमार आर्य के नाम से बिहार की जनता में लोकप्रिय कॉमरेड जसपाल जी एक महत्वपूर्ण कॉमरेड हैं जिन्होंने किसानों और सांस्कृतिक मोर्चे का नेतृत्व करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में उल्लेखनीय कार्य किया। पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से वे विभिन्न मोर्चों और विभिन्न इलाकों में क्रांतिकारी क्रियाकलापों का नेतृत्व करते रहे और जन आंदोलनों का निर्माण करते रहे।

बेअंत क्रूरता के लिए बदनाम सीआईए, मोस्साद जैसे विदेशी खुफिया संगठनों द्वारा प्रशिक्षित भारतीय खुफिया अधिकारी क्रांतिकारी आंदोलन का लम्बे समय से नेतृत्व करने वाले कॉमरेडों का पीछा करते हुए उन्हें पकड़ रहे हैं। दरअसल अमेरिका की सीआईए और एफबीआई ही हमारे देश की खुफिया संस्थाओं को चला रही हैं। पिछले दो सालों में पकड़े जाने वाले अग्रणी कॉमरेडों में पटेल सुधाकर, शाखामूरी अप्पाराव और आजाद की खुफिया संस्थाओं ने हत्या कर दी। कुछ और केन्द्रीय व राज्य स्तर के नेतृत्वकारी कॉमरेडों को गिरफ्तार कर जेलों में कैद किया। इन्हें अलग-अलग राज्यों के झूठे मामलों में फंसाकर लम्बे समय तक बिना किसी जमानत के जेलों में पड़े रहने पर मजबूर किया जा रहा है। झूठी गवाहियां दिलवाकर कठोर सजाएं और आजीवन सजाएं दी जा रही हैं। विभिन्न राज्यों के

जेलों में बंद महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को और ज्यादा अमानवीयता के साथ शारीरक और मानसिक यातनाओं का शिकार बनाया जा रहा है। जेलों में गंभीर बीमारियों से पीड़ित सुशील रॉय, शीला दीदी, नारायण सान्याल, कोबाड गांधी, अमिताभ बाग्ची आदि कॉमरेडों को चिकित्सा सुविधाओं से वंचित कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

तीखे संकट से ग्रस्त विश्व अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए साम्राज्यवादी पिछड़े देशों में संसाधनों की लूटखसोट में तेजी ला रहे हैं। जिन-जिन देशों से वे अपने हितों को जरा भी खतरा महसूस करते हैं उनके खिलाफ वे धौंस व धमकियों पर उतारू हो रहे हैं। जो उनकी बात नहीं मानते उन पर एकतरफा बमबारी करते हुए अन्यायपूर्ण युद्ध कर रहे हैं। भारत के सामंती व दलाल पूंजीपति शासक वर्ग यह झूठा दावा करते हुए कि देश में इस संकट का कोई प्रभाव नहीं है, दिन-ब-दिन संकट में गहरे फंसते जा रहे हैं। साम्राज्यवादी लूटखसोट के लिए सारे दरवाजे खोलते हुए नव उदार नीतियों पर निर्लज्जता से अमल कर रहे हैं। केन्द्र व राज्यों की सरकारें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ लाखों करोड़ों रुपए के एमओयू कर देश की प्राकृतिक सम्पदाओं को औने-पौने दामों में बेच रही हैं। एसईजेड, परमाणु रिएक्टरों की स्थापना, थर्मल बिजली परियोजनाएं, भारी बांध, एक्सप्रेस हाईवे, अभयारण्य आदि योजनाओं के नाम पर जनता से जमीनें बलपूर्वक छीन रही हैं। जल-जंगल-जमीन का, कुल मिलाकर पर्यावरण का विनाश करते हुए जनता को, खासकर आदिवासियों को बेघरबार कर रही हैं। इन नीतियों की आड़ में ही मंत्री, मुख्यमंत्री और नौकरशाह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व घोटाले करते हुए लाखों करोड़ रुपए डकार रहे हैं। इस तरह जमा किए गए काले धन को स्विस बैंकों में छुपा रहे हैं। इस तरह वे मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों और मध्यम वर्ग की जिंदगी दूभर बना रहे हैं। जहां एक ओर टाटा, बिड़ला, अंबानी, जिंदल, मित्तल, महेंद्रा, रुइया, निको जयस्वाल, सन नेटवर्क आदि अपनी सम्पत्तियों को हजारों, लाखों करोड़ों में बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की 77 फीसदी जनता रोजाना 20 रुपए से भी कम आमदनी से भूखों मर रही है। भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, विस्थापन, बीमारियां, कुपोषण आदि समस्याओं के भंवर में फंसकर देश की जनता छटपटा रही है। इसका विरोध करने वाली और आंदोलन करने वाली जनता का लौह पैरों से रौंदने के लिए शासक लाखों पुलिस व अर्धसैनिक बलों का प्रयोग कर रहे हैं। नागरिक व जनवादी अधिकारों का हनन करते हुए काले कानून बना रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए का जन धन पानी की तरह बहा रहे हैं ताकि जनता का

दमन करने वाली मशीनरी के पंजों की धार बढ़ाई जा सके।

लुटेरे शासक वर्गों के प्रति जनता में फूट पड़ रहे असंतोष और आक्रोश से माओवादी आंदोलन को मजबूती मिल रही है, इस सचाई को चिन्हित कर शासक वर्गों ने सुनियोजित तरीके से यह प्रचार शुरू किया कि 'माओवादी आंदोलन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है'। माओवादी आंदोलन को हिंसावाद के रूप में तथा माओवादी पार्टी को आतंकवादी संगठन के रूप में चित्रित करते हुए बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार मुहिम शुरू कर दी। अपनी साम्राज्यवाद-परस्त नीतियों को लागू करने तथा उसके अंतर्गत संसाधनों की लूटखसोट के रास्ते में माओवादी पार्टी को बहुत बड़ी बाधा मानते हुए उन्होंने माओवादी पार्टी का जड़ से सफाया करने के लक्ष्य से खासकर पिछले दो सालों से एक बेहद पाशविक व फासीवादी हमला शुरू किया जिसका नाम 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' रखा गया है। माओवादी आंदोलन के इलाकों में विभिन्न स्तरों पर विकसित हो रही वैकल्पिक जन राज्यव्यवस्था का भी गला घोंटने के लक्ष्य से जारी इस हमले में जनवरी 2011 से तेजी लाई गई और इसे अब 'ऑपरेशन ग्रीन हंट-2' कहा जा रहा है। इसके तहत पुलिस, अर्धसैनिक व विशेष बलों तथा उनके द्वारा बनाए गए प्रति-क्रांतिकारी गुण्डा गिराहों ने आंदोलन के क्षेत्रों में फर्जी मुठभेड़, कत्लेआम, गांव-दहन, लूट, महिलाओं पर बलात्कार, गिरफ्तारी और बर्बर यातना का सिलसिला तेज कर दिया। शासक वर्ग छत्तीसगढ़ में सेना की तैनाती की तैयारियां पूरी करके माड़ क्षेत्र में 800 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। माड़ क्षेत्र और छत्तीसगढ़-ओड़िशा की सीमा पर दो सैन्य प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने जा रहे हैं। वायु सेना के बेस स्थापित करने की तैयारियों के अलावा 'आत्मरक्षा' के नाम पर उसे हमले करने का अधिकार भी दे दिया गया है।

दण्डकारण्य (छत्तीसगढ़) के चिंतलनार इलाके में 11 से 16 मार्च तक 350 कोबरा बलों, कोया कमाण्डों बलों और सैकड़ों एसटीएफ बलों ने मोरपल्ली, तिम्मापुरम और ताड़िमेटला गांवों पर भारी तबाही मचाकर 300 घरों में आग लगा दी। हजारों कुंटल अनाज जला दिया। घर-घर को लूटा। तीन ग्रामीणों की हत्या की। दो ग्रामीणों को लापता कर दिया। पांच महिलाओं के साथ बलात्कार किया। करीब 50 ग्रामीणों के साथ बुरी तरह मारपीट की। इसकी जांच-पड़ताल के लिए जा रहे जनवादियों, रिपोर्टिंग के लिए जा रहे मीडियाकर्मियों तथा पीड़ितों को राहत-सामग्री ले जा रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर फासीवादी मुख्यमंत्री रमनसिंह,

शासक वर्गों के वफादार कुत्ते डीजीपी विश्वरंजन, बस्तर आईजी लांगकुमेर और दंतेवाड़ा एसएसपी कल्लूरी ने सोची-समझी साजिश के तहत सलवा जुडूमी गुण्डों से हमले करवाकर उन्हें उस इलाके में जाने से रोक दिया। इन घटनाओं को लेकर प्रदेश और देश में बड़े पैमाने पर हुए प्रचार की पृष्ठभूमि में रमनसिंह को ताड़िमेटला गांव के दौरा करने पर मजबूर होना पड़ा। उस मौके पर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री की सभा चल ही रही थी, तो दूसरी तरफ कोया कमाण्डो दरिंदों ने गांव के दूसरे कोने में फिर 15 घरों में लूटपाट मचाई और कुछ लोगों के साथ मारपीट कर एक महिला के साथ बलात्कार किया। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में फासीवादी आतंक कितना भयावह रूप धारण कर चुका है। इस तरह के हमले बस्तर क्षेत्र के साथ-साथ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में आए दिन किए जा रहे हैं। इसके अलावा इन इलाकों में गोपनीय हत्यारे दस्तों को उकसाकर जन संगठन कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्याएं करवाई जा रही हैं। खासतौर पर महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार और हमले करवाए जा रहे हैं। 19 अप्रैल को नारायणपुर जिले के चिनारी गांव में 14 वर्षीय किशोर रजनू की हत्या कर मुठभेड़ की कहानी गढ़ दी गई। दण्डकारण्य में आए दिन चल रहे भीषण दमनचक्र के ये चंद ताजा उदाहरण भर हैं।

14 मार्च को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस ने तीन महिलाओं समेत छह माओवादी कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या की। कुछ अन्य कॉमरेडों को गिरफ्तार किया। झारखण्ड सरकार माओवादी नेताओं की हत्या करने के बुरे मंसूबे से हजारों पुलिस व अर्धसैनिक बलों को उतारकर हमले कर रही है। अंधाधुंध गिरफ्तारियां चला रही है। विस्थापन और जबरिया जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलनरत जनता पर फासीवादी हमले कर रही है। ओड़िशा में दलाल नवीन पटनायक सरकार ने राज्य के चारों कोनों में फर्जी मुठभेड़ों का सिलसिला चलाकर पिछले चार महीनों में ही 25 से ज्यादा माओवादी कार्यकर्ताओं, खदान-विरोधी कार्यकर्ताओं और आम लोगों की हत्या की। मृतकों में 12 वर्षीय बालिका जांगा और कुछ अन्य किशोरियां भी शामिल हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पटनायक सरकार की दमनकारी नीतियों ने कितना घिनौना रूप ले लिया है।

पिछले 34 सालों से जारी अपने फासीवादी शासन को किसी भी तरह टिकाए रखने के लक्ष्य से पश्चिम बंगाल की सीपीएम सरकार ने चुनावों के पहले जनता और माओवादियों पर हमले तेज किए। पुलिस व अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ

अपनी गुण्डा वाहिनी – हर्मद बाहिनी के जरिए वह अमानवीय हत्याकाण्डों और जघन्य अपराधों को अंजाम दे रही है। नेताई हत्याकाण्ड, शशधर महतो की हत्या जैसी घटनाएं चंद ताजा उदाहरण हैं। गिरफ्तार माओवादी नेताओं पर, खासकर महिलाओं पर वह अमानवीय हिंसा कर रही है। हाल ही में मेदिनीपुर जेल में हड़ताल कर रहे राजनीतिक कैदियों पर उसने पुलिस बलों को उकसाकर हमला करवाया। राज्य में माओवादी आंदोलन का सफाया करने का ढिंढ़ोरा पीटने वाली आंध्रप्रदेश सरकार ने अपने पुलिस बलों को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी रखा हुआ है। माओवादी नेताओं को पीछा कर मार डालने की नीतियों में उसने तेजी लाई। पृथक तेलंगाणा राज्य के लिए आंदोलनरत जनता का वह दमन कर रही है। महाराष्ट्र सरकार आदिवासी आंदोलन के क्षेत्रों में सी–60 कमाण्डों बलों के सहारे दमनचक्र को लगातार तेज कर रही है। शहरी इलाकों में माओवादी नेताओं और जनवादियों को गिरफ्तार कर उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसा रही है।

यह फासीवादी हमला सिर्फ माओवादी आंदोलन पर ही नहीं चल रहा है। लुटेरे शासक वर्ग हर जनवादी आंदोलन पर फासीवादी दमन का ही प्रयोग कर रहे हैं। पिछले माह 18 तारीख को महाराष्ट्र के जैतापुर में परमाणु बिजली परियोजना के खिलाफ आंदोलनरत जनता पर पुलिस ने गोली चलाकर तबरेज़ नामक एक प्रदर्शनकारी की जान ली। और अब उत्तरप्रदेश में ग्रेटर नोइडा से आग्रा तक प्रस्तावित एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के लिए अपनी जमीनें देने से इनकार करने वाले किसानों पर पुलिस बल पाशविक दमनचक्र चला रहे हैं। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए। कम से कम दो किसान मारे गए। पुलिसिया जुल्म का भट्टा–परसौल और उसके आसपास के गांवों की जनता ने बहादुराना तरीके से प्रतिरोध किया। इसमें दो पुलिस वाले मारे गए, जबकि कुछ अन्य अधिकारी व पुलिस वाले घायल हो गए। अगले दिन आग्रा, अलीगढ़ आदि इलाकों में भी जनता ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। पुलिस जुल्म का प्रतिरोध किया। इस बहाने फासीवादी मायावती सरकार उत्तरप्रदेश के किसानों पर तीव्र दमन चला रही है। गांवों की नाकेबंदी कर जनता के ऊपर कई अत्याचार कर रही है।

प्यारे लोगो! जनवाद के प्रेमियो! देशभक्तो! उपरोक्त फासीवादी दमनात्मक कार्रवाइयां और माओवादी नेताओं की गिरफ्तारियां ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से

जारी उस युद्ध का हिस्सा हैं जिसे देश का शासक गिरोह – यानी सोनिया–मनमोहनसिंह–चिदम्बरम गिरोह साम्राज्यवादियों के साथ सांठगांठ से देश की जनता के खिलाफ चला रहा है। विश्व पूंजीवादी व्यवस्था जिस तीव्र संकट में फंसी हुई है, उसका प्रभाव हमारे देश के सभी क्षेत्रों में पड़ रहा है और इसी पृष्ठभूमि में इस राजनीतिक दमन, हत्याकाण्डों और मानवाधिकारों पर हमलों को समझना चाहिए। माओवादी आंदोलन का जड़ से सफाया कर लुटेरी सरकारों की साम्राज्यवाद–परस्त और जन–विरोधी नीतियों को बेरोकटोक जारी रखने की साजिश का ही हिस्सा है यह सब। यह एक ऐतिहासिक सचाई है कि दमन प्रतिरोध को जन्म देता है। सोनिया–मनमोहनसिंह–चिदम्बरम शोषक शासक गिरोह हत्याओं, गिरफ्तारियों और दमनात्मक मुहिमों से जन आंदोलनों और क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलने का जो सपना देख रहा है वह दिवास्वप्न ही साबित होगा। कॉर्पोरेट घरानों को अंधाधुंध मुनाफा पहुंचाकर किसानों व आदिवासियों को बेघरबार करने वाला 'विकास' का ढोंगी नमूना देशवासियों पर थोपते हुए, देश को बेचने वाले ये सामंती, दलाल पूंजीपति शासक वर्ग और उनको चलाने वाले साम्राज्यवादी ही बहुत बड़े दुश्मन हैं जिनसे हमारे देश के विकास, स्वावलम्बन, सम्प्रभुता, स्वतंत्रता और जन कल्याण को भारी खतरा है। हमारी केन्द्रीय कमेटी का यह आह्वान है कि इन दुश्मनों को उखाड़ फेंकने के लक्ष्य से हमारी पार्टी की अगुवाई में जारी जनयुद्ध तथा नई जनवादी क्रांति में आप सब बड़े पैमाने पर गोलबंद हों। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, जनवादियों और शांति वार्ता की हिमायत करने वालों से हमारी केन्द्रीय कमेटी अपील करती है कि वे हमारे आंदोलन के इलाकों का दौरा कर यहां पर हो रहे अमानवीय दमन और हत्याकाण्डों की खुद जांच–पड़ताल करें। हमारी केन्द्रीय कमेटी यह आग्रह करती है कि 'दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र' कहलाने वाले इस देश के बीचोबीच बेहद गरीब जनता पर, आदिवासियों पर हो रही सरकार की फासीवादी हिंसा से जुड़ी सचाइयां देश की तमाम जनता के सामने उजागर करें।

हमारी केन्द्रीय कमेटी जनता और जनवादियों का यह आह्वान करती है कि वे इन गिरफ्तारियों, कत्लेआमों, पुलिसिया जुल्म, तबाही, लूटपाट, अत्याचारों, दुष्प्रचार, राज्य के फासीकरण, जबरिया जमीन अधिग्रहण और यूएपीए जैसे काले कानूनों का खण्डन करें और इसके खिलाफ एकजुटता से संघर्ष करें। सरकार से हमारी मांग है कि माओवादी नेताओं को बिना शर्त रिहा किया जाए। सरकारी फासीवादी आतंक का एकजुटता और जुझारू तरीके से प्रतिरोध करना ही एक मात्र

रास्ता है, अतः हमारी केन्द्रीय कमेटी तमाम क्रांतिकारी जनता का यह आह्वान करती है कि वह इसके लिए हिम्मत के साथ आगे आए। हम स्पष्ट करते हैं कि पार्टी और पीएलजीए के नेतृत्व में जारी जन प्रतिरोधी आंदोलन को और ज्यादा तेज कर तथा इसमें हजारों, लाखों की संख्या में गोलबंदी से ही इस हमले को पराजित किया जा सकता है।

हमारी केन्द्रीय कमेटी देश की तमाम जनता से अपील करती है कि माओवादी नेताओं की गिरफ्तारी, जनता के ऊपर देश के शासक गिरोह द्वारा जारी युद्ध और उत्तरप्रदेश के किसानों पर जारी दमन के खिलाफ 21-22 मई को 48-घण्टों का 'भारत बंद' सफल बनाया जाए। यह बंद प्रमुख रूप से 6 राज्यों - झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र के तीन जिलों - गढ़चिरौली, चंद्रपुर और गोंदिया में, मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में तथा उत्तरप्रदेश के बिहार के सीमावर्ती जिलों में लागू किया जाएगा। अन्य राज्यों में विभिन्न रूपों में विरोध कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हालांकि हम चिकित्सा सेवाओं, छात्रों की परीक्षाओं व साक्षात्कार जैसी आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखेंगे।

अभय

प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

13 जून 2011

Hkkjrh; Økfr ds ofj"B usrk

vkSj mRihfM+r turk ds l;kjs usrk

dkejsM txnh'k ekLVj mQZ Hkwis'k th dks

fcuk 'krZ fjgk djks!

dkejsM txnh'k ekLVj dh fxj¶rkjh

vkSj Økfrdkjh vkanksyu ij

'kks"kd oxksZ }kjk tkjh Qklhoknh neu ds f[kykQ

23 twu dks ^Hkkjr cUn* lQy cukvks!

बिहार की शोषित जनता के बीच कॉमरेड 'जगदीश मास्टर' के नाम से लोकप्रिय, भाकपा (माओवादी) के पोलिटब्यूरो सदस्य और पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक कॉमरेड भूपेश जी को 11 जून को पुलिस ने बिहार के गया जिले के गुरार से गिरफ्तार किया। 72 साल के वयोवृद्ध और करीब दस सालों से गंभीर अस्वस्थता से जूझते हुए भी जनता के बीच, जन संघर्षों को अपनी सांस बनाकर काम कर रहे कॉमरेड भूपेश जी को सादे कपड़ों में आए बिहार व केन्द्रीय फासीवादी खुफिया गुण्डों ने उस समय उठा लिया जब वे इलाज के सिलसिले में जा रहे थे। अपने ही संविधान व कानून का, जिसका पालन करने का वे दावा करते नहीं थकते, घोर उल्लंघन करते हुए उन्होंने कॉमरेड भूपेश जी को 24 घण्टे बीत जाने पर भी अदालत में पेश न करके उन्हें तरह–तरह की यातनाओं और प्रताड़नाओं का शिकार बनाया।

पार्टी कतारों में 'कॉमरेड भूपेश' के नाम से सुविख्यात कॉमरेड जगदीश मास्टर पिछले चार दशकों से क्रांतिकारी आंदोलन के निर्माण के लिए अथक प्रयास करने वाले एक महत्वपूर्ण नेता हैं। जब वे शिक्षक की नौकरी कर रहे थे तब उनका परिचय भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के महान नेताओं में से एक शहीद कॉमरेड कन्नाई चटर्जी के साथ हुआ था। उनकी प्रेरणा से वे क्रांतिकारी राजनीति में आ गए और 1970 के दशक के शुरूआती दौर से

उन्होंने पेशेवर क्रांतिकारी के रूप में काम करना शुरू किया। सामंती शोषण और उत्पीड़ित जातियों के लोगों पर अगड़ी जातियों की सामंती सेनाओं के बर्बर हमलों के लिए बदनाम बिहार में उन्होंने शोषित जनता के जुझारू नेता बनकर कई जन संघर्षों का नेतृत्व किया। अब इस गिरफ्तारी से नव सामंत नीतिशकुमार और सोनिया–मनमोहनसिंह–चिदम्बरम गिरोह यह मंशा जाहिर कर रहे हैं कि वे बिहार के किसान समुदायों को फिर से अंधकार में ले जाना चाहते हैं। जमींदारों से हजारों एकड़ जमीन जब्त कर भूमिहीन व गरीब किसानों में बांटने तथा उन पर होने वाले सामाजिक उत्पीड़न का मुकाबला कर आत्मसम्मान के साथ सिर उठाकर जीने की स्थिति निर्मित करने में कॉमरेड भूपेश जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अपनी वृद्धावस्था और बुरी तरह बिगड़ते स्वास्थ्य की परवाह किए बिना, दुश्मन के हाथों पड़ने तक जनता के बीच ही रहकर जनता, काडरों और नई पीढ़ियों में प्रेरणा और उत्साह का संचार करने वाले कॉमरेड भूपेश जी की गिरफ्तारी एक बड़ा सद्मा है।

देश के शासक वर्ग माओवादी क्रांतिकारी आंदोलन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हुए उसका नेतृत्व कर रहे केन्द्रीय व राज्य स्तर के नेताओं को गिरफ्तार करना, मुठभेड़ के नाम से गोली मार देना जैसी करतूतों पर उतारू हैं। खासकर पिछले दो सालों से जारी 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के नाम से जारी देशव्यापी हमले के अंतर्गत एक तरफ महत्वपूर्ण नेताओं को निशाने पर लेकर उन पर वार करते हुए ही दूसरी तरफ आंदोलन के इलाकों में फासीवादी दमनचक्र चला रहे हैं। मुठभेड़ों के नाम से निहत्थे लोगों की अंधधाधुंध हत्याएं करना, गांवों को जलाना, महिलाओं पर अत्याचार, सम्पत्तियों को तबाह करना, लूटपाट, मारपीट, झूठे मामलों में फंसाकर सालों साल बिना सुनवाई या जमानत के जेलों में सड़ाना आदि मध्ययुगीन क्रूरतापूर्ण दमनात्मक तरीकों और नात्सी किस्म के फासीवादी स्वरूपों में यह हमला – ऑपरेशन ग्रीन हंट – चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, बंगाल, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के वे हिस्से जहां क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है, पुलिस व अर्धसैनिक बलों के लौह जूतों तले रौंदे जा रहे हैं।

जनवरी 2011 से जारी ऑपरेशन ग्रीनहंट के कथित दूसरे चरण में

सरकारें एक ओर गांवों और जनता पर भीभत्सपूर्ण हमले करते हुए ही दूसरी ओर वे इस हमले के खिलाफ अपनी आवाज उठाने वाले लेखकों, कलाकारों, जनवादियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का गला घोंटने के लिए चरम फासीवादी हमलों पर उतारू हैं। छत्तीसगढ़ में जन डॉक्टर व मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर बिनायक सेन को आजीवन कारावास की सजा देना; चिंतलनार क्षेत्र में सरकारी बलों द्वारा मचाए गए बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रत्यक्ष जायजा लेने के लिए जा रहे स्वामी अग्निवेश आदि लोगों पर हमले; पीयूसीएल पर प्रतिबंध लगाने की धमकियां; लेखकों और पत्रकारों पर झूठे केस दायर करना व हमले करना; ओड़िशा में कॉर्पोरेट कम्पनियों द्वारा जारी जबरिया जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलनरत जनता पर दमनचक्र; मुठभेड़ के नाम पर खदान–विरोधी कार्यकर्ताओं को गोली मार देना; बिहार में जनता पर गोलीबारी व हत्याएं; झारखण्ड में बेजा कब्जा हटाने के नाम पर जनता को विस्थापित करने वाले सरकारी फैसलों का विरोध करने वाली जनता पर गोलीबारी व जुल्म; पंजाब में पत्रिका सम्पादक व जन संगठन कार्यकर्ता हरविंदरसिंह जलाल की गिरफ्तारी और यातनाएं; उत्तरप्रदेश में शासक वर्गों के 'विकास' के ढोंगी नमूने का विरोध करने पर किसानों का दमन; महाराष्ट्र में दलित आंदोलन का कार्यकर्ता व पत्रिका सम्पादक सुधीर धवळे को राजद्रोह के मामले में गिरफतार करना; आंध्रप्रदेश में पृथक तेलंगाना आंदोलन पर विभिन्न तरीकों में जारी दमनचक्र आदि इसके कुछ उदाहरण भर हैं।

देश की सम्पदाओं को साम्राज्यवादियों व दलाल पूंजीपतियों की कॉर्पोरेट कम्पनियों के हवाले करने पर तुले हुए भारत के शासक वर्गों ने इस राह में सबसे बड़ी बाधा के रूप में खड़े माओवादी आंदोलन का जड़ से उन्मूलन करने के इरादे से जारी इस अन्यायपूर्ण युद्ध में अब सेना को उतार दिया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सैन्य बलों को 'प्रशिक्षण' के नाम पर मैदान में उतरा जा चुका है। कथित रूप से देश की सीमाओं पर शत्रु सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए निर्मित भारतीय सेना को अब देश के बीचोबीच देश की जनता के खिलाफ जारी युद्ध में झोंक दिया जा रहा है। सैन्य बलों के प्रशिक्षण के नाम पर बस्तर के माड़ इलाके में 750 वर्ग किलोमीटर जमीन देने वाले रमनसिंह सरकार के फैसले से माड़ क्षेत्र का पांचवां हिस्सा हड़प लिया जाएगा। दूसरी ओर कॉर्पोरेट कम्पनियां हजारों एकड़ जमीनों को

निगलने वाली परियोजनाओं के साथ आगे आ रही हैं। इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन के इलाकों में जनता को बलपूर्वक विस्थापित करने वाली साजिशें बड़े पैमाने पर जारी हैं।

एक ओर देश में अंधाधुंध भ्रष्टाचार–घोटालों में लिप्त कांग्रेस, भाजपा समेत सभी शासक वर्गीय पार्टियों के अनैतिक नेता, कॉर्पोरेट डकैत और बड़े अधिकारी हजारों, लाखों करोड़ रुपए डकारकर देश की जनता के गुस्से व नफरत का शिकार बन रहे हैं। महंगाई, भुखमरी, अकाल, महम्मारी, विस्थापन, संसाधनों का दोहन आदि समस्याओं से देश की करोड़ों जनता दो–चार है। जनता की एक भी बुनियादी समस्या का हल न करने वाली सरकारें जायज जन आंदोलनों को कुचलने के लक्ष्य से फासीवादी दमन व हत्याकाण्डों पर उतारू हैं। वहीं दूसरी तरफ, जनता के लिए निःस्वार्थ, समर्पित व अविराम परिश्रम करने वाले क्रांतिकारी नेताओं को जेलों में ठूंस रही हैं और उनकी हत्याएं कर रही हैं। कॉमरेड भूपेश जी की गिरफ्तारी इसी सिलसिले का हिस्सा है।

भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी देशवासियों का आह्वान करती है कि कॉमरेड भूपेश जी की गिरफ्तारी के खिलाफ तथा क्रांतिकारी आंदोलन पर जारी शासक वर्गों के फासीवादी दमनचक्र के खिलाफ 23 जून को 24 घण्टों का 'भारत बंद' सफल बनाया जाए। यह बंद मुख्य रूप से छह राज्यों – झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र के तीन जिलों – गढ़चिरौली, चंद्रपुर व गोंदिया जिलों, उत्तरप्रदेश के बिहार की सीमा से लगे हुए जिलों तथा मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में आयोजित होगा। अन्य राज्यों में विभिन्न रूपों में विरोध कार्यक्रम होंगे। चिकित्सा सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं, छात्रों की परीक्षाओं और साक्षात्कार आदि को हम बंद से मुक्त रखेंगे।

vHk;

iloDrk] dlUæh; delVh

Hkkjr dh dE;qfuLV ikVh ¼ekvksoknh½

15 जून 2011

vkij'ku xhu gV d nlj pj.k d rgr

NRrhlx< vkj vkfM'kk e

iLrkfor u, ljdkjh vkØe.k dk edkcyk djk!

n'k dk yVu&[klkVu d y{; l tkjh

gj Qklhoknh vkØe.k dk

n'k dh LokfHkekuh turk viu cgknjkuk ifrjk/k l gjkdj jgxh!

14 जून 2011 को केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने छत्तीसगढ़ और ओड़िशा के मुख्यमंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर इन दो राज्यों में 'वामपंथी उग्रवाद' का खात्मा करने के लिए एक नया आक्रमण शुरू करने की घोषणा की। हमेशा दोहराए जाने वाले अपने दोहरे मंत्र – 'विकास और पुलिस कार्रवाई' की आड़ में गृहमंत्री ने यह आश्वासन देते हुए कि इन दो राज्यों को बर्बर आक्रमण चलाने में पूरा समर्थन दिया जाएगा, उन्हें पूरा जोर लगाकर आगे बढ़ने को कहा। ओड़िशा के खून के प्यासे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, जिसके हाथ उन सैकड़ों लोगों के खून से सने हैं जो 'विकास के भगवान' के लिए इंसानी बलि के तौर पर चढ़ाए गए थे, अब हेलिकॉप्टरों की मांग की है ताकि बेचारे आदिवासियों पर बमबारी की जा सके। रमनसिंह जो संभवतः इतिहास में एक ऐसे भगवा फासीवादी के रूप में दर्ज हो जाएगा जिसने दुनिया के प्रचीनतम मानव समुदायों में से एक बस्तर के आदिवासियों के लिए मौत की घंटियां बजा दीं, ने अपने राज्य में बढ़ रहे बहादुराना सशस्त्र प्रतिरोध से बने दबाव को धुंधलाते हुए माओवादियों के सफाए को लेकर ऊंचे–ऊंचे दावे किए। कुछ दिन पहले जून महीने के पहले सप्ताह में (प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नेतृत्व में हुई 'माओवाद–प्रभावित' राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक और बैठक के बाद एक सप्ताह के अंदर ही) आंध्रप्रदेश और ओड़िशा की सरकारों ने माओवादियों का सफाया करने की मंशा से एक बड़ा अभियान चलाने की घोषणा की जिसके बारे में यह बताया गया कि वह तीन माह तक

चलेगा। उन्होंने घोषणा की कि वे आधुनिक तकनीक और नए तरीकों व दावपेंचों का इस्तेमाल करेंगे जिसके तहत माओवादियों पर 'पानी, हवा और जमीन' से वार किया जाएगा। हेलिकॉप्टरों का भी इस्तेमाल करने की संभावना जताई। और अब यह जगजाहिर है कि छत्तीसगढ़ में 'प्रशिक्षण' के बहाने सेना को उतारा जा चुका है।

यह घोषणा उस समय की जा रही है जिसके कुछ ही दिन पहले सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) ने बस्तर (छत्तीसगढ़) क्षेत्र में मौजूद रावघाट खदानों के निजीकरण की घोषणा की। और यह उस समय की जा रही है जबकि ओड़िशा की जनता ने पोस्को द्वारा किए जा रहे जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जबर्दस्त प्रतिरोध खड़ा किया हुआ है, जहां 'भारत का सबसे बड़ा विदेशी पूंजीनिवेश' किया जा रहा है (जो दरअसल 'इतिहास में भारत के प्राकृतिक संसाधनों को हड़पने की सबसे बड़ी कोशिश' है।) और यह घोषणा ऐसे वक्त की जा रही है जिसके चंद दिन पहले हमारी पीएलजीए (जन मुक्ति गुरिल्ला सेना) द्वारा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के उन इलाकों में जो दण्डकारण्य में आते हैं, लगातार हमलों का सिलसिला छेड़ा गया था। शासक वर्गों ने इन राज्यों की सीमाओं पर अपने हमले को केन्द्रित किया है ताकि उनकी लूटखसोट के लिए कोई सीमा न रह सके तथा अपनी लूटखसोट का दायरा निर्बाध रूप से बढ़ाया जा सके। (उदाहरण के लिए पूर्व में जैसा ओड़िशा और झारखण्ड के बीच; पश्चिम बंगाल और झारखण्ड के बीच; छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच; और छत्तीसगढ़–आंध्रप्रदेश–महाराष्ट्र के बीच चलाया गया था।) अब साफ जाहिर है कि काज और कारण के बीच क्या सम्बन्ध है।

दरअसल सच्चाई यह है कि यह घोषणा इस पृष्ठभूमि में की गई है कि भारत की समूची जनता ने – उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक, खासकर मध्य भारत में – दलाल शासक वर्गों के 'विकास के नमूने' को सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार, झारखण्ड, ओड़िशा, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत समूचे देश में करीब–करीब हर उस परियोजना के खिलाफ जो देश को बेच डालने और लूटने–खसोटने की लिए लाई गई हो, बढ़ रहा प्रतिरोध इसका ऐसा स्पष्ट उदाहरण है जिसे सिर्फ वो लोग देख नहीं पाते हैं जिन्होंने अपनी

आंखों पर 'विकास' का दृष्टिहीन चश्मा पहन रखा हो। और हवा में तैर रहे 'जल–जंगल–जमीन पर अधिकार हमारा है' और 'ढोंगी विकास की योजनाओं को बंद करो' के नारे सिर्फ वो लोग सुन नहीं पाते हैं जिनके कानों में 'पुलिस कार्रवाई' के ध्वनिरोधक प्लग लगे हों।

दरअसल अपने देश को गिद्ध जैसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े दलाल पूंजीपतियों से बचाने के लिए देश के निर्धनतम लोगों द्वारा जारी तमाम किस्म के प्रतिरोधी संघर्षों – हिंसात्मक और अहिंसात्मक; जुझारू और शांतिपूर्ण; सशस्त्र और निःशस्त्र संघर्षों – पर देश का हर देशभक्त इंसान गर्व करेगा। और न सिर्फ अपने बाल–बच्चों के लिए, बल्कि देश के हर नागरिक को इज्जत से जीने का अधिकार हासिल करने के लिए उनके द्वारा दी जा रही कुरबानियों को तहेदिल से नमन करेगा। लेकिन भारत के शासक वर्ग इसे उलटा देख रहे हैं। इन प्रतिरोधी संघर्षों को लेकर वे बौखलाए हुए हैं, सहमे हुए हैं, घिरे हुए महसूस कर रहे हैं और गले तक गुस्साए हुए हैं क्योंकि इससे उन्हें उन 'वायदों' को पूरा करने में दिक्कत आ रही है जो उन्होंने अपने साम्राज्यवादी आकाओं और अपने वर्ग से कर रखे हैं कि वे देश की तमाम सम्पदाओं को चने–मुर्रे के भाव में बेच डालेंगे। उनके आका अब उनके सीने पर बैठकर उनसे 'विकास का रास्ता सुगम बनाने' के नाम पर पेट फटते तक खाई हुई दलाली के बदले 'नतीजे दिखाने' का दबाव डाल रहे हैं। यही वजह है कि वे इन प्रतिरोधी संघर्षों को कुचलने की हताशा भरी कोशिशों के तहत नए–नए अभियान छेड़ते जा रहे हैं।

सबसे पहले हमें उनके इन सफेद झूठों से धोखा नहीं खाना चाहिए कि ये आक्रमण अभियान सिर्फ माओवादियों को कुचलने के लिए चलाए जा रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दरअसल ये आक्रमण इन इलाकों के तमाम किसानों, आदिवासियों और मजूदूरों को; महिलाओं, बच्चों, पुरुषों और बूढ़ों को; जनवादियों, देशभक्तों और क्रांतिकारियों को; एक शब्द में कहें तो देश के उन तमाम नागरिकों को जिनका इस देश के संसाधनों पर वाजिब हक है, कुचलने के लिए चलाए जा रहे हैं। इसलिए हमें एक व्यक्ति बनकर समवेत स्वर में आवाज उठानी चाहिए ताकि अपने प्यारे देश को बेच डालने की उनकी तमाम साजिशों को हरा दिया जा सके।

हमें सरकारों से सवाल करने हैं कि – जनता द्वारा खारिज किए गए

'विकास के नमूने' को उन्हीं के नाम पर अमल करने का अधिकार उन्हें आखिर किसने दिया है? देश की जनता की गाढ़ी कमाई को खर्च कर पुलिस कार्रवाइयों और सैन्य अभियानों में खुद के नागरिकों को मार डालने का अधिकार उन्हें आखिर किसने दिया है? लाखों सशस्त्र बलों को बलि के बकरे बनाकर ऐसे युद्ध में झोंकने का अधिकार उन्हें किसने दिया है जो उनके हित में या उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कतई नहीं लड़ा जा रहा हो, बल्कि साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और सामंतों के हितों में लड़ा जा रहा हो? सबसे अहम, अपनी आजीविका और अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत जनता पर नरसंहार, आगजनी, लूटपाट, बलात्कार, फर्जी मुठभेड़ें, हिरासती हत्याएं आदि कुकृत्य करने का अधिकार इन सरकारों को कहां से मिला है?

माओवादी संघर्ष वाले इलाकों में, खासकर छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में एक के बाद एक लगातार हुए हमलों के चलते सरकारी सशस्त्र बलों के गिरते मनोबल को ऊपर उठाने के लिए गृहमंत्री ने कहा कि उनके बल माओवादियों का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं और इस साल 125 मुठभेड़ों में कुल 78 माओवादियों को मार गिराया। हम देश और दुनिया की जनता का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि ये आंकड़े सच्चाई को बयां नहीं करते, बल्कि सच यह है कि सैकड़ों निहत्थे लोगों को (चाहे वे क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक या कार्यकर्ता हों या न हों) सरकारी सशस्त्र बलों ने ठण्डे दिमाग से फर्जी मुठभेड़ों में मार डाला। 'माओवादी' महज एक बहाना बना है जिसका ठप्पा लगाकर जनता के जायज संघर्षों को दबाया जा रहा है जिनमें न सिर्फ वो संघर्ष शामिल हैं जिनका नेतृत्व माओवादी कर रहे हैं और जिनमें सिर्फ वही संघर्ष शामिल नहीं हैं जिनका माओवादी नेतृत्व कर रहे हैं।

गैंग्स्टर मुख्यमंत्रियों और डाकू पुलिस महा निदेशकों (डीजीपी) की हर बैठक में आंध्रप्रदेश सरकार की पीठ यह कहकर थपथपाई जाती है कि उसने अपने राज्य में माओवादी आंदोलन को सुचारू रूप से कुचल दिया। सच्चाई यह है कि इस 'उपलब्धि' को हासिल करने के लिए उन्होंने लगातार चार दशकों तक फासीवादी हमले कर क्रांतिकारियों, जनता और खासकर तेलंगाना के लोगों का काफी खून बहाया। अब यह उकसाया जा रहा है कि हर राज्य

इसी फासीवादी नमूने पर अमल करे। आंध्रप्रदेश के ग्रेहाउण्ड्स के बल ओड़िशा और छत्तीसगढ़ की सीमाओं में खुलेआम घुसपैठ करते हैं ताकि माओवादियों और सीमावर्ती इलाकों की आदिवासी बस्तियों पर हमले किए जा सके। देश के किसी भी हिस्से में हुई माओवादी नेताओं की गिरफ्तारी और प्रत्येक फर्जी मुठभेड़ के पीछे एपीएसआईबी का हाथ है। इसलिए केन्द्र सरकार के पूर्ण समर्थन से एओबी में आंध्रप्रदेश और ओड़िशा सरकारों द्वारा तालमेल के साथ तीन माह तक चलने वाले इस भारी आक्रमण को हम अगर मजबूत प्रतिरोध के जरिए रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो इतिहास में एक बेहद खूनी अध्याय शुरू होने का खतरा है। सलवा जुडूम, शांति सेना तथा सशस्त्र बलों के कई किस्म के अत्याचारों के लिए बदनाम छत्तीसगढ़ और ओड़िशा में यह हमला बेहद बर्बर तरीके से चलेगा क्योंकि साम्राज्यवाद–परस्त सरकारी नीतियों के खिलाफ इन राज्यों में मजबूत सशस्त्र और निःशस्त्र जन प्रतिरोध जारी है। केन्द्र सरकार ने अब इन दो राज्यों पर आक्रमण को केन्द्रित करते हुए आंध्र के सीमावर्ती इलाकों को भी इसमें जोड़ दिया। इस व्यापक इलाके में प्रतिरोध को दबाकर वे फिर दूसरे इलाकों की ओर निकल पड़ेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि झारखण्ड या पश्चिम बंगाल में हमले रुकने वाले हैं। इसका यही मतलब है कि देशव्यापी युद्ध के अंतर्गत अब इस इलाके पर फोकस रहेगा।

अपनी जिंदगी के लिए और अस्तित्व के लिए संघर्षरत भारत के लोगों के प्रति देश की तमाम जनता और विश्व जनता की ओर से हमेशा समर्थन मिला है, मिल रहा है। देश के शासक वर्गों द्वारा किए जा रहे इन फासीवादी आक्रमणों के संदर्भ में उनका समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए, हम देश–दुनिया की तमाम सच्ची जनवादी ताकतों से अपील करते हैं कि वे भारत के शासक वर्गों की साजिशों का पर्दाफाश कर, उसके खिलाफ हर संभव तरीके से संघर्ष छेड़ें। हमारी अपील है कि वे संघर्ष के क्षेत्रों में सेना की तैनाती को रोकने और तमाम आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक व मनोवैज्ञानिक हमलों को रोकने की मांग के साथ आंदोलनों का निर्माण करें।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी छत्तीसगढ़–ओड़िशा, आंध्रप्रदेश–ओड़िशा और छत्तीसगढ़–आंध्रप्रदेश की सीमावर्ती इलाकों की तमाम लड़ाकू जनता का आह्वान करती है कि वे इस

नए फासीवादी हमले का बहादुरी के साथ मुकाबला करें। समूची पार्टी और पीएलजीए बलों को चाहिए कि वे इस व्यापक इलाके में जनता की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए सभी मोर्चों में दुश्मन के इस हमले का प्रतिरोध करें तथा सशस्त्र प्रतिरोध को तेज करें।

- ★ छत्तीसगढ़–ओड़िशा, ओड़िशा–आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़–आंध्रप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में प्रस्तावित नए फासीवादी आक्रमण को फौरन रोक दिया जाए!
- ★ ऑपरेशन ग्रीन हंट को तत्काल बंद किया जाए!
- ★ पोस्को, रावघाट रेल लाइन और खदानों के लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण को रोका जाए!
- ★ पोस्को परियोजना के खिलाफ आंदोलनरत जनता पर चलाए जा रहे सरकारी दमनचक्र का विरोध करो!

vHk;

izoDrk] dsUæh; desVh

Hkkjr dh dE;qfuLV ikVhZ ¼ekvksoknh½

18 जून 2011

4 ls 11 tqykbZ rd e/; jhtu esa fojks/k lIrkg euk;k tk,! ukjk;.kiqj ftys ¼ekM+ {ks=½ ds chpkchp clk;s tk jgs lsuk ds izf'k{k.k dsUæ dk rRdky cn djks!

छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले में 750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भारतीय सेना के लिए एक काउण्टर–गुरिल्ला प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया जा रहा है। यह इलाका एक प्राचीन आदिवासियों का जीवन–स्थल है। इन्हीं आदिवासियों के बारे में विगत दो दशकों से सरकार का कहना है कि यह कबीला विलोप के कगार पर है। आज यहां के एक बड़े भू–भाग पर सैनिक अड्डा बसाना उस प्रक्रिया को और तेज करने के सिवाए कुछ नहीं है। 'माओवादी शीर्ष नेताओं ने इन पहाड़ों को अपना अड्डा बनाया है और यहां पर उनकी भूमिगत गतिविधियां खुलेआम चलती हैं' कहकर छत्तीसगढ़ सरकार ने विगत पांच सालों से इस क्षेत्र को एक सैनिक छावनी में तब्दील किया हुआ है। विगत दो साल से यहां पर ग्रीन हंट ऑपरेशन के तहत सघन सैनिक अभियान चलाया जा रहा है। आज यहां पर एक सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना यहां के आदिवासियों के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। वास्तव में इसके पीछे कारण यह है कि यहां के बहुमूल्य खनिज सम्पत्ति को लूटकर ले जाना उनका मकसद है। यहां की जनता इसका पुरजोर विरोध कर रही है। इस तीखे जन विरोध को कुचलने के षड़यत्र से सेना को तैनात किया जा रहा है। हमारी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और जनता से आह्वान करती है कि इसके विरोध में जन संघर्ष को तेज किया जाए।

माड़ क्षेत्र से सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र के प्रस्ताव को तुरंत रद्द करने की मांग से 4 से 11 जुलाई तक मध्य रीजन के छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और आध्रप्रदेश–ओड़िशा सीमा क्षेत्र में आयोजित 'विरोध सप्ताह' सफल बनाया जाए। भारत की व्यापक जनता और जनवाद के प्रेमियों व आदिवासियों के

हितैषियों से हमारी अपील यह है कि वे इस विरोध सप्ताह को सफल बनाने हेतु आगे आएं।

भारतीय सेना के जवानों से हमारी अपील यह है कि वे लुटेरे शासक वर्गों के हित में आदिवासी जनता के खिलाफ युद्ध मत करें। 'माओवादी' के बहाने जनता पर फायरिंग मत करें।

प्रताप
प्रवक्ता
मध्य रीजनल ब्यूरो
भाकपा (माओवादी)

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

22 जून 2011

u flQ viuh tehuk dk]

cfYd viu cPpk dk Hkfo"; Hkh Nhu yu okyh ikLdk ifj;ktuk dk cgknjkuk ifrjk/k dj jg ikLdk&fojk/kh vkUnkyudkfj;k dk yky&yky lyke!

u nyky o rkuk'kkg 'kkld uohu iVuk;d dk vkj u gh lkfu;k&euekgu&t;jke je'k&fpnEcje dk] cfYd flQ turk dk ;g r; dju dk vf/kdkj g fd ge fdl fdLe dh ifj;ktuk, pkfg,!

ikLdk fojk/kh vkUnkyu d leFku e n'k Hkj e O;kid tu vkUnkyuk dk fuekZ.k dj!

भारत की जनता पिछले एक सप्ताह से ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में जारी 'पोस्को–विरोधी आंदोलन' का साक्षी रही है जोकि आधुनिक भारत के इतिहास में किसी साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनी की परियोजना के खिलाफ जारी एक बेहद दृढ़तापूर्ण व उम्दा संघर्ष है। 52 हजार करोड़ रुपए की इस परियोजना को, जिसके बारे में 'सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश' कहकर ढिंढ़ोरा पीटा जा रहा है, हर हाल में रोकने के मजबूत इरादों के साथ संघर्षरत ओड़िशा की जनता को भाकपा (माओवादी) लाल अभिनंदन पेश करती है और अपना पूरा समर्थन प्रकट करती है।

15 मई 2007 को केन्द्र सरकार ने पोस्को परियोजना को आनन–फानन में अनुमति मंजूर की। इसके खिलाफ जनता की ओर सें बड़े पैमाने पर सामने आए विरोध को नजरअंदाज करते हुए मनमोहन ने खुद दक्षिण कोरिया सरकार को यह आश्वासन दिया कि उसकी सरकार इस परियोजना के निर्माण में पूरा सहयोग करेगी। वन अधिकार कानून के नियम–कायदों तथा 2009 में जारी वन और पर्यावरण मंत्रालय के मार्गदर्शक नियमों का ओड़िशा

सरकार के साथ–साथ खुद उस मंत्रालय ने भी खुलेआम उल्लंघन किया। दरअसल 5 अगस्त 2010 को इस परियोजना को रोकने हेतु इस मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया, उसका यही आधार था। राज्य सरकार बार–बार इस बात से इनकार करती आ रही थी कि इस इलाके में आदिवासी निवासरत हैं। लेकिन सक्सेना कमेटी और मीना गुप्ता कमेटि ने अपनी तथ्यान्वेशण रिपोर्टों में इस बात के अकाट्य सबूत पेश किए थे कि प्रस्तावित इलाके में परम्परागत वननिवासी मौजूद हैं जो अपने जीवन यापन के लिए परम्परागत रूप से जंगलों पर ही निर्भर हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्टों में यह आरोप लगाया कि राज्य सरकार मौजूदा वन अधिकारों पर अमल नहीं कर रही है। धिंकिया और गोविंदपुर गांवों के 65 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने अपनी पल्ली सभाओं (ग्रामसभाओं) में यह मत प्रकट करते हुए प्रस्ताव किया कि वे किसी भी प्रकार के जमीन–अधिग्रहण के खिलाफ हैं। लेकिन राज्य सरकार ने बेशर्मी के साथ इन तथ्यों पर परदा डालकर वन और पर्यावरण मंत्रालय को दी गई अपनी रिपोर्ट में झूठ बताया कि उपरोक्त प्रस्ताव ही गलत थे। इस तरह के कई सबूत हैं जिसमें कि राज्य सरकार ने झूठों का सहारा लेकर सच्चाइयों और आंकड़ों को तोड़–मरोड़कर पेश किया हो। मीना गुप्ता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर वन सलाहकार कमेटी ने वन अनुमति को वापस लेने की सिफारिश की। लेकिन इन सबका उल्लंघन करते हुए 2 मई को जयराम रमेश ने इस परियोजना को पर्यावरणीय अनुमति दे डाली। इसके तुरंत बाद राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए जून महीने में पुलिस बलों को उतार दिया है।

इस पूरे दौर में जनता ने इस 12 मिलियन टन क्षमता वाले इस्पात संयंत्र के निर्माण के खिलाफ, सुंदरगढ़ जिले में इस कम्पनी के लिए प्रस्तावित लोहा खदान के खिलाफ और परादीप बंदरगाह से 12 कि.मी. दूर पर व प्रस्तावित स्टील कारखाने के नजदीक पोस्को द्वारा प्रस्तावित निजी बंदरगाह के निर्माण के खिलाफ संघर्ष का परचम बुलंद कर जमीन–अधिग्रहण की हर कोशिश का विरोध किया है। सच्चाई यह है कि केन्द्र व राज्य सरकार दोनों ने इस साजिश को अंजाम दिया। जयराम रमेश ने यह कहकर कि 'पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति देने का यह मतलब नहीं है कि जमीन का बलपूर्वक अधिग्रहण किया जाए' शिगूफा जो छोड़ा है और इस जन आंदोलन के समर्थन के नाम

पर कांग्रेसियों के गोविंदपुर की ओर निकल पड़ना महज धोखा है। जयराम रमेश ओड़िशा सरकार को यह हिदायत दे रहा है कि जमीनों का अधिग्रहण 'लोकतांत्रिक तरीके' से किया जाए! हो सकता है कि उसके मार्के के 'लेकतंत्र' में झूठ बोलना और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से दलालखोरी करना भी शामिल हों! लेकिन इस तरह की परियोजनाओं का विरोध करने वाली जनता को (जिसमें आदिवासियों की बहुसंख्या है) जिस 'लोकतंत्र' का स्वाद चखाया जाता है उसमें सिर्फ फर्जी मुठभेड़ें, यातनाएं और बिना किसी सुनवाई के सालों साल जेलों में बंद करना शामिल हैं।

केन्द्रीय गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने हाल ही में दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि योजना आयोग के वेबसाइट में जाकर लोगों को वहां लगी तस्वीरों को देखना चाहिए कि पिछड़े इलाकों (खासकर 'माओवादी' इलाकों) में सड़कों, आंगनवाड़ी और शाला भवनों के निर्माण के साथ 'विकास' कितनी तेजी से हो रहा है। उसने यह भी जोड़ा है कि 'तस्वीरें अपने आप सच्चाई को बयां करती हैं'। क्या जी.के. पिल्लई गिरोह ने उन तस्वीरों को देखा है जिसमें बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों को एक के पीछे एक घेरा बनाकर कतारों में लेटे हुए देखा जा सकता है जो अपनी जमीनों को नवीन पटनायक के 'लाइसेंसी हत्यारों' के दमनपूर्वक सहयोग से बहुराष्ट्रीय दैत्य द्वारा हड़पने की कोशिशों को रोक रहे थे? क्या वे तस्वीरें किसी सच्चाई को बयां कर रही हैं?

आखिर हजारों आंदोलनकारी पोस्को के प्रवेश को रोकने के लिए क्यों अपनी जान को दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं? जब भी दलाल शासकों ने नव उपनिवेशवादियों के हाथों देश की सम्पदाएं बेचने की कोशिश की, तो सरकारी नीतियों के खिलाफ लड़ने वालों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? क्या ये आंकड़े किसी सच्चाई को बयां कर रहे हैं?

सिंगूर, नंदीग्राम, लालगढ़, नारायणपटना, भट्टा–परसौल, श्रीकाकुलम, बस्तर और लोहरदग्गा में ही नहीं, बल्कि देश के हर राज्य में, हर गांव में और कस्बे में क्यों इतने सारे जन आंदोलनों का अनवरत सिलसिला चल पड़ा है जिसमें जनता की व्यापक भागीदारी है? हाल के दिनों में भड़क रहे इन जन आंदोलनों की लम्बी फेहरिश्त क्या किसी सच्चाई को बयां कर रही है?

सिंगूर की तपसि मलिक से लेकर जैतापुर में तबरेज़ तक और कलिंगनगर के 13 आदिवासियों से लेकर सोम्पेटा, काकरापल्ली के किसानों तक ऐसे

आंदोलनों में जान गंवाने वाले जन नेताओं और आंदोलनकारियों की कुरबानियां तथा उनकी अंतिमयात्राओं में हजारों लोगों के हजूम का निकल पड़ना क्या किसी सच्चाई को बयां कर रहे हैं? धराशायी हुए इन शहीदों का स्थान खामोशी से पर दृढ़तापूर्वक पूरा करते हुए, 'जल–जंगल–जमीन हमारा है' का नारा बुलंद करते हुए क्यों हजारों लोग संघर्ष के कतारों में भर्ती होने लगे हैं?

उन लोगों के लिए संदेश साफ है जो सुनना चाहते हैं। देश का अत्यधिक बहुमत मुनाफा–केन्द्रित व साम्राज्यवाद–परस्त विकास के नमूने को ठुकराकर विकास के उस नमूने को अपना रहा है जो जन–केन्द्रित और जन–अनुकूल हो। शासक वर्गों की ओर से भी संदेश साफ है। जनता को और देश को चाहे जितना भी नुकसान हो, साम्राज्यवादियों के मार्गदर्शन में और उनके पूरे सहयोग से दलाल शासक अपनी लूटखसोट और शोषण को जारी ही रखेंगे। यह 'नुकसान' न सिर्फ 'भौतिक रूप से' जमीन, पानी, हवा, समुद्र, बंदरगाह, प्राकृतिक संसाधन, जंगल, पर्यावरण, दुर्लभ वृक्ष, वन्यप्राणी, प्राचीन सभ्यताएं, सम्पत्तियां, शरीर के अंग और प्राणों को गंवाने के रूप में रहेगा, बल्कि आत्मसम्मान, संप्रभुता, आजादी, स्वाधीनता, अभिमान आदि मूल्यों को खोने के रूप में भी रहेगा जो हमें खुद को इंसान के रूप में पहचानने के लिए बेहद जरूरी हैं।

जगतसिंहपुर की जनता एक सीधा–सादा सवाल पूछ रही है – हम इन सबको क्यों गंवाएं? दरअसल वो कौन होते हैं जो यह तय कर रहे हैं कि हम इन सबको गंवा दें? वो एक सच्चाई को बयां कर रहे हैं जिसकी जानकारी सभी को जरूर होनी चाहिए – हमें क्या चाहिए इसे तय करने का अधिकार हम जनता को ही होगा। वो शासक वर्गों को सीधी चुनौती दे रहे हैं – जनता के गुस्से का मुकाबला करने तैयार हो जाएं क्योंकि हम घुटने टेकना नहीं चाहेंगे। वो एक नियमबद्ध तथ्य की घोषणा कर रहे हैं – भारत की जनता गुलामों सी जिंदगी में धकेले जाने का विरोध कर रही है।

दरअसल तस्वीरें भी कई बार सच्चाई को बयां नहीं कर सकतीं! मसलन, 'माओवादी इलाकों' में निर्मित शाला भवनों की तस्वीरें यह सच बयां नहीं करेंगी कि उनका निर्माण पूरा होते ही उन पर कब्जा करने के लिए सरकारी सशस्त्र बल ताक में बैठे हुए हैं। लेकिन सालों से, लाखों लोगों का अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आंदोलन करना एक सच को जरूर बयां करता है।

एक ऐसा सच जिसे फिलहाल हमारे देश में दूसरे किसी भी सच से ज्यादा बोलने और सुनने की जरूरत है। एक ऐसा सच जोकि हमारे देश का भविष्य तय करने वाला है। इसी सच को 19वीं और 20वीं सदियों में ब्रितानी उपनिवेशवादियों के खिलाफ लड़े गए अनगिनत किसानों और आदिवासियों की बगावतों और संघर्षों (जिनमें ज्यादातर सशस्त्र थे) ने भी बयां किया था। एक ऐसा सच जो सभी किस्म के उपनिवेशी व नव उपनिवेशी शोषण व उत्पीड़न को खत्म कर देना चाहता है। अंग्रेजों ने इस सच को न देखने और न सुनने के लिए अपनी आंखें और कान बंद कर रखे थे और पाशविक बल के सहारे उसका दमन करना चाहा था। भारत के वर्तमान शासक वर्ग भी उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। अगर वे 'जनता पर अपने अन्यायपूर्ण युद्धों' को इसी तरह जारी रखेंगे तो यह रास्ता उन्हें भी कब्रगाह में ही ले जाएगा जैसाकि उनके साम्राज्यवादी आकाओं के साथ हुआ था। ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से माओवादी इलाकों में पुलिस व अर्धसैनिक बलों को (अब सेना को भी) उतारना, या एक भट्टा–परसौल में या फिर एक गोविंदपुर में पुलिस व अर्धसैनिक बलों को उतारना – इन सबका मकसद न्यायपूर्ण जन संघर्षों को कुचलना ही है। दिसम्बर 2010 से लेकर अभी तक नवीन पटनायक सरकार द्वारा 25 से ज्यादा खदान–विरोधी कार्यकर्ताओं की फर्जी मुठभेड़ों में हत्या करना और ओड़िशा व छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित माओवाद–विरोधी दमनकारी कार्रवाइयों को लेकर नवीन पटनायक व रमनसिंह के साथ पी. चिदम्बरम की बैठक इस बात को दर्शाते हैं कि केन्द्र व राज्य सरकारें जन आंदोलनों का किस तरह दमन करना चाहती हैं।

जबरिया जमीन अधिग्रहण और देश के प्राकृतिक संसाधनों की लूटखसोट के खिलाफ जारी कई अन्य संघर्षों के साथ–साथ पोस्को–विरोधी आंदोलन यह फैसला कर सकने की क्षमता रखता है कि देश में निर्बाध रूप से आ रहे तमाम दूसरे विदेशी पूंजीनिवेशों का भविष्य क्या रहेगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी ओड़िशा की जनता को अपने संघर्ष में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है और समूचे देशवासियों का यह आह्वान करता है कि वे इस बहादुर जनता के समर्थन में संघर्षों का निर्माण करें। जगतसिंहपुर की जनता को चाहिए कि वह विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और नागरिक समाजों से उसको मिल रहे समर्थन को स्वीकारते हुए

ही तमाम संभावित साजिशों व षड़यंत्रों के प्रति सावधान रहे क्योंकि उनमें से कुछ, खासकर संसदीय राजनीतिक पार्टियां इस संघर्ष को गुमराह कर सकती हैं। इस बात को नहीं भुलाना चाहिए कि ये तमाम राजनीतिक पार्टियां उन जगहों पर जहां वे सत्ता में होती हैं या सत्ता में भागीदारी लेती हैं, इसी प्रकार की साम्राज्यवाद–परस्त नीतियों पर अमल कर रही हैं। जब वे विपक्ष में होती हैं तब भी वे इन नीतियों को परोक्ष समर्थन कर रही हैं।

जगतसिंहपुर जाकर पोस्को–विरोधी आंदोलन का समर्थन करने के अलावा जहां–तहां हर राज्य में उनके समर्थन में प्रचार व आंदोलन के विभिन्न स्वरूपों को अपनाने की जरूरत है। भारत की जनता और विश्व जनता से भाकपा (माओवादी) की अपील है कि वे इस बहादुराना जन संघर्ष के प्रति व्यापक समर्थन प्रकट करें। आज फौरी जरूरत इस बात की है कि ऐसे तमाम संघर्षों के बीच एक व्यापक आधार पर एकजुटता कायम कर न सिर्फ पोस्को जैसी परियोजनाओं को रद्द करने की मांग से बल्कि पूरे देश से सभी किस्म के साम्राज्यवादी शोषण, नियंत्रण और उत्पीड़न का अंत करने के लक्ष्य से लड़ने वाले सांझा मंच खड़ा किया जाए।

★ पोस्को के लिए जारी जमीन अधिग्रहण को तत्काल रोक दिया जाए!

★ जगतसिंहपुर जिले से पुलिस व अर्धसैनिक बलों को तत्काल वापस बुलाया जाए! जनता पर दबाव बनाने वाले हर किस्म के हथकण्डों को रोका जाए!

★ देश की प्राकृतिक सम्पदाओं, जिन पर सिर्फ और सिर्फ जनता का जायज हक है, की लूटखसोट की खुली छूट देकर देश को बेच डालने हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ किए गए तमाम एमओयू रद्द किया जाए!

vHk;

dUæh; deVh ioDrk

Hkkjr dh dE;fuLV ikVh ¼ekvkoknh½

24 जून 2011

jk"V'ifr }kjk j[kk x;k 'kkfr okrk dk iLrko turk dk xejkg djus dk ,d vkj gFkd.Mk!

अपने रायपुर प्रवास के दौरान राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा पाटिल ने आज, यानी 24 जून 2011 को हमारे सामने यह प्रस्ताव रखा है कि 'माओवादी हिंसा छोड़कर बातचीत के लिए आगे आएं और मुख्य धारा से जुड़ जाएं ताकि आदिवासियों के विकास में शामिल हुआ जा सके'। राष्ट्रपति का प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है जबकि भारतीय सेना के करीब एक हजार जवान बस्तर क्षेत्र के तीन जिलों में अपना पड़ाव डाल चुके हैं ताकि देश की निर्धनतम जनता पर जारी अन्यायपूर्ण युद्ध – ऑपरेशन ग्रीन हंट में शिरकत कर सकें। वे ऐसे वक्त 'वार्ता' की बात कह रही हैं जबकि खनिज सम्पदा से भरपूर देश के कई इलाकों से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बाबत् सरकारों और कार्पोरेट कम्पनियों के बीच वार्ता के कई दौर पूरे हो चुके हैं और लाखों करोड़ रुपए के एमओयू पर दस्तखत किए जा चुके हैं। वे 'वार्ता' की बात तब कह रही हैं जबकि बस्तर क्षेत्र में 750 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र, जिसके दायरे में दर्जनों गांव और हजारों माड़िया आदिवासी आते हैं, सेना के हवाले करने का फैसला बिना किसी वार्ता के ही लिया जा चुका है।

देश की ये सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति हमें ऐसे समय हिंसा छोड़ने की हिदायत दे रही हैं जबकि इसी छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित ताड़िमेट्ला, मोरपल्ली, पुलानपाड़ और तिम्मापुरम गांवों में सरकारी सशस्त्र बलों के हाथों बलात्कार और मारपीट की शिकार महिलाओं के शरीर पर हुए जख्म भरे ही नहीं। वे ऐसे समय हमें हिंसा त्यागने की बात कह रही हैं जबकि न सिर्फ इन गांवों में, बल्कि दण्डकारण्य, बिहार–झारखण्ड, ओड़िशा, महाराष्ट्र, आदि कई प्रदेशों में, खासकर माओवादी संघर्ष वाले इलाकों या आदिवासी इलाकों में सरकारी हिंसा रोजमर्रा की सच्चाई बन गई है। दरअसल सरकारी हिंसा एक ऐसा बहुरूपिया है जो अलग–अलग समय में विभिन्न रूप धारण कर लेता है। जैसे कि अगर आज का ही उदाहरण लिया जाए, तो रातोंरात मिट्टी तेल पर 2 रुपए, डीज़ल पर 3 रुपए और रसोई गैस पर 50 रुपए का दाम बढ़ाकर गरीब व मध्यम तबकों की जनता की कमर

तोड़ देने के रूप में भी होती है जो पहले से महंगाई की मार से कराह रही थी। लेकिन राष्ट्रपति को इस 'हिंसा' से कोई एतराज नहीं!

भारत की यह प्रथम नागरिक हमें उस 'मुख्यधारा' में लौटने को कह रही हैं जिसमें कि उस तथाकथित मुख्यधारा के 'महानायकों' – घोटालेबाज मंत्रियों, नेताओं, कार्पोरेट दैत्यों और उनके दलालों के खिलाफ दिल्ली से लेकर गांव–कस्बों के गली–कूचों तक जनता थूं–थूं कर रही है। वो ऐसी 'मुख्यधारा' में हमें बुला रही हैं जिसमें मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं आदि के लिए अन्याय, अत्याचार और अपमान के अलावा कुछ नहीं बचा है।

और श्रीमति प्रतिभा पाटिल हमें उस पृष्ठभूमि में वार्ता के लिए आमंत्रित कर रही हैं जबकि ऐसी ही एक पेशकश पर हमारी पार्टी की प्रतिक्रिया सरकार के सामने रखने वाले हमारी पार्टी के प्रवक्ता और पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड आजाद की हत्या इसी सरकार ने एक फर्जी झड़प में की थी। इत्तेफाक से उनकी शहादत की सालगिरह अब से ठीक एक हफ्ता बाद है जबकि साल भर पहले करीब–करीब इन्हीं दिनों में चिदम्बरम और उनका हत्यारा खुफिया–पुलिस गिरोह उनकी हत्या की साजिश को अंतिम रूप दे रहे थे। कॉमरेड आजाद ने वार्ता पर हमारी पार्टी के दृष्टिकोण को साफ तौर पर देश–दुनिया के सामने रखा था और उसका जवाब उनकी हत्या करके दिया था आपकी क्रूर राज्यसत्ता ने। और उसके बाद भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पकड़कर जेलों में कैद करने का सिलसिला लगातार जारी रखा हुआ है। 60–70 साल पार कर चुके वयोवृद्ध माओवादी नेताओं को जेलों में न सिर्फ अमानवीय यातनाएं दी जा रही हैं, बल्कि उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन पर 10–10 या 15–15 राज्यों के झूठे केस लगाए जा रहे हैं ताकि ताउम्र उन्हें जेल की कालकोठरियों में बंद रखा जा सके।

इसलिए, देश की जनता से हमारा आग्रहपूर्वक निवेदन है कि –

आप महामहिम राष्ट्रपति से यह मांग करें कि 'शांति वार्ता' की पेशकश करने से पहले उनकी सरकार जनता पर जारी युद्ध – ऑपरेशन ग्रीन हंट बंद करे; बस्तर में सेना का 'प्रशिक्षण' बंद करे; और तमाम माओवाद–प्रभावित इलाकों से सेना व अर्धसैनिक बलों को वापस ले। अगर सरकार इसके लिए

तैयार होती है तो दूसरे ही दिन से जनता की ओर से आत्मरक्षा में की जा रही जवाबी हिंसा थम जाएगी।

आप महामहिम राष्ट्रपति से यह मांग करें कि 'विकास' की बात करने से पहले उनकी सरकार कार्पोरेट घरानों और सरकारों के बीच हुए तमाम एमओयू रद्द करे। बलपूर्वक जमीन अधिग्रहण की सारी परियोजनाओं को फौरन रोके; उनकी सरकार यह मान ले कि जनता को ही यह तय करने का अधिकार होगा कि उसे किस किस्म का 'विकास' चाहिए।

आप महामहिम राष्ट्रपति से यह मांग करें कि 'मुख्यधारा' में जुड़ने की बात करने से पहले सरकार सभी घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों को गिरफतार कर सजा दे। विदेशी बैंकों में मौजूद सारा काला धन वापस लाए। घोटालों और अवैध कमाई में लिप्त तमाम मंत्रियों और नेताओं को पदों से हटाकर सरेआम सजा दे।

vHk;

i:oDrk] dUæh; deVh

Hkkjr dh dE;fuLV ikVh ¼ekvkoknh½

vkfnoklh o nfyr lkLd`frd dk;Zdrk o urk dkejM l thru ejk.Mh] vfuy jke] eukt jktoj vkj N=ifr e.My dk nh xbZ Qklh dh ltkvk dk Qkju jí djk!

23 जून को झारखण्ड के गिरिडीह सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति इंद्रदेव मिश्र ने 2007 में छिलकारी में हुई 19 लोगों की हत्या के मामले में जीतन मराण्डी, अनिल राम, मनोज राजवर और छत्रपति मण्डल को मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले के साथ ही राजसत्ता ने फिर एक बार अपने फासीवादी चरित्र का नंगा प्रदर्शन किया। जीतन मराण्डी और अन्य लोग हमेशा खुलेआम काम करते रहे और वे जिन संगठनों से जुड़े थे वे प्रतिबंधित भी नहीं थे। ऐसे लोगों को एक ऐसे मामले में जिसके साथ उनका कोई लेना–देना नहीं था, मौत की सजा सुनाने का साफ मतलब यह है कि यह एक बदले की कार्रवाई के तहत दी गई सजा थी क्योंकि वे अपने नाच–गानों के साथ साम्राज्यवाद–विरोधी, सामंतवाद–विरोधी, खासकर विस्थापन–विरोधी जन संघर्षों की मजबूती से पक्षधरता कर रहे थे। देश में माओवादी आंदोलन का, खासकर मध्य और पूर्वी भारत में, दमन करने की मंशा से शुरू किए गए ऑपरेशन ग्रीन हंट के तहत केन्द्र व राज्य सरकारें अत्यंत गरीब आदिवासियों पर बेहद घिनौने व पाशविक अत्याचार कर रही हैं। मौत की ये सजाएं इस बात का एक और सबूत है। ऑपरेशन ग्रीन हंट के अत्यंत पाशविक स्वरूप छत्तीसगढ़, झारखण्ड व ओड़िशा के खासकर उन आदिवासी इलाकों में लागू किए जा रहे हैं जहां माओवादी आंदोलन मजबूत है।

जीतन मराण्डी एक जाने–माने आदिवासी सांस्कृतिक कलाकार हैं। वे सांस्कृतिक संगठन 'झारखण्ड अभेन' के नेता हैं और अखिल भारतीय क्रांतिकारी सांस्कृतिक संघ के भी नेता हैं। क्रांतिकारी गीतों और संस्कृति का प्रचार करते हुए उन्होंने देश भर में दौरे किए। अनिल राम, मनोज राजवर और छत्रपति मण्डल भी आदिवासी व दलित सांस्कृतिक कलाकार हैं। जीतन ने बचपन से ही सांस्कृतिक मामलों में अपनी कुशलता का परिचय दिया था।

धीरे–धीरे वे देश के अत्युत्तम कलाकारों में से एक बन गए। एक सचेतनशील किशोर के रूप में वे अपने आदिवासी समाज की हालत पर ध्यान दिए बिना रह नहीं सके। आदिवासियों में व्याप्त गरीबी, शोषण और उत्पीड़न की जड़ों को समझने के मकसद से किया गया सामाजिक अध्ययन उन्हें क्रांतिकारी राजनीति की तरफ लेकर गया। खुद वे और उनका सांस्कृतिक संगठन जनता की चेतना बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी राजनीति का प्रचार करते हैं।

अपने विचारों का खुले तौर पर प्रचार करना अपराध नहीं है। इसके लिए किसी को भी दण्डित नहीं किया जा सकता। भारत के शासक वर्ग किसी भी प्रकार के विरोध को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। जनता की प्राकृतिक सम्पदाओं और अपार खनिज सम्पदाओं की लूटखसोट को सुगम बनाने वाली साम्राज्यवाद–परस्त और जन विरोधी नीतियों के विरोध में उठने वाली हर आवज को दबाने के लिए वे हर प्रकार का हथकण्डा अपना रहे हैं। सच्चे जन कलाकारों के रूप में वे झारखण्ड में जारी विस्थापन–विरोधी आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे जहां से देश के शासक वर्गों द्वारा लागू विस्थापन की नीतियों के खिलाफ बेहद मजबूती से प्रतिरोध उठ रहा है। यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि राजसत्ता उन्हें उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए सजा दे रही है, न कि किसी छिलकारी केस के सिलसिले में। बिहार व झारखण्ड में हुए सामंतवाद–विरोधी संघर्षों के दौरान जमींदारों ने अपनी निजी सेनाओं के जरिए किसानों, खासकर दलितों के कत्लेआम किए थे। किसानों को अपनी आत्मरक्षा में जवाबी हिंसा का रास्ता अख्तियार करने पर बाध्य होना पड़ा। छिलकारी जैसी घटनाएं इसी सिलसिले का हिस्सा हैं। ऐसी घटनाओं की गहराई में जाकर कारणों का पता लगाने की बजाए राजसत्ता इस आड़ में जन संगठनों पर फर्जी मुकदमे दायर कर उनका गला घोंटने की कोशिश कर रही है। पहले उन्होंने 2007 में जीतन मराण्डी पर रांची में राजभवन के सामने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के सवाल को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राजद्रोह का एक मामला दायर किया था। तबसे उन्हें जेल में डालकर झूठे मामलों में फंसाते हुए प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके पहले भी उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था और उनके साथ कई बार बुरी तरह मारपीट की गई। आखिर में इन तमाम साजिशों की पराकाष्ठा के रूप में उन्हें मौत की सजा सुनाकर उनकी

आवाज हमेशा के लिए दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में राजसत्ता की बेशर्मी का आलम यह है कि उन पर पीरटांड और तीसरी पुलिस थानों के ऐसे मामले भी दायर किए गए हैं जो दरअसल उस समय हुए थे जब वे जेल में बंद थे!

हमारा देश दो सौ सालों के लम्बे अरसे तक अंग्रेजों के उपनिवेशी शासन में रहा। फलस्वरूप यह कई आदिवासी विद्रोहों का गवाह भी रहा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने आधुनिक हथियारों के सहारे पाशविक ताकत का प्रयोग कर इन विद्रोहों को कुचलने की कोशिश की। विद्रोहों के नायकों को फांसी देना उनका एक प्रचलित दमनात्मक दावपेंच था। उपनिवेशवादी शासकों की दमनकारी मशीनरी के वारिसों के रूप में भारत के दलाल शासक वर्ग उन्हीं के नक्शेकदम पर चल रहे हैं। कॉमरेड्स भूमैया और किष्टागौड़ 'आजाद' भारत के पहले क्रांतिकारी किसान कार्यकर्ता थे जिन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। उसके बाद भी कई क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं, खासकर बिहार (जिसमें आज का झारखण्ड भी शामिल था) के क्रांतिकारी किसान कार्यकर्ताओं को फर्जी मामलों में फंसाकर मौत की सजाएं सुनाई गईं। जन वकील और मानवाधिकार संगठनों के नेता के.जी. कन्नबीरन, पत्तिपाटी जैसे शख़्सों ने अपने संगठनों के जरिए अदालतों के अंदर और बाहर भी न सिर्फ मौत की सजाओं के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि मौत की सजा को ही पूरी तरह रद्द करने की मांग से व्यापक आंदोलनों का निर्माण किया। इस पृष्ठभूमि में कि राजसत्ता आदिवासी बस्तियों में आए दिन कत्लेआम, फर्जी मुठभेड़ और अत्याचारों को जारी रखते हुए ही फांसी की सजा जैसी फासीवादी कार्रवाइयों पर भी उतारू है, इस संघर्ष को और भी व्यापक आधार पर तेज करने की जरूरत है। नारायणपटना संघर्ष से जुड़े हुए नेता सिंगन्ना को पुलिस ने सीधे तौर पर गोली मार दी। लालगढ़ संघर्ष के लोकनायक लालमोहन टुडू की पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी। अब झारखण्ड में जीतन मराण्डी को फांसी की सजा सुनाई गई। सामंतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ जारी जन आंदोलनों से उभर रहे नेताओं को कत्ल करने की साजिश के तहत ही यह सब हो रहा है। उनकी कोशिश यह है कि जन संघर्षों को नेतृत्वविहीन कर आदिवासी इलाकों से प्राकृतिक सम्पदाओं को बेरोकटोक लूटने के रास्ते में मौजूद तमाम बाधाओं को खत्म किया जाए।

जैसा कि फांसी की सजा सुनाने के तुरंत बाद जीतन के साथ–साथ अदालत में मौजूद जनता ने गीत गाकर सुनाया, 'वह सुबह कभी तो आएगी' जब राजसत्ता द्वारा लागू इन तमाम फासीवादी कार्रवाइयों को जन उभारों से खत्म किया जाएगा। जेलखाने और फांसी के तख़्त जनता के सच्चे नेताओं के क्रांतिकारी जज़्बे को खत्म नहीं कर सकेंगे। वे आखिर तक लड़ते रहेंगे।

भाकपा (माओवादी) यह मांग करती है कि जीतन मराण्डी, अनिल राम, मनोज राजवर और छत्रपति मण्डल को दी गई मौत की सजाओं को तुरंत रद्द किया जाए। हम सभी जनवादी, मानवाधिकार संगठनों, राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए संघर्षरत संगठनों, खासकर कला व साहित्य से जुड़े संगठनों तथा आदिवासी सांस्कृतिक संगठनों से अपील करते हैं कि वे इन मौत की सजाओं को समाप्त करने, इन जन कलाकारों की रिहाई के लिए व्यापक आंदोलनों का निर्माण करें। मौत की सजा को पूरी तरह रद्द करने की मांग के साथ चलने वाले आंदोलन के रूप में इसे व्यापक आधार पर आगे बढ़ाएं।

vHk;
ioDrk] dUæh; deVh
Hkkjr dh dE;fuLV ikVh ¼ekvkoknh½

turk d fy, tku nu oky 'kghnk dh djckfu;k dk Åpk mBkvk!

'kghnk d cfynkuk dh ij.kk l tu;) dk r t djk & vkij'ku xhu gV dk ijkLr djk!!

28 tykbZ l 3 vxLr rd 'kghn lIrkg lQy cuk,!

जनता की मुक्ति के लिए अपने अनमोल प्राणों को न्यौछावर करने वाले बलिदानी वीर समूचे मानव समाज के लिए आदर्श हैं। इन वीरों की कुरबानियों की बदौलत ही उत्पीड़ित जनता कई उपलब्धियां प्राप्त कर रही है। समाजवाद–साम्यवाद के लक्ष्य के अंतर्गत, भारत में नई जनवादी क्रांति की जीत के लिए लड़ते हुए पिछले एक साल में 260 से ज्यादा पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं, पीएलजीए के योद्धाओं, जन संगठनों व जन मिलिशिया के सदस्यों और आम जनता ने अपने अनमोल प्राणों को अर्पित किया। इनमें – दण्डकारण्य में 77, बिहार–झारखण्ड–उत्तर छत्तीसगढ़ में 78, ओड़िशा में 29, आंध्र–ओड़िशा सीमा क्षेत्र में 16, पश्चिम बंगाल में 7, लालगढ़ जन आंदोलन में 36, छत्तीसगढ़–ओड़िशा सीमा क्षेत्र में 10, महाराष्ट्र में तीन और उत्तर तेलंगाना में एक शहीद शामिल हैं। इन सभी में महिला शहीदों की संख्या 30 से ज्यादा है। लुटेरे शासक वर्गों द्वारा जारी 'जनता पर युद्ध' को हराने तथा पल्लावित हो रही जनता की नई सत्ता को विकसित करने के लिए शत्रु–बलों से साहस के साथ लड़ते हुए जनयुद्ध को आगे बढ़ाने के दौरान इन सभी ने अपनी जान कुरबान की। भारतीय क्रांति के महान शिक्षक कॉमरेड्स चारू मजुमदार और कन्नाई चटर्जी समेत भारत की नई जनवादी क्रांति के दौरान धराशायी हुए तमाम शहीदों की याद में, हर साल की तरह 28 जुलाई से शहीद सप्ताह जोरदार ढंग से मनाने हेतु भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी समूची पार्टी, पीएलजीए, क्रांतिकारी जन सरकारों, क्रांतिकारी जन संगठनों और जनता का आह्वान कर रही है।

हमारे देश के अलावा विभिन्न देशों के जनता, जनवादी, देशभक्त, लेखक, कवि व कलाकारों द्वारा 'जनता पर युद्ध' (आपरेशन ग्रीन हंट) का पुरजोर

विरोध किए जाने के बावजूद शोषक शासक वर्गों ने उसकी जरा भी परवाह न करते हुए ग्रीन हंट का दूसरा चरण शुरू कर अपने भाड़े के पुलिस व अर्धसैनिक बलों व प्रतिक्रियावादी गिरोहों के जरिए अंधाधुंध कत्लेआम जारी रखा। इनमें निहत्थी जनता की ही अत्यधिक संख्या में जानें गईं। लालगढ़ जन विद्रोह में शामिल आदिवासी, ओड़िशा में विस्थापन के खिलाफ जारी आंदोलनों में अगुवा भूमिका निभाने वाले, दण्डकारण्य, बिहार, झारखण्ड और उत्तर छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी हमदर्द और जनता शामिल हैं। इन सभी को 'माओवादी' बताकर पुलिस व अर्धसैनिक बलों, पश्चिम बंगाल में हर्मद बाहिनी व गण प्रतिरोध कमेटी के गुण्डों तथा दण्डकारण्य में कोया कमाण्डो, एसपीओ और सलवा जुडूम के गुण्डों ने हत्या की। पश्चिम बंगाल में लालगढ़ इलाके के नेताई गांव में सामाजिक फासीवादी सीपीएम के गुण्डों ने चार महिलाओं समेत 9 लोगों की सामूहिक हत्या की जिसके खिलाफ पूरे राज्य में व्यापक आंदोलन चला। इसी प्रकार दण्डकारण्य के चिंतलनार इलाके में कोबरा, कोया कमाण्डो और सलवा जुडूम के गुण्डों ने छह दिनों तक लगातार श्वेत आतंक चलाया था जिसके खिलाफ देश भर में जनवादियों ने आवाज उठाई। उत्तर छत्तीसगढ़ में पुलिस ने मीना खालखो नामक सोलह साल की किशोरी की सामूहिक बलात्कार के बाद फर्जी मुठभेड़ में हत्या की। इस दरिंदगी के खिलाफ जनता ने आवाज उठाई। ये सब घटनाएं अगस्त 2010 से जून 2011 के बीच घटी हैं।

इसके अलावा फर्जी मुठभेड़ें, पीएलजीए बलों पर जहर का प्रयोग, जन मिलिशिया पर शत्रु–बलों द्वारा किए गए ऐम्बुश, घेराव–हमले आदि में कई आम लोग और क्रांतिकारी मारे गए। छत्तीसगढ़–ओड़िशा की सीमा पर महासमुंद जिले के पड़कीपाली गांव के पास पीएलजीए की एक कम्पनी पर, जो क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार के लक्ष्य से काम कर रही थी, शत्रु–बलों ने घात लगाकर हमला किया जिसमें छह साथी शहीद हुए थे। इस मौके पर भाड़े के पुलिस बलों ने दो ग्रामीणों को भी पकड़कर क्रूरतापूर्वक कत्ल कर दिया। शत्रु–बलों के साथ हुई वास्तविक मुठभेड़ों में कुछ कॉमरेड शहीद हुए थे। कुछ कॉमरेडों और जनता को पुलिस ने लापता कर दिया है। कुछ अन्य घटनाओं, दुर्घटनाओं और बीमारियों के कारण चंद कॉमरेड शहीद हुए थे।

शहीद होने वाले नेतृत्वकारी कॉमरेडों में पश्चिम बंगाल में लालगढ़ जन नेता कॉमरेड्स उमाकांत महतो, शशधर महतो, पार्टी की रीजनल कमेटी

सदस्य कॉमरेड अरुण, कॉमरेड खोखन महतो; बिहार में प्लाटून कमाण्डर कॉमरेड विक्रम मुण्डा, बांका जिले के कटोरिया पुलिस थाना अंतर्गत मंजरी में हुई मुठभेड़ में शहीद हुए छह में से एक नेतृत्वकारी कॉमरेड, ओड़िशा में प्रफुल्ल नायक, लक्ष्मण मुण्डा, गागरी कडेस्की; बिहार–झारखण्ड में कम्पनी कमाण्डर कॉमरेड नितांत, ओड़िशा में काशीपुर के पास हुए घेराव–हमले में बासाधारा डिवीजनल कमेटी सदस्य कॉमरेड रवि, दण्डकारण्य में उत्तर बस्तर डिवीजनल कमाण्डर–इन–चीफ कॉमरेड नागेश, महाराष्ट्र के गोंदिया डिवीजन के कमाण्डर–इन–चीफ कॉमरेड नागेश, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में प्लाटून कमाण्डर कॉमरेड कोसा (आयतू), सांस्कृतिक कार्यकर्ता कॉमरेड नताशा, दण्डकारण्य में प्लाटून–7 के कमाण्डर कॉमरेड महरू, जन शिक्षिका कॉमरेड चंदना और प्रेस कार्यकर्ता कॉमरेड चैते आदि शामिल हैं।

पीएलजीए द्वारा शत्रु–बलों पर किए गए हमलों के दौरान लड़ाई में कुछ कॉमरेड शहीद हुए। बिहार में लखीसराय–कजरा ऐम्बुश (29 अगस्त 2010) में सेक्शन कमाण्डर कॉमरेड रतन यादव; दण्डकारण्य में ऊसूर ऐम्बुश (21 सितम्बर 2010) में दो मिलिशिया सदस्य कॉमरेड्स ओयाम बुदरू और वेट्टि हिड़माल; तिम्मापुरम ऐम्बुश (14 मार्च 2011) में सेक्शन उप–कमाण्डर कॉमरेड मुचाकी गंगा; भेज्जी ऐम्बुश (11 जून 2011) में पीएलजीए बटालियन का पीपीसी सदस्य कॉमरेड मंगडू; महाराष्ट्र के गोंदिया डिवीजन में कोबरामेण्डा एम्बुश (19 अप्रैल 2011) में तीन कॉमरेड्स – डिवीजनल कमाण्डर–इन–चीफ नागेश, पीएलजीए सदस्य मंजू और मंगू; गढ़चिरौली डिवीजन के नारुगोण्डा ऐम्बुश (19 मई 2011) में जिसमें जनता का कट्टर दुश्मन चिन्ना वेंटा का सफाया किया गया, दो कॉमरेड्स – प्लाटून–7 कमाण्डर महरू और एरिया कमेटी सदस्य राकेश शहीद हुए थे। कोइलीबेड़ा के निकट सुलंगी ऐम्बुश (26 जून 2011) में कम्पनी–1 के दो सदस्य कॉमरेड्स जोगाल और श्यामलाल शहीद हुए थे।

साथ ही, कई दशकों से जनवादी अधिकारों के लिए जनता के पक्ष में खड़े होकर लड़ने वाले क्रांतिकारी बुद्धिजीवी व मानवाधिकार आंदोलनों के नेता कॉमरेड्स कन्नाबीरन, पत्तिपाटी वेंकटेश्वरलु, प्रोफेसर आर. सोमेश्वर राव आदि ने इस एक साल में अंतिम सांस ली। इनकी मृत्यु से भारतीय क्रांति ने अपने घनिष्ठ मित्रों और शुभचिंतकों को खो दिया।

शहीद सप्ताह के उपलक्ष्य में पार्टी के संस्थापक नेता कॉमरेड्स चारु

मजुमदार और कन्नाई चटर्जी समेत आज तक शहीद हुए हजारों ज्ञात व अज्ञात स्त्री–पुरुष वीर योद्धाओं को केन्द्रीय कमेटी विनम्र श्रद्धांजली पेश करती है। उनके सपनों को साकार बनाने के लिए अविराम संघर्ष जारी रखने का संकल्प लेती है। इस मौके पर शहीदों के दोस्तों व परिजनों तथा साथियों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उनके शोक में शामिल होती है। उनके तमाम प्यारे साथियों से आग्रह करती है कि वे शहीदों की कमी को पूरा करने आगे आएं।

यह साल अरब दुनिया में जबर्दस्त विद्रोहों का गवाह रहा। लाखों अरब जनता तानाशाही, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ तथा जनतंत्र के लिए अमेरिकी साम्राज्यवादियों के दलाल शासक वर्गों के खिलाफ जुझारू तरीके से लड़ रही है। इन जन विद्रोहों में हजारों जनता और जन नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। विभिन्न देशों में जनतंत्र के लिए, अपनी राष्ट्रीयताओं की मुक्ति के लिए साम्राज्यवाद व सभी किस्म के प्रतिक्रियावाद के खिलाफ लड़ने के दौरान शहीद हुए तमाम वीर योद्धाओं को शहीद सप्ताह के अवसर पर भाकपा (माओवाद) श्रद्धांजली पेश करती है।

इस साल आपरेशन ग्रीन हंट को पराजित करने के लिए अपनाए गए निम्न व मध्यम स्तर के कई कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण सफल रहे हैं। इन हमलों ने दुश्मन की आक्रमकता पर अंकुश लगाया। खासकर ऐसे समय, जब दुश्मन ने दण्डकारण्य के नारायणपुर जिले में सेना को तैनात करने की प्रक्रिया तेज कर दी, हुए इन हमलों ने लुटेरे शासक वर्गों और उनके सशस्त्र बलों को बेहद भयभीत कर दिया। इसके अलावा, झारखण्ड में हजारों शत्रु बलों द्वारा सेना की तर्ज पर किए गए हमलों को पीएलजीए बलों ने बेहद वीरतापूर्वक परास्त कर दिया।

दूसरी ओर, लालगढ़ और नारायणपटना क्षेत्रों में जन आंदोलन भीषण दमन के बीचोबीच भी दुश्मन को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देश के कई अन्य इलाकों में विस्थापन विरोधी संघर्ष जारी हैं। पृथक तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन तेज हो रहा है। साम्राज्यवादियों और उनके दलाल लुटेरे शासक वर्गों के धनाढ्य–कार्पोरेट विकास नमूने का विरोध करते हुए जनता हर तरफ आंदोलन की राह पकड़ रही है। खुफिया कुत्ते इस तरह के संघर्षों के साथ माओवादियों के सम्बन्धों को तलाशते हुए उन्हें माओवादी रंग देने में लगे हुए हैं जिससे यह पता चलता है कि माओवादी आंदोलन से शोषक

शासक वर्ग कितने डरे हुए हैं। दूसरी ओर माओवादी जनयुद्ध देश के जनवादियों और प्रगतिशील ताकतों को काफी उत्साहित कर रहा है। वीर शहीदों की कुरबानियां उन्हें प्रेरणा दे रही हैं।

प्यारे लोगो! माओवादी आंदोलन का जड़ से सफाया करने की डींगें मारते हुए सोनिया–मनमोहन सिंह–चिदम्बरम– प्रणब मुखर्जी का शासक गिरोह आपरेशन ग्रीन हंट के नाम से जनता पर एक अन्यायपूर्ण युद्ध चला रहा है। फिलहाल इसके दूसरे चरण के तहत दण्डकारण्य के बस्तर क्षेत्र में उसने सेना को उतार दिया। लेकिन वह यह कहते हुए कि यह तैनाती नहीं है, सिर्फ प्रशिक्षण के लिए सेना को भेजा जा रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है। क्रांतिकारी आंदोलन को चंद इलाकों तक सीमित कर घेराव–उन्मूलन की रणनीति के तहत भारी दमन अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार को रोका जा सके। मुखबिर नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। इसके बावजूद जन गुरिल्ला बल दुश्मन से लोहा लेते हुए क्रांतिकारी आंदोलन का नए इलाकों में विस्तार कर रहे हैं। गुरिल्ला क्षेत्रों में विकसित हो रही जनता की नई सत्ता का बचाव कर रहे हैं। दुश्मन के आतंकी हमलों से जनता के जानमाल व फसलों की रक्षा कर रहे हैं। इन सभी कार्यों में शहीदों की कुरबानियां छिपी हुई हैं। आगे हासिल की की जाने वाली महान कामयाबियों की वे हामी भर रही हैं।

महान कुरबानियों के बिना दुनिया में कोई भी क्रांति सफल नहीं हुई। आज क्रांति हमें और ज्यादा कुरबानियों के लिए तैयार होने का आह्वान कर रही है। लड़ने का साहस करेंगे तो जनता अपराजेय है। आइए, आज के अद्भुत क्रांतिकारी हालात का सुचारू रूप से फायदा उठाते हुए शहीदों के खून से रंगे सर्वहारा के लाल पताके को ऊंचा उठाकर जनयुद्ध के रास्ते में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ेंगे! अपने देश को सामंती, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और साम्राज्यवादी शोषण–उत्पीड़न से आजाद कर नए जनवादी भारत का निर्माण करेंगे जहां दमन व अन्याय के लिए कोई जगह न हो!

vHk;

i;oDrk] dUæh; deVh

Hkkjr dh dE;qfuLV ikVhZ ¼ekvkoknh½

eEcbl es gq, chHkR l i.k ce geyk dh HkR lluk djk!

eDdk efLtn] ekyxko] le>kSrk ,Dlil ler ce foLQkV dh lHkh ?kVukvk dh

fu"i{k vkj Lor= tkp djokdj nkf"k;k dk dMh l dMh ltk nus dh ekx djk!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) मुम्बई में 13 जुलाई 2011 को हुए बम हमलों की तीव्र निंदा करती है। इन सिलसिलेवार विस्फोटों को, जिसमें लगभग 20 आम लोगों की मौत हुई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए, हमारी पार्टी अमानवीय मानती है। किन लोगों ने इन बम विस्फोटों को अंजाम दिया होगा यह स्पष्ट होने से पहले ही और जांच की प्रक्रिया तक शुरू होने से पहले ही लुटेरे शासक वर्गों और उनके पुलिस/खुफिया संगठनों ने हमारी पार्टी पर षड़यंत्रकारी व बेबुनियाद ढंग से आरोप लगाए हैं कि इसमें माओवादी पार्टी का भी हाथ हो सकता है। इसका हमारी पार्टी पुरजोर खण्डन करती है। देश की उत्पीड़ित जनता को साफ तौर पर मालूम है कि शोषित जनता की मुक्ति के लिए लड़ने वाली हमारी पार्टी आम लोगों को निशाना बनाने और उनकी जान को जोखिम में डालने वाले हमले कभी नहीं करती। लुटेरे शासक वर्ग और उनके सुर में सुर मिलाने वाला कॉर्पोरेट मीडिया अपने बुरे मंसूबों के साथ हम पर जानबूझकर इसलिए झूठे आरोप मढ़ रहे हैं ताकि हमारी पार्टी को आतंकवादी संगठन के रूप में तथा हमारे जायज जन आंदोलन को आतंकवादी आंदोलन के रूप में चित्रित किया जा सके जिससे कि उनकी दमनकारी नीतियों तथा जनता पर जारी युद्ध – ऑपरेशन ग्रीन हंट के दूसरे चरण के तहत शुरू हुई सेना की तैनाती को वैधता हासिल की जा सके।

हमारे देश में अब तक हुए बम विस्फोटों का जायज़ा लिया जाए, तो ज्यादातर घटनाओं में यह बात साफ हो ही नहीं पाई कि उनके असली दोषी कौन थे और दोषियों के रूप में दिखाए जा रहे लोगों के पीछे छिपे असली

गुनाहगार कौन थे। यह रिवाज सा बना है कि विस्फोट की कोई भी घटना घटती है तो हिंदू धर्म की पक्षपाती भारतीय राज्यसत्ता और उसके खुफिया/जांच संस्थाएं व कार्पोरेट मीडिया तुरंत ही और बिना किसी आधार के मुसलमानों और तथाकथित इस्लामिक आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस तरह के तमाम हमलों के लिए मुस्लिम समाज को गुनाहगार निरूपित करने हेतु भारतीय राज्यसत्ता और कांग्रेस, भाजपा जैसी शासक वर्गीय पार्टियों के नेताओं द्वारा रची गई साजिश के तहत आईबी ने खुद ही इंडियन मुजाहिद्दीन नामक एक छद्म संगठन खड़ा किया जिसे हाल में हुए हर बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार बताकर प्रचारित किया जा रहा है। ऐसे आरोपों की सत्यता को लेकर प्रश्न उठाने वालों और उन पर समग्र व निष्पक्ष जांच की मांग करने वालों पर एकायक देशद्रोही का ठप्पा लगाकर कार्पोरेट मीडिया के सम्राट और शासक वर्गों के तलवे चाटने वाले बुद्धिजीवी उन पर बेतुके, आवेशपूर्ण और आक्रामक ढंग से टूट पड़ रहे हैं। इससे बहुसंख्यक जनता को यह जानने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि सच्चाई क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले हमारे देश में सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि सच्चाइयों का पता लगाने की मांग नहीं करना देशभक्ति की और करना देशद्रोह की कसौटी बन गई है!

विगत में हुए मक्का मस्जिद, मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस आदि बम विस्फोट के मामलों में पुलिस ने सैकड़ों निर्दोष मुसलमानों, खासकर नौजवानों को गिरफ्तार कर, अमानवीय यातनाएं देकर जेलों में बंद कर दिया। कई लोगों को फर्जी मुठभेड़ों में मार डाला। बाद में यह सबूत मिलने के बावजूद भी कि संघ गिरोह (आरएसएस) से जुड़े हिंदू कट्टरवादी संगठनों ने इन जघन्य करतूतों को अंजाम दिया था, पीड़ित मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल सका। अभिनव भारत, हिंदू डिफेंस फोर्स, राष्ट्रीय जागरण मंच, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि हिंदू आतंकी संगठनों के एक भी नेता को आज तक सजा नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर संसद पर हमले के मामले में अफ्जल गुरू को, गोधरा रेल जलाने के मामले में 11 मुसलमानों को पिछले 1 मार्च को सुनाई गई फांसी की सजाएं राज्यसत्ता की मुस्लिम विरोधिता और हिंदू कट्टरवाद की पक्षधरता को समझने के लिए चंद उदाहरण भर हैं। जब दो हजार से ज्यादा मुसलमानों के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जैसे

हत्यारे सीना तानकर घूम रहे हों, वहीं बेतुके और आधे–अधूरे सबूतों से मुसलमानों को सजाएं सुनाकर राज्यसत्ता ने मुसलमानों को बेहद नाराज और आक्रोशित किया।

एक सच्चाई यह है कि मुस्लिम समाज, खासकर नौजवानों का एक बड़ा तबका बाबरी मस्जिद की तबाही, गुजरात नरसंहार आदि के चलते भारत के शासक वर्गों से बेहद असंतुष्ट है। एक और अकाट्य सच्चाई यह है कि इस असंतोष ने कुछ इस्लामिक संगठनों को पैदा किया। इस परिस्थिति का फायदा उठाकर, इस तरह के संगठनों को अपने प्रभाव में लेकर या फिर उन्हें षड़यंत्रकारी ढंग से गुमराह कर, कुछ नए संगठनों को पैदा कर दोनों भारत और पाकिस्तान की आरएडब्ल्यू (रॉ), आईबी, आईएसआई जैसी संस्थाएं अपने स्वार्थ राजनीतिक हितों के मद्देनजर दोनों ही देशों में इस तरह के बम विस्फोट और हमले करवा रही हैं। कई असंतुष्ट और आक्रोशित मुस्लिम नौजवान इस जाल में फंसकर, यह नहीं समझते हुए कि उनके असल दुश्मन कौन हैं, इस तरह की अविवेकपूर्ण हिंसात्मक कार्रवाइयों में शिरकत कर रहे हैं। और आम लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार बन रहे हैं। यह इस तरह का जहरीला दुष्चक्र है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन लोग परदे के पीछे से उन्हें चला रहे हैं और इस किस्म के हमलों से किन वर्गों के हित पूरे हो रहे हैं।

दूसरी ओर, इस बात के ठोस सबूत मिलने के बाद कि मक्का मस्जिद, मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस विस्फोटों के लिए 'अभिनव भारत' नामक संघ गिरोह (आरएसएस) से जुड़ा संगठन जिम्मेदार है, देश की जनता ने भगवा आतंकवाद को एक खतरनाक रुझान के रूप में पहचानना शुरू किया। बाद में जब यह पता चला कि अजमेर शेरीफ में हुए बम विस्फोट के लिए भी भगवा आतंकी ही जिम्मेदार हैं, यह मांग उभरकर आई कि देश में विभिन्न जगहों पर हुए तमम बम विस्फोटों की घटनाओं पर हुई जांचों की समीक्षा की जाए। पुलिस अत्याचारों से पीड़ित मालेगांव और हैदराबाद के मुसलमान नौजवानों ने यह मांग की सरकार उनसे माफी मांग ले। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ऊपर से चाहे कुछ भी कहे, अपने स्वार्थपूर्ण राजनीतिक हितों के मद्देनजर भगवा आतंकवाद को शह देते हुए इन मांगों को अनसुना करती आ रही है। आम तौर पर हिंदू धार्मिक कट्टरवाद का समर्थन करने वाला

कॉर्पोरेट मीडिया जहां एक तरफ बिना किसी सबूत के ही मुसलमानों और इस्लामिक संगठनों पर आक्रामक ढंग से टूट पड़ता है, वहीं दूसरी ओर बम विस्फोट की विभिन्न घटनाओं में भगवा आतंकी संगठनों का हाथ होने का साफ सबूत मिल जाने के बावजूद भी वह या तो उस पर कम से कम रिपोर्टिंग करता है या फिर दबा देता है।

इस पृष्ठभूमि में, 13 जुलाई के मुम्बई बम विस्फोटों के लिए दक्षिणपंथी भगवा आतंकी संगठन या फिर आईबी, रॉ जैसी खुफिया संस्थाओं द्वारा प्रायोजित तथाकथित इस्लामिक मिलिटेंट संगठन जिम्मेदार होने की संभवना ज्यादा है। या फिर पुलिस अधिकारियों और शासक वर्गीय राजनेताओं से सांठगांठ करने वाले माफिया गिरोह भी इन हमलों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इन हमलों को चाहे किसी ने भी अंजाम दिया हो, इस तरह की अविवेकपूर्ण हिंसात्मक कार्रवाइयों का फायदा शासक वर्गों को ही मिलेगा। पहला, वर्तमान में ज्वलंत समस्याओं के रूप में मौजूद महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले, काला धन, स्विस बैंक खाते आदि से जनता का ध्यान बंटाना। दूसरा, आतंकवाद को बहुत बड़े खतरे के रूप में दिखाकर और ज्यादा क्रूरतापूर्ण कानूनों को तैयार करना तथा लाखों करोड़ का जन धन का दुरुपयोग करते हुए साम्राज्यवादी देशों से बड़े पैमाने पर हथियार और तकनीक की खरीद कर दमनकारी मशीनरी के दांतों को और ज्यादा धारदार बनाना। तीसरा, 'आतंक के खिलाफ युद्ध' के नाम पर अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा छेड़े गए दुराक्रमणकारी युद्धों, हमलों और धौंस का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन करते हुए दक्षिण एशिया में उसके कनिष्ठ भागीदार की भूमिका निभा रहे भारतीय राज्य का होमलैण्ड सेक्यूरिटी, नागरिक परमाणु समझौता आदि देशद्रोहपूर्ण समझौतों से देश को साम्राज्यवाद के आगे पूरी बेशर्मी से घुटने टेक देना। चौथा, सरकारों द्वारा लागू जन विरोधी और साम्राज्यवादपरस्त नव उदार नीतियों के खिलाफ सुलग रहे जन आंदोलनों और बढ़ते माओवादी क्रांतिकारी आंदोलन का सैनिक रूप से दमन करने के पक्ष में आतंकवाद का डर दिखाकर जनमत को तैयार कर लेना। और सबूतों के बिना ही हर बार इस तरह के विस्फोटों के लिए मुसलमानों और इस्लामिक संगठनों को जिम्मेदार बताकर हिंदू वोट बैंक को मजबूत बनाना तथा रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, विस्थापन जैसी बुनियादी समस्याओं

से देश की जनता का ध्यान बंटाकर अपने शोषणकारी शासन को बेरोकटोक जारी रखना कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए तथा सामंती व दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्गों के लिए, जिनका वे प्रतिनिधित्व करती हैं, जरूरी है।

इसलिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) यह मानती है कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच से ही यह पता लगाना संभव है कि मुम्बई विस्फोटों के लिए जिम्मेदार कौन हैं। हमारी पार्टी देश की जनता और जनवादियों से यह अपील करती है कि वे शासक वर्गों, उनके खुफिया संगठनों और कॉर्पोरेट मीडिया द्वारा जारी उन्मादपूर्ण प्रचार, गलतफहमियों और पूर्वाग्रहों का शिकार न बनें। हमारी पार्टी मांग करती है कि इन विस्फोटों के लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढ़ निकालकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही, हमारी पार्टी देशवासियों का यह आह्वान करती है कि वे सरकारों से यह मांग करें कि 1992 से लेकर अभी तक हुए बम विस्फोट की तमाम घटनाओं पर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जाए तथा जेलों में बंद मुसलमानों और ईसाइयों को बिना शर्त रिहा किया जाए। देश की तमाम जनता से हमारा आग्रह है कि वह बाबरी मस्जिद का विध्वंस, गुजरात नरसंहार, कंधमाल (ओड़िशा) हमलों समेत देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हुए तमाम हमलों के लिए जिम्मेदार भगवा आतंकी सरगनाओं को कड़ी सजा देने की मांग करे तथा हिंदू धार्मिक कट्टरवाद और सभी किस्म के धार्मिक अधराष्ट्रवाद का खण्डन करे।

vHk;

iboDrk] dsUæh; desVh

Hkkjr dh dE;qfuLV ikVhZ ¼ekvksoknh½

ekvkoknh urRo d: f[kykQ y|Vj: 'kk l d oxk vkj dkikjV ehfM;k }kjk pyk, tk jg

tgjhy: n|"iipkj dk jíh d: Vkdj: e: Qd nk!

आज भारत का क्रांतिकारी आंदोलन कठिन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए जीत–हार–जीत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस क्रांतिकारी आंदोलन को जड़ से सफाया करने के लक्ष्य से लुटेरे शासक वर्ग साम्राज्यवादियों के सम्पूर्ण समर्थन से बर्बर दमनकारी युद्ध चला रहे हैं। ये फासीवादी खासकर उस एलआईसी (कम तीव्रता वाला संघर्ष) की रणनीति पर अमल करते हुए प्रति–क्रांतिकारी युद्ध को चला रहे हैं जिसे अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने तैयार किया। खासकर 2009 से यूपीए सरकार ने राज्य सरकारों के साथ तालमेल कर 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के नाम से देशव्यापी दमनकारी युद्ध छेड़ रखा है। सोनिया–मनमोहनसिंह–चिदम्बरम–प्रणब मुखर्जी गिरोह की अगुवाई में देश की जनता के खिलाफ जारी इस अन्यायपूर्ण युद्ध में 'दमन और विकास' (जनता का दमन और कॉर्पोरेट कम्पनियों का विकास समझना चाहिए) को रणनीति के रूप में बताया जा रहा है। इसके अंतर्गत, मनोवैज्ञानिक युद्ध को एक रणनीतिक हथियार के बतौर इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका अहम हिस्सा है क्रांतिकारी आंदोलन के नेतृत्व के खिलाफ दुष्प्रचार। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में मीडिया को एक मुख्य साधन के बतौर इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्पोरेट वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले मीडिया के प्रतिनिधि और शोषक वर्गों की विचारधारा का समर्थन करने वाले छद्‌म बुद्धिजीवी माओवादी आंदोलन पर कीचड़ उछालने वाली इस मुहिम को जारी रखते हुए दुश्मन के मनोवैज्ञानिक युद्ध में बढ़–चढ़कर भाग ले रहे हैं।

क्रांतिकारी आंदोलन का जितना लम्बा इतिहास है क्रांति–विरोधी दुष्प्रचार का भी उतना ही इतिहास है। जर्मनी के फासीवादी प्रचार मंत्री गोबेल्स, जिसने यह बताया था कि एक झूठ को सौ बार दोहराने से वह सच होकर रहेगा, के असली भारतीय अवतार के रूप में सामने आए हुए सोनिया, मनमोहनसिंह, चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, रमन सिंह, नवीन पटनायक, नितीश

कुमार, किरण कुमार आदि शासक तथा अरणाब गोस्वामी, चंदन मित्रा जैसे उनके प्रवक्ता मीडिया के जरिए विभिन्न रूपों में दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं। क्रांतिकारी सिद्धांत मार्क्सवाद के अप्रासंगिक होने से शुरू कर माओवादी नेताओं के बीच तीव्र मतभेद होने के प्रचार तक कोरी कल्पनाओं, झूठों और अर्धसत्यों से क्रांतिकारी आंदोलन के नेतृत्व व नेतृत्वकारी संस्थाओं के खिलाफ आए दिन खबरें प्रकाशित व प्रसारित कर रहे हैं। क्रांतिकारी सिद्धांत पर, क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व करने वाली हमारी पार्टी पर तथा पार्टी नेतृत्व पर गलतफहमियां, संदेह और भ्रम पैदा कर जनता और क्रांतिकारी कतारों को दिग्भ्रमित करना तथा निराशा और अविश्वास फैलाना ही इस दुष्प्रचार मुहिम का एक मात्र लक्ष्य है। लुटेरे शासक और उनका ढिंढ़ोरा पीटने वाले छद्म बुद्धिजीवी यह सपना देख रहे हैं कि इस तरह जनता को भ्रमित कर वे अपना शोषणकारी शासन बेरोकटोक जारी रख सकेंगे और साम्राज्यवाद–परस्त आर्थिक नीतियों को बिना किसी विरोध के लागू कर सकेंगे। इस श्रेणी में आने वाले कुछ पत्रकार खुफिया अधिकारियों से सांठगांठ कर कार्पोरेट मीडिया संस्थाओं के जरिए माओवादी क्रांतिकारी आंदोलन पर कीचड़ उछालते हुए घटिया किस्त की रद्दी को प्रचारित व प्रसारित कर रहे हैं। इसी का हिस्सा है 17 जुलाई 2011 को अंग्रेजी अखबार 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'बिट्टर डिफरेन्सेस क्राप अप बिट्वीन माओइस्ट्स पीडब्ल्यू एण्ड एमसीसी फैक्शन्स' के शीर्षक से छपी घटिया व मनगढ़ंत कहानी।

देश की खुफिया संस्थाओं द्वारा तैयार और राखी चक्रबर्ती द्वारा लिखी गई इस कपोलकल्पित कहानी के अंदर न सिर्फ माओवादी पार्टी के नेतृत्व को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया गया, बल्कि पार्टी में पीडब्ल्यू और एमसीसी गुटों को कृत्रिम तरीके से पैदा कर उनके बीच तीखे मतभेद होने की बात लिखी गई है। देश की उत्पीड़ित जनता और दुनिया भर के क्रांतिकारी कतारों की चिर–प्रतीक्षित आकांक्षाओं के फलस्वरूप, कई समृद्ध अनुभवों के आधार पर तथा 'काला अध्याय' के रूप में चिन्हित किए गए एक पीड़ादायक दौर को पार करके दो क्रांतिकारी पार्टियों के बीच जो एकता निर्मित हुई है वह हमारे देश के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में एक महान व उज्ज्वल अध्याय है। सिर्फ सच्चे और निस्वार्थपूर्ण क्रांतिकारी ही इस तरह अपनी

गलतियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर जनता से माफी मांग सकते हैं और उनकी पुनरावृत्ति न हो, उस दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ काम कर सकते हैं। इसीलिए इस सच्ची एकता से देश व दुनिया भर में उत्पीड़ित जन समुदाय व क्रांतिकारी कतार जितने उत्साहित हुए थे, उतने ही घबरा गए थे भारत के लुटेरे शासक वर्ग और उनके साम्राज्यवादी आका। गौरतलब है कि साम्राज्यवादियों का नमकहलाल गुलाम और देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस ऐतिहासिक एकता की पृष्ठभूमि में ही माओवादी आंदोलन को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताना शुरू किया। यह भी एक अकाट्य सच्चाई है कि इस एकता के बाद से ही देश के शासक गिरोह ने क्रांतिकारी आंदोलन पर अपने फासीवादी हमले को अंधाधुंध बढ़ाया।

शोषक शासक वर्गों की यह बहुत पुरानी चाल है कि क्रांतिकारी पार्टियों के उच्च नेताओं के बीच मनगढ़ंत मतभेद पैदा किया जाए ताकि जनता को यह झूठा एहसास दिलाया जा सके कि क्रांतिकारी आंदोलन के नेताओं में व्याप्त इस तरह के केरीरिज़्म और आपसी अंतरविरोधों के चलते ये पार्टियां भी उसे ठीक से नेतृत्व नहीं दे सकेंगी। दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण गिनाए जा सकते हैं जिनमें से एक है 'टाइम्स आफ इंडिया' में छपी यह खबर जो दशकों से निस्वार्थ रूप से जनता की सेवा कर रहे हमारे नेताओं के खिलाफ चलाए गए बेहद जहरीला दुष्प्रचार मुहिमों में से एक है। उन नेताओं में से कुछ फिलहाल जेलों में कैद हैं जिन्हें सभी सुविधाओं से वंचित कर, बूढ़ी उम्र में भी उन्हें इलाज की सुविधाएं न देते हुए राजसत्ता अपनी अमानवीयता का खुला प्रदर्शन कर रही है। शोषित जनता की मुक्ति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले हमारे नेताओं के प्रति राजसत्ता जो दमनकारी रवैया अपना रही है वह आए दिन अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ रहा है। एक प्रकार से कहा जाए, तो इससे यह साबित होता है कि क्रांतिकारी राजनीति के बढ़ते प्रभाव को लेकर राजसत्ता कितनी आतंकित है और इसे घटाने के लिए वह किस तरह बेकार की चालें चल रही है। हमारे नेतृत्व पर लगाए जा रहे इन तमाम आरोपों को हमारी पार्टी सिरे से खारिज कर देती है और शोषित जनता व क्रांतिकारी शिविर से अपील करती है कि इसमें से एक शब्द पर भी यकीन न करें।

सभी सच्ची क्रांतिकारी पार्टियों में मत भिन्नताएं होती हैं। उनके सदस्यों में सैद्धांतिक, राजनीतिक, सांगठनिक, सैनिक, सांस्कृतिक आदि मामलों को लेकर भिन्न–भिन्न मत रहते हैं। विभिन्न विचारों को लेकर बहसें होती हैं। उन पर हर सदस्य द्वारा अपना मत प्रकट करने के बाद उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। क्रांतिकारी पार्टियों के भीतर लागू इस जनवादी प्रक्रिया को शासक वर्गीय पार्टियों के अंदर न हम कभी देख पाएंगे, न ही वे इसे समझ पाएंगी। इस तरह की बहसों और आलोचना–आत्मालोचना के दौर से गुजरते हुए ही एक क्रांतिकारी पार्टी अपने क्रांतिकारी तत्व को बनाए रख सकती है, न कि किसी नेता का अंधानुसरण करते हुए जैसा कि बुर्जुवाई पार्टियों में होता है। वर्ग संघर्ष के शोलों में तपकर और आलोचना–आत्मालोचना के कई सत्रों में भाग लेकर ही क्रांतिकारी खुद को फौलाद बना लेते हैं। खुफिया संस्थाएं पार्टी के भीतर मौजूद ऐसे स्वस्थ माहौल को तोड़–मरोड़कर उसके ठीक विपरीत में चित्रित करने की कोशिश कर रही हैं। पार्टी के भीतर, वह भी पीडब्ल्यू और एमसीसी गुटों के बीच तीखे मतभेद होने का प्रचार कर रही हैं ताकि जनता और कतारों को भ्रम में डाला जा सके। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी देश और दुनिया की जनता, जनवादियों और क्रांतिकारी कतारों से अपील करती है कि वे इस दुष्प्रचार का पुरजोर खण्डन करें; राजसत्ता द्वारा चली जा रही चालों के प्रति सतर्क रहें; तथा इस दुष्प्रचार को कूड़े के ढेर में फेंककर क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थन में दृढ़तापूर्वक डटे रहें।

आखिर में, हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड गणपति ने पिछले साल अक्टूबर में मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में पीडब्ल्यू और एमसीसी के कथित गुटों के बीच मौजूद कथित मतभेदों पर हो रहे दुष्प्रचार पर टिप्पणी करते हुए जो बात कही थी, उसे इस संदर्भ में भी पेश करना मुनासिब समझते हुए हमारी केन्द्रीय कमेटी इसे फिर एक बार दोहरा रही है।

"...पार्टी में सही विचारों और गलत विचारों के बीच संघर्ष हमेशा रहता है। हम जनवादी केन्द्रीयता और मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद की रोशनी में अपने मतभेदों को हल कर लेते हैं। इसी से हमारी पार्टी के विकास का रास्ता सुगम हो जाता है। विलय के साथ हमने महान एकता हासिल की। अब हमारी पार्टी में चाहे जो भी बहसें हो जाएं और वैचारिक संघर्ष हो जाएं, वे

एक एकताबद्ध पार्टी के भीतर होने वाली राजनीतिक व सैद्धांतिक बहसों के रूप में ही होंगे, पुरानी सीपीआई (एम–एल) (पीपुल्सवार) और पुरानी एमसीसीआई के बीच मतभेदों के रूप में कतई नहीं होंगे। हम निश्चित रूप से कहते हैं कि विलय के पहले वाली झड़प की स्थिति तो कभी नहीं आ सकती।"

vHk;

ioDrk] dUæh; deVh

Hkkjr dh dE;fuLV ikVh ¼ekvkoknh½

iFkd rsyaxkuk jkT; dk Qkju xBu djuk pkfg,! rsyaxkukokfl;ksa dh ^ldy tu gM+rky* dk leFkZu esa 11 vDVwcj 2011 dks ^Hkkjr can* lQy cukvks!

पृथक तेलंगाना राज्य को लेकर तेलंगाना के लोगों में जनवादी आकांक्षा अभूतपूर्व ढंग से उमड़ रही है। तेलंगाना की जनता में जबर्दस्त एकता देखी जा रही है। सरकारी कर्मचारी, सिंगरेनी कोयला खदानों के मजदूर, राज्य परिवहन निगम व बिजली विभाग के मजदूर व कर्मचारी, छात्र, वकील, अध्यापक – सभी की पहलकदमी पर शुरू हुई इस 'सकल जन हड़ताल' *(सकल जनुला सम्मे)* ने दस्तकारों, आटो ड्राइवरों, असंगठित मजदूरों, मुनिसिपल कर्मचारियों, व्यापारियों, पुजारियों, किसानों समेत हर तबके के लोगों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों की भागीदारी से एक व्यापक आम हड़ताल का रूप धारण कर लिया है जोकि दिन–ब–दिन तेज होती जा रही है। इस संघर्ष की व्यापकता को समझने के लिए एक उदाहरण काफी है कि इसमें बूढ़ों से लेकर महिलाओं और बच्चों तक सभी उम्र के लोग भागीदारी ले रहे हैं। सकल जन हड़ताल के प्रभाव को देखते हुए जनता से अलग–थलग पड़ जाने के डर से कांग्रेस, तेलुगुदेशम, भाजपा आदि तेलंगाना क्षेत्र की शासक वर्गीय पार्टियां एक से बढ़कर एक 'इस्तीफों' का नाटक खेल रही हैं जिन्हें मंजूर नहीं किए जाने वाला है। कांग्रेस यह दिखावा कर रही है कि वह अपनी हाई कमान पर दबाव डालकर तेलंगाना राज्य हासिल करने की कोशिश कर रही है। हड़ताल और तेज होने के बाद कांग्रेसी नेता दिल्ली जाकर गुलाम नबी आजाद के साथ सलाह–मशविरा शुरू कर दी जो खुद को तेलंगाना के मसले के हल के लिए कोशिश करने का दावा करते रहे हैं। मामूल की तरह उन्होंने अपनी रिपोर्ट में तेलंगाना के गठन पर फैसला लेने के लिए 'और थोड़ा समय' लगने की बात कहकर फिर एक बार दगा किया। दूसरी ओर तरह–तरह की अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं। सीमा–आंध्र इलाके के धनाढ्य वर्गों से सांठगांठ करने वाली कांग्रेस की हाइ कमान पहले से तय योजनाओं को अमल में लाने की फिराक में है। उसी का हिस्सा है हैदराबाद

को तेलंगाना से अलग कर उसे केन्द्र शासित क्षेत्र या दो राज्यों की साझी राजधानी बनाने की साजिश। इसके अंतर्गत एक तर्क और प्रचारित किया जा रहा है जिसमें हैदराबाद को अलग कर बाकी तेलंगाना के साथ कर्नूल जिले को मिलाकर अलग राज्य बनाने की बात कही जा रही है। इन प्रस्तावों को तेलंगाना की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा है जो एक अकाट्य ऐतिहासिक सच्चाई है। तेलंगानावासियों को चाहिए कि वे ऐसे तेलंगाना का, जिसमें हैदराबाद न हो, गठन करने की साजिशों का एकजुटता के साथ नाकाम कर दें।

19 दिनों से जारी इस जबर्दस्त सकल जन हड़ताल का दमन करने के लिए सरकार तीखे दमन का प्रयोग कर रही है। मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करते हुए एस्मा कानून का प्रयोग; फैक्टरियों, खदानों और दफ्तरों की पुलिस छावनियों में तब्दीली; प्रदर्शनों पर लाठीचार्ज व रबड़ की गोलियों का प्रयोग; तेलंगानावादियों की अवैध गिरफ्तारियों और ध मकियां देने का सिलसिला जारी है। दूसरी ओर वह यह कोशिश भी कर रही है कि तेलंगाना की जनता और तटीय आंध्र क्षेत्र के सेटिलरों के बीच झगड़ा पैदा कर आंदोलन को कुचल दिया जाए। उसी साजिश के मुताबिक हड़ताल के अंदर विघटनकारियों को घुसाकर मजदूरों पर हमले करवा रही है। इसके तहत ही कर्मचारियों के नेता स्वामी गौड़ पर हमला किया गया। इसी साजिश के तहत लगडापाटी राजगोपाल राज्य परिवहन निगम (आरटीसी) के मजदूरों का हालचाल पूछने के नाम पर हैदराबाद आया था जो सीमा–आंध्र के इलाके से भाड़े के ड्राइवरों को लाकर आरटीसी की हड़ताल को तोड़ने में लगा हुआ है। राज्यपाल नरसिंहन, मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी और डीजीपी दिनेश रेड्डी केन्द्र सरकार के आदेश पर सकल जन हड़ताल का दमन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे है। हैदराबाद में कांग्रेसी मंत्री दानम नागेंदर, मुकेश गौड़ और मज़लिस के नेता ओवैसी बंधु पृथक तेलंगाना आंदोलन के खिलाफ खड़े होकर गद्दारी कर रहे हैं। सरकारें और शासक वर्ग 'श्रीकृष्ण कमेटी' की रिपोर्ट के 8वें अध्याय में दिए गए सुझावों पर चलते हुए मीडिया को पूरी तरह नियंत्रित कर रहे हैं ताकि बेहद उच्च स्तर पर चल रही सकल जन हड़ताल का प्रचार आंध्रप्रदेश और देश के दूसरे प्रदेशों में न हो सके। इस तरह वे देश की जनता को अंधेरे में रखकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं।

लोगो, सकल जन हड़ताल को और ज्यादा दृढ़ता व तेजी के साथ जारी रखें। कठिन संघर्षों के लिए तैयार होकर ही तेलंगाना राज्य को हासिल किया जा सकता है। यह मानना बेमानी है कि जनता के न्यूनतम अधिकारों का भी हनन करने वाले ये शासक वर्ग इतनी आसानी से पृथक तेलंगाना राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। पिछले इतिहास से भी यह पता चलता है कि तेलंगाना की जनता को अपने न्यूनतम अधिकारों को हासिल करने के लिए भी कितना खून बहाना पड़ा था। दीर्घकालीन, एकताबद्ध और जुझारू आंदोलनों के लिए तैयार होने और संघर्ष ही एक मात्र रास्ता मानकर आगे बढने से ही केन्द्र सरकार को अलग तेलंगाना देने पर झुकाया जा सकता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि शासक वर्गीय पार्टियां और उनके नेता हमेशा मोलभाव करते हुए हर मौके पर आंदोलन पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं। इन साजिशों का हर कदम पर पर्दाफाश कर हरा देना चाहिए। लम्बे समय से जारी आंदोलन के दौरान आंदोलन के नेतृत्व में आने वाले ढुलमुलपन का समय–समय पर मुकाबला करते हुए आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरस) जिसका दृढ़ विश्वास है कि लॉबीइंग के जरिए ही तेलंगाना राज्य को हासिल किया जा सकता है, मजबूरी में सकल जन हड़ताल में भाग ले रही है ताकि खुद को जनता से अलग–थलग पड़ने से बचाया जा सके। लेकिन दूसरी ओर, उसने सकल जन हड़ताल को गुमराह करने की नीयत से ही बांसवाड़ा उपचुनाव में तेलुगुदेशम से दलबदल करने वाले अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश की। खुद को तेलंगाना राज्य के लिए समर्पित बताने वाली कांग्रेस ने इस चुनाव में उम्मीदवार खड़ाकर अपने अवसरवाद को जाहिर किया। शुरू से तेलंगाना का विरोध करते आ रही तेलुगुदेशम पार्टी द्वारा यह कहकर कि जब तक तेलंगाना नहीं मिलेगा तब तक चुनावों में वह भाग नहीं लेगी, बांसवाड़ा उपचुनावों का बहिष्कार करना उसके घोर अवसरवाद का सबूत भर है। इस मौके पर हमारी पार्टी सभी संयुक्त कर्याचरण समितियों (जेएसी) से अपील करती है कि वे इस सकल जन हड़ताल के दौरान तेलंगाना जनता के अंदर सामने आई एकजुटता के आधार पर आगे बढ़ें तथा वे अपने अंदर विभिन्न मौकों पर सामने आ रहे ढुलमुलपन को दरकिनार कर जनता के जुझारू आंदोलन का सही ढंग से नेतृत्व करें।

'सकल जन हड़ताल' का संघर्षशील प्रभाव आज पूरे देश पर पड़ रहा है।

इससे पृथक राज्य की मांग से जारी विभिन्न आंदोलनों को प्रेरणा मिल रही है। फिलहाल तेलंगाना की जनता के समर्थन में खड़े होना देशवासियों का एक अहम फर्ज बनता है। हमारी पार्टी रायलासीमा और तटीय आंध्र क्षेत्रों के लोगों से तहेदिल से अपील करती है कि वे सकल जन हड़ताल के दौरान उमड़ आई तेलंगाना की जनता की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए पृथक तेलंगाना राज्य की मांग का समर्थन करें तथा वे तेलंगाना और सीमा–आंध्र क्षेत्रों की जनता के बीच फूट डालने की नीयत से जारी शोषक वर्गों की साजिशों का शिकार न बनते हुए इस जनवादी मांग का स्वागत करें।

इस मौके पर हमारी पार्टी तेलंगाना की जनता की पुरजोर मांग को मानकर पृथक तेलंगाना राज्य का तत्काल गठन करने की मांग करते हुए तथा सकल जन हड़ताल के समर्थन में 11 अक्टूबर 2011 को 'भारत बंद' का आह्वान करती है। हम मजदूरों, किसानों, छात्रों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, जनवादियों, प्रगतिशील जन संगठनों व व्यक्तियों, कवियों, कलाकारों समेत तमाम जन समुदायों से अपील करते हैं कि भारत बंद को सफल बनाया जाए। हम समूचे देशवासियों से अपील करते हैं कि दफ्तरों, शिक्षा संस्थानों और कारोबार को बंद रखकर तेलंगाना की जनता के पृथक राज्य आंदोलन के प्रति भाईचारा प्रकट करें।

i:rki	vHk;
ioDrk	ioDrk
e/; jhtuy C;jks	dUnh; deVh
Hkkdik ¼ekvksoknh½	Hkkdik ¼ekvksoknh½

turk ij ;|) ^vkij'ku xhugV* dk ijkLr dju d y{; l tu;|) dk rt djk!

ih,yth, dh 11oh o"kxkB d miy{; e Hkkdik ¼ekvkoknh½ lVy fefyVjh dfe'ku dk lnk'k

प्यारे लोगो!

2 दिसम्बर तक जनमुक्ति छापामार सेना के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर केन्द्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) यह आह्वान करता है कि अपने तमाम गुरिल्ला जोनों और लाल प्रतिरोधी इलाकों में लुटेरे शासक वर्गों के आपरेशन ग्रीनहंट को परास्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ 11वीं वर्षगांठ को मनाया जाए। पिछले साल में भारत में शोषित जनता की मुक्ति के लिए जारी जनयुद्ध में लगभग 150 उत्तम बेटियों, बेटों और आम जनता ने अपने अनमोल प्राणों को न्यौछावर किया है। आइए, इन तमाम वीर शहीदों को क्रांतिकारी श्रद्धांजली पेश करें और उनके अधूरे मकसद को पूरा करने की कसम खाएं।

इस एक साल में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय जन संगठनों व क्रांतिकारी जन कमेटियों के कार्यकर्ताओं और आम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर काले कानूनों के तहत जेल में कैद किया। क्रांतिकारी सांस्कृतिक आंदोलन का दमन करने के लिए झारखण्ड एभेन के प्रमुख कॉ. जीतन मरांडी समेत चार अन्य को फांसी की सजा सुनाई। खासकर हमारी पार्टी के नेतृत्व को खत्म करने की मंशा से जारी खुफिया शिकारी कुत्तों के अभियान में 29 अप्रैल 2011 को तीन केन्द्रीय कमेटी सदस्य, जून महीने में पोलिटब्यूरो सदस्य कॉ. भूपेश दा और अन्य नेतृत्वकारी कॉमरेड पकड़े गए जिन्हें जीवन भर के लिए जेलों में कैद करने की साजिशें की जा रही हैं। सीएमसी जनता का यह आह्वान करता है कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए जहां–तहां संघर्ष चलाया जाए।

फासीवादी आपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ देश भर में हमारे पीएलजीए बलों ने पिछले दिसम्बर से अक्तूबर तक दुश्मन के 150 सशस्त्र बलों का सफाया कर, 180 को घायल कर उनसे 60हथियार छीन लेने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा पीएलजीए बलों द्वारा लगातार की गई एकल कार्रवाइयों में 170 विरोधियों का सफाया किया गया। इसमें जन मिलिशिया बलों की भूमिका विशेष रूप

से उल्लेखनीय है।

केंद्र व राज्य सरकारों ने यह घोषणा की है कि फिलहाल ऑपरेशन ग्रीनहंट का दूसरा चरण जारी है। यह सर्वविदित है कि 2009 के मध्य से सोनिया–मनमोहन–चिदम्बरम गिरोह द्वारा देश की जनता के खिलाफ शुरू किए गए इस अन्यायपूर्ण युद्ध (ऑपरेशन ग्रीनहंट) का मकसद आदिवासी इलाकों में छिपी हुई खनिज संपदाओं को दलाल पूंजीपतियों व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले करना ही है। जनता पर जारी इस युद्ध को और ज्यादा पाशविकता के साथ जारी रखने के लिए सरकार ने मई के आखिर में प्रशिक्षण के नाम पर दण्डकारण्य में ब्रिगेड के स्तर पर सेना को उतार दिया। दरअसल कार्पोरेट लूटखसोट की राह में बाधा के रूप में खड़े क्रांतिकारी आंदोलन का सफाया करने के लक्ष्य से पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा चलाए जा रहे काउण्टर इंसर्जेन्सी ऑपरेशन्स का सैन्य अधिकारी पिछले छह सालों से मार्गदर्शन कर रहे हैं। दण्डकारण्य के कांकेर और उत्तर छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर में सेना खुद ही काउण्टर टेर्ररिज्म जंगल वारफेर स्कूलें खोलकर पुलिस व अर्धसैनिक बलों को प्रशिक्षण दे रही है। सेना के आला अधिकारियों ने बस्तर में कई बार दौरे किए। जब सलवा जुडूम बेहद क्रूरता के साथ चलाया जा रहा था, उसी दौरान अमेरिकी कान्सुलेट के अधिकारियों द्वारा कांकेर के जंगल वारफेर स्कूल का कई दफे दौरा करना तथा रायपुर में रमनसिंह व पुलिस के आला अधिकारियों के साथ सलाह–मशविरा करना इस बात का पुख़्ता सबूत है कि यह अमेरिकी साम्राज्यवादियों के मार्गदर्शन में ही चल रहा था।

फासीवादी आपरेशन ग्रीन हंट सैनिक हमले के तहत जनता पर हमले, हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, गांव दहन, लूटपाट, फसलों की तबाही, मुरगियां, सुअर, बकरे आदि पालतू जानवरों को लूटना आम हो गया। दण्डकारण्य के चिंतलनार इलाके में हत्या, अत्याचार, गांव दहन व लूटपाट; पश्चिम बंगाल के लालगढ़ इलाके के नेताई गांव में सीपीएम के गुण्डों द्वारा केन्द्र–राज्य संयुक्त बलों की मदद से किया गया कत्लेआम; और झारखण्ड के गुमला जिले के जामगाई गांव में पीएलएफआई के गुण्डों द्वारा किया गया हत्याकाण्ड इसका ठोस प्रमाण है। प्रति–क्रांतिकारी सलवा जुडूम, सेंदरा, नागरिक सुरक्षा समिति, शांति संघ, बिहार व झारखण्ड में कई किस्म के हत्यारे गिरोहों और सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा मारे जाने वालों में 99 प्रतिशत निहत्थी जनता ही है। हमलों, मुठभेड़ों व फर्जी मुठभेड़ों में मारे जाने वालों में सशस्त्र गुरिल्लों की संख्या 1

प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। यह इस बात का बड़ा सबूत है कि यह सचमुच जनता पर जारी युद्ध है।

दण्डकारण्य को माओवादी छापामारों के मुख्यालय के रूप में चित्रित करते हुए, आदिवासी इलाकों में लागू जमीन हस्तांतरण निषेध कानून, पेसा कानून व ग्रामसभा कानून का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन करते हुए सेना की तैनाती कर वहां के प्राचीन मानव समुदायों को विस्थापित करने की साजिश की जा रही है। इस तरह उनकी आदिम संस्कृति और माओवादियों की अगुवाई में स्थापित की जा रही उनकी जनताना सरकार का सफाया करने की साजिश भी की जा रही है। इस केलिए केन्द्र सरकार ने भारतीय सेना को 'सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून' के अधिकांश प्रावधानों के अलावा आत्मरक्षा के नाम पर कुछ भी करने के लिए तमाम जरूरी अधिकार दे दिए। कथित रूप से देश की सरहदों की रक्षा करने वाली सेना देश के बीचोबीच अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो गई। कश्मीर और पूर्वोत्तर की रष्ट्रीयताओं के संघर्षों पर भारतीय सेना व अर्धसैनिक बलों द्वारा किए गए हत्याकाण्डों और अत्याचारों का अब मध्य भारत में विस्तार कर साम्राज्यवादियों और बहुराष्ट्रीय के हितों को पूरा करने की भारत के शासक वर्गों के खिलाफ देश भर के आदिवासी जन समुदायों को आंदोलन में उतरना चाहिए। सभी तबकों की जनता, जनवादियों, देशभक्तों और जन संगठनों इनके समर्थन में खड़े हों।

प्यारे लोगो!

साम्राज्यवादी एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण व भूमण्डलीकरण) की नीतियों और विकृत विकास के फलस्वरूप दुनिया भर में बढ़ी हुई आर्थिक मंदी का प्रभाव हमारे देश पर भी है। भ्रष्टाचार का बढ़ना, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, विस्थापन की नीतियों के चलते जमीनों, जंगलों और पानी पर जनता का हक छिन जाना आदि कारणों से मजदूरों, किसानों और मध्यम वर्गीय जनता का जीवन स्तर दूभर हो जाने से उनके सामने क्रांति के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। क्रांति के लिए वस्तुत हालात परिपक्व बन रहे हैं। सभी तबकों के लोग हड़तालों और आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं। आर्थिक संघर्ष राजनीतिक संघर्षों का रूप धारण कर रहे हैं। आदिवासी किसानों के राजनीतिक आंदोलन तीव्र रूप धारण कर रहे हैं। लालगढ़, कलिंगनगर, नारायणपटना, पोस्को–विरोधी संघर्ष, नियमगिरी, माली–देवमाली, सिंगरेणी ओपेनकास्ट, पोलावरम, सोम्पेटा, काकरापल्ली,

जैतापुर, ग्रेटर नोइडा आदि संघर्ष, झारखण्ड में शहरी विकास के नाम पर विस्थापित होने वाले लोगों का संघर्ष, देश भर में सेज के खिलाफ संघर्ष, महंगाई व भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष, किसानों के संघर्ष, दलितों व महिलाओं के संघर्ष आदि जनता की बढ़ती राजनीतिक चेतना को प्रतिबिम्बित करते हैं। पृथक तेलंगाणा राज्य की मांग को लेकर जनता जुझारू संघर्ष कर रही है। कश्मीरी जनता का राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष सुलग ही रहा है। साम्राज्यवादियों की देखरेख में चलने वाले गैर–सरकारी संगठन अन्ना हजारे जैसे शख़्सों के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन के तौर पर भूख हड़तालों का आयोजन करवा रहे हैं ताकि जनता के जुझारू संघर्षों को गुमराह किया जा सके। शोषित जनता के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ी माओवादी पार्टी पर तथा विभिन्न आंदोलनों में भाग ले रहे मजदूरों, किसानों व मध्यम वर्ग की जनता पर शोषक शासकों का फासीवादी दमनचक्र बढ़ रहा है। आर्थिक व राजनीतिक संकट जब हर तरफ तीखा हो रहा हो, ऐसे हालात में व्यापक जनता को चाहिए कि वह क्रांतिकारी विचारों से लैस होकर आखिरी दम तक संघर्ष के नारे से जन आंदोलनों को तेज करे। रोजमर्रा की समस्याओं से राजनीतिक समस्याओं तक सभी में बड़े पैमाने पर गोलबंद होना चाहिए। राजनीतिक संघर्षों को निश्चयपूर्वक जारी रखे बिना उत्पीड़ित जनता के लिए अपने आर्थिक हितों को साधना संभव नहीं है। इन आंदोलनों को ''जनयुद्ध के जरिए राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करो'' के नारे से जोड़कर उन्नत स्तर में विकसित करना चाहिए।

केन्द्रीय मिलिटरी कमिशन का आह्वानः

मजदूरो, किसानो, आदिवासियो, मेहनतकशो, महिलाओ, छात्रो, नौजवानो व बुद्धिजीवियो! केन्द्र व राज्य सरकारों से जानी जनता पर युद्ध 'आपरेशन ग्रीनहंट' को हराने के लिए कई आंदोलन देशभर चल रहे हैं। इसमें हजारों की संख्या में जनता, खासकर आदिवासी किसान गोलबंद हो रहे हैं। इस संघर्षों में सभी पीडित वर्ग व तबकों के जनता शामिल हो जावें! सभी आदिवासियों पर आतंकवादी का ठप्पा लगाकर राजसत्ता भेड़िए की तरह टूट पड़ रही है। आदिवासियों का सैकड़ों की संख्या में कत्लेआम कर उनका सब कुछ लूट रहे भाड़े के पुलिस बलों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सक्रिय रूप से आगे आएं! माओवादी हिंसावादी नहीं हैं। दरअसल वे शांति को चाहने वालों में आगे रहेंगे। उन पर जहर उगलने वाले बुर्जुवाई प्रचार साधनों के दुष्प्रचार पर विश्वास मत करें! आप क्रांतिकारी आंदोलन का पक्ष लें! अगर इस शत्रु–हमले को हम

नहीं हराते हैं और माओवादी पार्टी, जन मुक्ति गुरिल्ला सेना, वैकल्पिक राजसत्ता के संगठनों व जन संगठनों का सफाया करने की दुश्मन की साजिशों को अगर हम नाकाम नहीं करते हैं तो क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा प्राप्त अनमोल नतीजे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए दुश्मन को अलग–थलग कर परास्त करने में आपके हिस्से की भूमिका निभाएं! पीएलजीए में बड़े पैमाने पर भर्ती होकर जन सेना की शक्ति को कई गुना बढ़ाकर उसे मजबूत बनाएं! 'जमीन', 'राजसत्ता', 'जनवाद', 'जन सेना का निर्माण', 'स्वावलम्बन' आदि नारों के साथ आज देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर चल रहे जन आंदोलनों के साथ एकजुट होवें! उनके कंधे से कंधा मिलाएं! पीएलजीए द्वारा अपनाए जा रहे प्रतिरोधी संघर्षों में हिस्सा लें! लुटेरे वर्गों को जड़ से खत्म किए बिना कोई बुनियादी बदलाव नहीं आने वाला है। उनके द्वारा फेंके जाने वाले जूठन के टुकड़ों जैसे सुधारों से जनता का जीवन और ज्यादा बर्बाद ही होगा, न कि उनसे कोई फायदा होगा। जनता की एकता को तोड़ने की साजिश के तहत ही इन सुधारों को लाया जा रहा है – इस सच्चाई को जनता में प्रचारित करते हुए उन्हें ठुकरा देंगे! वैकल्पिक नई जनवादी व्यवस्था के लिए कदम बढ़ाएंगे! आइए, लड़ने का साहस करेंगे तो अंतिम जीत जनता की ही है!

★ दण्डकारण्य व बिहार–झारखण्ड को आधार इलाका बनाने के लक्ष्य से पीएलजीए को पीएलए में तथा गुरिल्ला युद्ध को चलायमान युद्ध में विकसित करो!

★ माओवादी आंदोलन के उन्मूलन के लिए भारत के लुटेरे शासक वर्गों द्वारा प्रशिक्षण के बहाने सेना को उतारने का विरोध करो!

★ महान जनयुद्ध के जरिए–भारत के पीडित जनता पर लूट, उत्पीडन, दमन चलानेवाली भाडे सेना को सबक सिखाओ!

★ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जिंदाबाद!

noth

lsaVªy fefyVjh dfe'ku ds rjQ ls]

Hkkjr dh dE;qfuLV ikVhZ ¼ekvksoknh½

'kksf"kr turk ds l;kjs liwr]
Hkkjrh; Økafr ds usrk vkSj
Hkkdik ¼ekvksoknh½ ds iksfyVC;wjks lnL;
dkWejsM eYyks tqyk dksVs'oj jko
¼fd'kuth@jketh½
dh ccZj gR;k dk iqjtksj fojks/k djks!
29 uoEcj ls 5 fnlEcj rd ns'kO;kih fojks/k lIrkg rFkk 4&5 fnlEcj dks 48&?k.Vs dk ^Hkkjr cUn* dks lQy cukvks!!

24 नवम्बर 2011 का दिन भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में काले दिन के रूप में अंकित हुआ है। भाकपा (माओवादी) को 'देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा' के रूप में प्रचारित करते हुए देशव्यापी दमनचक्र व शोषित जनता के खिलाफ अन्यायपूर्ण युद्ध छेड़ने वाले फासीवादी सोनिया–मनमोहन सिंह–प्रणब–चिदम्बरम– जयराम रमेश शासक गिरोह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सांठगांठ कर एक षड़यंत्र के तहत कॉमरेड कोटेश्वर राव को जिंदा पकड़कर कत्ल किया। पिछले साल 1 जुलाई को पार्टी के प्रवक्ता कॉमरेड आजाद की हत्या कर चुके इस गिरोह ने फिर एक बार पंजा मारकर अपनी खून की प्यास बुझा डाली। कॉमरेड आजाद की हत्या पर मगरमच्छ के आंसू बहाई ममता बनर्जी ने सत्ता में आने के बाद एक तरफ माओवादी पार्टी के साथ 'शांति वार्ता' का ढोंग करते हुए ही दूसरी ओर एक अन्य अग्रणी नेता कॉमरेड कोटेश्वर राव की हत्या कर अपने जन विरोधी व फासीवादी चेहरे पर से मुखौटा हटा लिया। केन्द्रीय खुफिया संस्थाओं, पश्चिम बंगाल व आंध्रप्रदेश की हत्यारी खुफिया संस्थाओं ने बड़ी सोची–समझी साजिश के तहत उनका पीछा किया और एक संयुक्त ऑपरेशन में उनकी कायराना हत्या करके मुठभेड़ की मनगढंत कहानी फैला

दी। केन्द्रीय गुह सचिव आर.के. सिंह ने जहां एक तरफ यह घोषणा की कि मुठभेड़ में मारे जाने वाले व्यक्ति के बारे में शत प्रतिशत कहना मुश्किल है क्योंकि उसकी शिनाख़्त करना बाकी है, वहीं दूसरी ओर यह कहकर कि इससे माओवादी आंदोलन को बड़ा झटका लगा, इस हत्या के पीछे की साजिश की ओर खुद ही इंगित किया। लुटेरे शासक वर्गों और उनका मार्गदर्शन करने वाले साम्राज्यवादियों को, जो यह दिवास्वप्न देख रहे हैं कि वे क्रांतिकारी आंदोलन के उच्च नेतृत्व की हत्या कर माओवादी पार्टी का जड़ से सफाया कर सकेंगे, शोषित जनता जनयुद्ध के जरिए जरूर दफना देगी।

पार्टी और जनता के बीच प्रह्लाद, रामजी, किशनजी, बिमल आदि नामों से लोकप्रिय कॉमरेड कोटेश्वर भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। पिछले 37 सालों से एक अथक योद्धा के रूप में, उठाई हुई बंदूक को कभी नीचे न रखते हुए, शोषित जनता की मुक्ति के लिए लड़ते हुए अपने सिद्धांत व उसूलों की खातिर जान कुरबान करने वाले कॉमरेड कोटेश्वर का जन्म 1954 में आंध्रप्रदेश के उत्तर तेलंगाना क्षेत्र में आने वाले जिला करीमनगर के पेद्दापल्ली कस्बे में हुआ था। पिता वेंकटैया, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे और मां मधुरम्मा, जो प्रगतिशील विचारों वाली महिला हैं, के लालन–पोषण में पले–बढ़े कॉमरेड कोटेश्वर में बचपन से ही देश और देश की मेहनतकश जनता के प्रति प्रेम की भावना पैदा हुई। पेद्दापल्ली कस्बे में हाईस्कूल की पढ़ाई करने के दौरान 1969 में उभार के रूप में सामने आए पृथक तेलंगाना आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। करीमनगर के एसआरआर महाविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई के दौरान महान नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम के संघर्षों से प्रेरित होकर वे क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े थे। 1974 से उन्होंने पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। आपातकाल के अंधेरे दौर में कुछ समय के लिए जेल जाने वाले कॉमरेड कोटेश्वर ने आपातकाल को हटाने के बाद पार्टी संगठनकर्ता के रूप में अपने गृह जिला करीमनगर की जनता के बीच कामकाज शुरू किया। पार्टी द्वारा दिए गए 'चलो गांवों की ओर' के आह्वान को पाकर गांवों में जाकर उन्होंने किसानों के साथ संपर्क कायम कर लिया। 1978 में 'जगित्याल जैत्रयात्रा' के रूप में मशहूर हुए किसान आंदोलन के उभार में प्रमुख भूमिका निभाने वालों में वे एक थे। उसी सिलसिले में वे भाकपा (मा–ले) की आदिलाबाद–करीमनगर संयुक्त जिला कमेटी के सदस्य के रूप में चुन लिए

गए थे। 1979 में जब यह कमेटी दो कमेटियों के रूप में अलग हुई थी तो उन्हें करीमनगर जिला कमेटी के सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। 1980 में आयोजित आंध्रप्रदेश के 12वें राज्य अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था जहां उन्हें राज्य कमेटी में चुन लिया गया था और उसके सचिव बनाया गया था।

1985 तक एपी राज्य कमेटी के नेतृत्व में प्रदेश भर में आंदोलन का विस्तार करने में तथा गुरिल्ला जोन के लक्ष्य से जारी उत्तर तेलंगाना के आंदोलन को विकसित करने में कॉमरेड कोटेश्वर ने अहम भूमिका निभाई। 1980 में दण्डकारण्य में क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार करने और उसे विकसित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1986 में वे स्थानांतरित होकर दण्डकारण्य आंदोलन में शामिल हो गए जहां उन्होंने फॉरेस्ट कमेटी सदस्य की जिम्मेदारी उठाई। दण्डकारण्य में उन्होंने गुरिल्ला दस्तों और जनता का नेतृत्व व मार्गदर्शन किया। 1993 में उन्हें पार्टी की केन्द्रीय सांगठनिक कमेटी (सी.ओ.सी.) के सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया।

1994 से उन्होंने खास तौर से बंगाल समेत पूर्वी और उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार व विकास में योगदान दिया। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, जहां नक्सलबाड़ी आंदोलन के पीछे हटने के बाद कई टुकड़ों में बिखर चुकी क्रांतिकारी शक्तियों को एकजुट कर क्रांतिकारी आंदोलन का पुनरनिर्माण करने में उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल की शोषित जनता से तथा क्रांतिकारी खेमे के अंदर विभिन्न तबकों से घनिष्ठता के साथ घुलमिलकर, बंग्ला भाषा को दृढ़ संकल्प के साथ सीखकर उन्होंने वहां की जनता के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी। कई क्रांतिकारी ग्रुपों से एकता कायम करने और पार्टी को मजबूत करने में उन्होंने अथक परिश्रम किया। इस दौरान 1995 में आयोजित पुरानी भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) के अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन में उन्हें केन्द्रीय कमेटी के सदस्य के रूप में चुन लिया गया। 1998 में पीपुल्सवार और पार्टी यूनिटी के बीच एकता कायम करने में उन्होंने मजबूती से काम किया। 2001 में आयोजित पुरानी भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) पार्टी की कांग्रेस में उन्हें फिर से केन्द्रीय कमेटी सदस्य के रूप में चुन लिया गया और पोलिटब्यूरो सदस्य चुन लिया गया। उत्तर रीजनल ब्यूरो सचिव की जिम्मेदारी लेकर उन्होंने बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया। उसी समय पुरानी भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) और एमसीसीआई के

बीच चली एकता वार्ता में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 2004 में दो पार्टियों के विलय के बाद गठित एकीकृत केन्द्रीय कमेटी और पोलिटब्यूरो में सदस्य बनकर उन्होंने पूर्वी रीजनल ब्यूरो (ई.आर.बी.) के अंतर्गत काम किया। पश्चिम बंगाल राज्य के आंदोलन पर प्रधान रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए वे ई.आर. बी. के प्रवक्ता के रूप में बने रहे।

पार्टी में उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं के संचालन और राजनीतिक शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रमुख भूमिका निभाई। 'क्रांति', 'एर्राजेंडा', 'जंग', 'प्रभात', 'वैनगॉर्ड' आदि पत्रिकाओं के संचालन में उनका योगदान रहा। पश्चिम बंगाल से प्रकाशित कई क्रांतिकारी पत्रिकाओं के पीछे उनका खासा योगदान रहा। इन पत्रिकाओं में उन्होंने कई सैद्धांतिक व राजनीतिक लेख लिखे थे। पार्टी के अंदर राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिए बनी सब–कमेटी में सदस्य रहकर कॉमरेड कोटेश्वर ने पार्टी के कतारों को मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद विचारधारा पर शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई। पार्टी के समूचे इतिहास में देखा जाए तो, क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार में, पार्टी के दस्तावेजों को समृद्ध बनाने में और आंदोलन को विकसित करने में उनकी भूमिका अविस्मरणीय रही। जनवरी 2007 में आयोजित पार्टी की एकता कांग्रेस – 9वीं कांग्रेस में उन्हें फिर से केन्द्रीय कमेटी सदस्य के रूप में चुन लिया गया और आखिर तक उन्होंने पोलिटब्यूरो व पूर्वी रीजनल ब्यूरो में सदस्य के तौर पर काम किया।

पश्चिम बंगाल में सामाजिक फासीवादी सीपीएम सरकार द्वारा लागू जन विरोधी व कॉर्पोरेट–परस्त नीतियों के खिलाफ 2007 से सिंगूर और नंदिग्राम में भड़क उठे जन आंदोलनों, खासकर पुलिसिया अत्याचारों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के लालगढ़ इलाके में एक जबर्दस्त उफान के रूप में उठे जन विद्रोह को उन्होंने राजनीतिक मार्गदर्शन दिया जोकि काफी महत्वपूर्ण था। बंगाल की राज्य कमेटी और पार्टी के कतारों को इन आंदोलनों का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करते हुए ही उन्होंने मीडिया के माध्यम से पार्टी के प्रचार–कार्य को भी पहलकदमी के साथ संचालित किया। 2009 में जब चिदम्बरम गिरोह वार्ता के नाम से, संघर्ष विराम के नाम से जनता को, खासकर मध्यम वर्ग को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, तब उसका पर्दाफाश करने में कॉमरेड कोटेश्वर ने खासा योगदान दिया। कदम–कदम पर जनयुद्ध की अहमियत को ऊंचा उठाए रखते हुए क्रांतिकारी राजनीति को

जनता में फैलाने के लिए असीम प्रयास किए। इस तरह करीब चार दशकों तक अनवरत जारी उनका क्रांतिकारी प्रस्थान 24 नवम्बर 2011 को अचानक समाप्त हुआ।

ykxk! tuokni lnk!!

इस बर्बर हत्या का सभी को खण्डन करना चाहिए। शासक वर्गों की साजिश यही है कि क्रांतिकारी नेतृत्व का सफाया कर देश की शोषित जनता को सही मार्गदर्शन और सर्वहारा नेतृत्व से वंचित किया जाए। साफ जाहिर है कि देश को मनमाने ढंग से लूटने–खसोटने में तथा यहां के जल–जंगल–जमीन को बड़े व विदेशी पूंजीपतियों के हाथों में सौंपकर अपने हिस्से की दलाली की मोटी रकम को स्विस बैंकों में छुपाने में इन महाचोरों और दलालों के लिए माओवादी आंदोलन ही सबसे बड़ा रोड़ा है। इसीलिए वे आपरेशन ग्रीनहंट के नाम से पिछले दो सालों से चौतरफा व देशव्यापी बर्बर अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत हुई है यह निर्मम हत्या। आज तमाम देशभक्तिपूर्ण व स्वतंत्रताप्रेमी जनता का यह कर्तव्य बनता है कि क्रांतिकारी आंदोलन और क्रांतिकारी नेतृत्व की आंख की पुतली के समान रक्षा की जाए। इस तरह रक्षा करने का मतलब है देश और हमारी भावी पीढ़ियों के भविष्य को बचाना।

57 साल की उम्र में, कठोर गुरिल्ला जीवन में युवाओं से भी होड़ लगाते हुए, जहां भी रहें वहां के सभी कार्यकर्ताओं और जनता में उत्साह का संचार करने वाले कॉमरेड कोटेश्वर राव का जीवन खासकर आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। वे बिना किसी आराम के घण्टों तक अध्ययन और पार्टी के अन्य कामों में भाग लेते थे। लम्बी दूरियों की परवाह न करते हुए, कम सोते हुए, सादा–सीधा जीवन बिताते हुए, ज्यादा मेहनत करने वाले शख़्स थे वे। हर उम्र के लोगों से तथा विभिन्न किस्म की सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले कॉमरेडों से आसानी से घुलते–मिलते हुए सभी में क्रांतिकारी जोश भर देते थे। इस बात में जरा भी शक नहीं कि कॉमरेड कोटेश्वर की मौत से भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को गंभीर नुकसान हुआ है। लेकिन जनता महान है। इतिहास का निर्माता है। जनता और जन आंदोलनों ने ही कोटेश्वर राव जैसे साहसिक व समर्पित क्रांतिकारियों को पैदा किया। उनके अधूरे उद्देश्यों की स्फूर्तिभावना से तथा जगित्याल से जंगलमहल के जंगलों तक

फैलाई गई क्रांतिकारी सुगंध से सशस्त्र होकर मजदूर–किसान और क्रांतिकारी भारत के नए जनवादी क्रांतिकारी आंदोलन को विजय–पथ पर अवश्य आगे बढ़ाएंगे। साम्राज्यवादियों, उनके गुर्गे भारत के सामंती व दलाल पूंजीपति वर्गों और सोनिया, मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, ममता बनर्जी वगैरह उनके प्रतिनिधियों का नामोनिशान तक मिटा देंगे।

हमारी केन्द्रीय कमेटी समूचे देशवासियों से यह अपील करती है कि कॉमरेड कोटेश्वर राव की बर्बर हत्या के विरोध में 29 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक 'विरोध सप्ताह' तथा 4–5 दिसम्बर को 48 घण्टे का 'भारत बंद' सफल बनाया जाए। विरोध सप्ताह के दौरान इस हत्या का खण्डन करते हुए सभा, जुलूस, धरना, काली पट्टियां लगा लेना, चक्का जाम जैसे विभिन्न कार्यक्रम अपनाने का हम आग्रह करते हैं। 4 और 5 दिसम्बर को आयोजित 'भारत बंद' के दौरान रेल, सड़क यातायात, शिक्षा संस्थानों, व्यापार–कारोबार और सभी किस्म की औद्योगिक गतिविधियों को बंद रखा जाए। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं को हम बंद से मुक्त रखेंगे।

vHk;

izoDrk] dsUæh; desVh

Hkkjr dh dE;qfuLV ikVhZ ¼ekvksoknh½

सब्यसाची पण्डा द्वारा शासक वर्गों के सुर में सुर मिलाते हुए हमारी पार्टी के खिलाफ लगाए गए तमाम जहरीले, बेबुनियाद और झूठे आरोपों को भाकपा (माओवादी) सिरे से खारिज कर देती है! और गद्दारी के लिए उसे पार्टी से बहिष्कार करती है!

हमारी ओड़िशा सांगठनिक कमेटी (एस.ओ.सी.) के सचिव सब्यसाची पण्डा ने हमारी पार्टी के महासचिव के नाम 16 पृष्ठों वाला पत्र लिखकर 14 मई 2012 को मीडिया में जारी कर दिया। इस पत्र में उसने शासक वर्गों के सुर में सुर मिलाकर भाकपा (माओवादी) और उसकी अगुवाई में जारी क्रांतिकारी आंदोलन पर जहर उगलते हुए कोरी कल्पनाओं से कई बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए। पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की बुरी नीयत से उसने इस पत्र को जारी कर मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद तथा सर्वहारा की अगुवा पार्टी से खुद को अलग कर लिया। पार्टी छोड़ने और जनयुद्ध की लाइन व क्रांतिकारी व्यवहार को त्यागने की खुलेआम घोषणा कर उसने अपने नव संशोधनवादी चेहरे को उजागर किया। उसने अत्यंत निंदनीय, नीचतापूर्ण व षड़यंत्रकारी तरीकों से पार्टी, क्रांति, शोषित जनता, खासकर ओड़िशा की शोषित जनता की मुक्ति से जुड़े महान उद्देश्यों के साथ विश्वासघात कर खुद को गद्दार साबित किया।

सब्यसाची पण्डा ने पहले कुछ समय तक सीपीएम में और उसके बाद सीपीआई (मा.ले.) (लिबरेशन) में काम किया था। बाद में क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित होकर उसने दक्षिणपंथी लिबरेशन पार्टी को छोड़कर 1998 में भाकपा (मा.ले.) (पार्टी यूनिटी) में प्रवेश किया। क्रांतिकारी पार्टियों की एकता से वह भाकपा (मा.ले.) (पीपुल्सवार) और उसके बाद भाकपा (माओवादी) में बना रहा। 2003–05 के बीच ए.ओ.बी. एस.जेड.सी. सदस्य के रूप में, 2005 से

ओड़िशा राज्य सांगठनिक कमेटी सदस्य के रूप में और 2008 से उस कमेटी के सचिव के रूप में काम करता रहा। क्रांतिकारी पार्टी में 15 साल के लम्बे अंतराल तक काम करने के बावजूद खुद को एक असली सर्वहारा क्रांतिकारी के रूप में ढालने में वह विफल रहा। उसके क्रांति–विरोधी व अवसरवादी राजनीतिक विचारों, रुझानों और व्यवहार की साथियों, कैडरों और सी.सी. कामरेडों ने कई बार आलोचना की। पिछले दिसम्बर में जब राज्य स्तर का विशेष प्लीनम आयोजित किया गया था, उसमें उसके खिलाफ कई आलोचनाएं उठी थीं। लेकिन उसने उनमें से कुछ को रस्मी तौर पर स्वीकार कर बाकी को टालमटोल कर दिया। एक सच्चे सर्वहारा क्रांतिकारी के तौर पर अपनी गलतियों को ईमानदारी से चिन्हित कर सुधार लेने की बजाए वह एक कायर की तरह क्रांतिकारी आंदोलन से भाग गया।

उसके 16 पृष्ठों वाले पत्र में झूठ, विकृतियां और सच को तोड़ने–मरोड़ने वाले कुतर्क ही थे, जबकि रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं कि इस पत्र को उसने ओड़िशा में हमारी पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन को कमजोर कर, छिन्न–भिन्न कर, विनाश करने की ही नीयत से लिखा था। यह किसी से छिपी नहीं है कि महान क्रांतिकारी लक्ष्य को समर्पित, असीम कुरबानियों से नहीं डरने वाली, निस्वार्थ रूप से काम करने वाली, देश की मुक्ति के लिए कटिबद्ध और शोषित जनता के लिए आशा की किरण के रूप में हमारी पार्टी को प्राप्त प्रतिष्ठा को ध्वस्त कर, शासक वर्गों की सेवा में संलग्न होकर अपनी स्वार्थ राजनीति को साधने की बुरी मंशा ही पण्डा के इस पत्र के पीछे निहित थी। इतिहास में ऐसा अक्सर देखा गया है कि शासक वर्ग पण्डा जैसे लोगों को इस भ्रम के साथ सामने लाते हैं कि इससे क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ जारी अपने दुष्प्रचार को वैधता मिल जाएगी। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरूआत से देखा जाए तो दुश्मन ने पण्डा जैसे अवसरवादियों को सामने रखकर इस तरह की कोरी कल्पनाओं के सहारे कामरेड्स चारु मजुमदार, कन्नाई चटर्जी आदि हमारे कई नेताओं पर, पार्टी पर तथा क्रांतिकारी आंदोलन पर कई बार हमले किए थे।

पण्डा द्वारा लगाए गए आरोपों की तह में जाने से पहले हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी समय–समय पर बैठकें, प्लीनम और अधिवेशन चलाती रहती है ताकि अपने कार्याचरण को सुधारा जा सके तथा उसे बेहतर बनाया जा सके। अपनी गलतियों को चिन्हित कर उन्हें आलोचना–आत्मालोचना, समीक्षा और विशेष भूल सुधार अभियानों के जरिए सुधार लेती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह सब जान–समझकर भी पण्डा अपने सोलह पन्नों वाले झूठे आरोपों के साथ सामने आया है तो उसके बुरे मंसूबों को साफ समझा जा सकता है। असल बात यह है कि चूंकि वह इस तरह की प्रक्रिया में भाग लेकर खुद को सुधारने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया।

हालांकि पण्डा के सड़ांध से भरे आरोपों की फेहरिश्त काफी लम्बी है, लेकिन उनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं –

1. माओवादियों के लिए विवेकहीन हिंसा और बेकसूर लोगों को मारना आम बात बन गया। वे अपने कैडरों को तथा भोलेभाले और बेकसूर पुलिस वालों को अंधाधुंध मार डालने के आदेश देते हैं। 2. पार्टी में तेलुगु और कोया कामरेडों का दबदबा कायम है। 3. माओवादी ही आदिवासियों का सबसे ज्यादा शोषण करते हैं। उनसे खाना बनवाते हैं। सामान उठवाते हैं। कार्यकर्ताओं को त्यौहारों पर भी अपने परिवारों से मिलने नहीं देते हैं। माओवादी आदिवासी महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं। 4. गणपति आतंक और भय पर आध ाारित तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं।

अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली जनता पर राजसत्ता अपने पास मौजूद तमाम हथियारों से दमनचक्र चलाती है। अगर यह लड़ाई जनता की मुक्ति के लक्ष्य से, यानी उत्पीड़ित जनता की राजसत्ता को कायम करने के लिए चलती हो तो राजसत्ता उस पर तीखे दमन पर उतारू हो जाती है। उसके पुलिस, अर्द्धसैनिक व फौजी बल आगे रहकर हमला करते हैं, जबकि उसके तमाम दूसरे अंग इस हमले में सुनियोजित, तालमेल के साथ, बेहद क्रूरता व षड़यंत्रकारी तरीकों से भाग लेते हैं। इसलिए इस हिंसा का मुकाबला

करने के लिए जनता को सशस्त्र संघर्ष जरूरी हो जाता है। मार्क्सवाद के बारे में एबीसीडी जानने वालों को भी क्रांतिकारी हिंसा से सम्बन्धित इस बुनियादी व प्राथमिक विषय के बारे में जरूर मालूम होगा। जब पण्डा ने दक्षिणपंथी अवसरवादी सीपीआइ (एम.एल.) लिबरेशन पार्टी को छोड़ क्रांतिकारी पार्टी की लाइन को कबूलकर पार्टी में शामिल हुआ था और एकता कांग्रेस की लाइन को मान लिया था, तब उसे इसके बारे में मालूम नहीं था ऐसा तो नहीं हो सकता। चूंकि पण्डा ने खुद को पार्टी से अलग करना चाहा, इसलिए वह अवसरवादी तरीके से जहर उगल रहा है कि माओवादियों की हिंसा विवेकहीन है और वे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। इन सबका विरोध करने का दिखावा करते हुए वह यह उम्मीद कर रहा है कि भारतीय राजसत्ता उसके प्रति रहमदिली दिखा दे। जनता को कई प्रकार की हिंसा का शिकार बनाते हुए, उनके जीवन के तमाम पहलुओं को ध्वस्त करते हुए, उनकी हत्याएं करते हुए, बर्बर राजकीय दमन चलाने वाले और उसमें हिस्सा लेने वाले सरकारी सशस्त्र बल व अधिकारी तथा लक्ष्मणानंद, जगबंधु जैसे वर्ग–दुश्मन पण्डा को अब अचानक निर्दोष नजर आ रहे हैं। शासक वर्गों के चरणों पर नतमस्तक होने के लिए वह झूठे इलजाम लगाने के मामले में शत्रु–दुष्प्रचार को भी पीछे छोड़ रहा है।

'ओड़िशा में तेलुगु और कोया कामरेडों का दबदबा चल रहा है' वाला आरोप लगाकर पण्डा 'फूट डालो और राज करो' की उसी घिसी–पिटी व ओछी चाल चल रहा है जोकि दरअसल ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और उनके नक्शेकदम पर चल रहे भारतीय शासक वर्गों की है। दीर्घकालीन जनयुद्ध की लाइन के अनुसार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रणनीतिक दृष्टि से बिखरे हुए इलाकों से देशव्यापी स्तर में तथा छोटे इलाकों से व्यापक इलाकों में विस्तार करने के लिए और खुद को छोटी ताकत से एक बड़ी ताकत के रूप में विकसित करते हुए अंततः देशव्यापी पैमाने पर राजसत्ता हासिल करने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन का निर्माण हो रहा है। इसके लिए पार्टी रणनीतिक दृष्टि से अपनी ताकतों को शुरू से ही विभिन्न इलाकों में तैनात करके काम कर रही है। स्थानीय स्तर पर जनाधार को बढ़ाते हुए पार्टी व जनसेना को विकसित

करते हुए इलाकेवार राजसत्ता की स्थापना कर रही है। इस लाइन पर चलते हुए रणनीतिक तौर पर शक्ति संतुलन में बदलाव लाकर अंततः शहरों को घेरकर देशव्यापी राजसत्ता पर कब्जा करनी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी के हर सदस्य को देश के किसी भी हिस्से में जाकर काम करने के लिए तैयार रहना होगा। इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीयवादी होने के चलते कम्युनिस्टों को दुनिया के किसी भी देश में या क्षेत्र में जाकर वहां की जनता के साथ कंध ो से कंधा मिलाकर उनकी मुक्ति के लिए काम करने को तैयार रहना चाहिए। भारतीय क्रांति के इतिहास पर नजर डाली जाए तो हम यह समझ सकते हैं कि अपने इलाकों व राज्यों को छोड़कर दूसरे इलाकों व राज्यों में जाने वाले कामरेडों के कड़े प्रयासों के फलस्वरूप ही देश के विभिन्न हिस्सों में क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार हो पाया है। इन कामरेडों ने भाषाएं सीखीं। वहां की जनता की संस्कृति का सम्मान किया। उनके साथ एकताबद्ध हुए। नए इलाकों में निर्मित आंदोलनों को ऐसे कामरेडों के सामूहिक परिश्रम के नतीजे के रूप में देखा जा सकता है। पण्डा के संकीर्ण क्षेत्रीयवादी नजरिए के चलते दूसरे राज्यों से आए कामरेडों का ओड़िशा में आकर काम करना उसे कभी रास नहीं आया। ऐसे कामरेडों की निस्वार्थ भावना की प्रशंसा करने की बजाए उसने उनके और ओड़िया कामरेडों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए षड़यंत्रकारी तरीकों व गुटबाजी से ही लगातार काम किया। आंदोलन की जरूरत के अनुसार दूसरे राज्यों से ओड़िशा में काम करने के लिए आने वाले कामरेडों के मामले में उसने क्षेत्रीय अंधराष्ट्रवाद का प्रदर्शन करते हुए नौकरशाहीपूर्ण, गैर–जनवादी व संकीर्ण तरीके से काम किया। वास्तव में ओड़िया जनता और ओड़िया कामरेडों ने उनके लिए और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए आंध्रप्रदेश, झारखण्ड व छत्तीसगढ़ से आए हुए कामरेडों का खुशी से ही स्वागत किया। इस सच्चाई को स्वीकार किया। हम आशा करते हैं कि पण्डा के साथ कार्यरत चंद कामरेड्स जनयुद्ध की लाइन के बारे में दोबारा चिंतन–मनन कर उसके झूठों को समझ लेंगे और उसकी साजिशों को समझकर उसका पर्दाफाश कर देंगे।

क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत आदिवासियों की मुक्ति का लक्ष्य त्याग देने वाले पण्डा 'माओवादियों के हाथों आदिवासियों का शोषण' के बारे में शासक वर्गीय हत्यारों की ही तर्ज पर हमारी पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हुए मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है जोकि उसके छलकपट का साफ सबूत है। पार्टी में रहते समय शारीरक श्रम में कभी भाग न लेने वाले पण्डा की आंखों पर जब शासक वर्गीय चष्मे सज गए, आदिवासी कामरेडों का स्वैच्छिक रूप से, अत्युन्नत क्रांतिकारी चेतना के साथ क्रांति के लिए अपनी सारी शारीरक शक्ति को बाहर लाकर काम करना 'माओवादियों के हाथों शोषण' के रूप में दिखाई दे रहा है। आखिर माओवादी कौन हैं? और आदिवासी कौन हैं? क्या पार्टी में काम करने वाले आदिवासी माओवादी नहीं हैं? क्रांति को छोड़कर शासक वर्गों की वकालत करने पर उतारू ठेठ अवसरवादी पण्डा को क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान रोजमर्रा के जीवन में जरूरी व्यक्तिगत श्रम और सामूहिक जीवन में सैन्य, तकनीकी, उत्पादन–विकास, जन कल्याण आदि क्षेत्रों में आवश्यक श्रम, जन आंदोलन में जनता का विभिन्न प्रकार का श्रम माओवादियों द्वारा आदिवासी जनता के शोषण के रूप में दिखाई देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सर्वहारा पार्टी में हरेक व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना–अपना काम कर लेते हैं। भार उठाते हैं। बीमार, शारीरक रूप से कमजोर और विशेष कामों में लगे साथियों की मदद दूसरे लोग करते हैं। दरअसल जनसेना प्रधान रूप से युद्ध का संचालन करते हुए अपने लिए जरूरी रसोई, भार उठाना आदि काम खुद ही कर लेती है। राष्ट्रीयता, लिंग, क्षेत्र आदि का फर्क किए बगैर हरेक को जनयुद्ध के अंतर्गत उपरोक्त काम करने ही होंगे। देश के विभिन्न गुरिल्ला जोनों में यही चलता आ रहा है। और चल रहा है। दरअसल हमारी पार्टी की संस्कृति जनवादी व समाजवादी संस्कृति है जिसमें स्त्री–पुरुषों के बीच, पढ़े–लिखे व अनपढ़ों के बीच तथा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी पार्टी के प्रति आदिवासियों के आकर्षित होने का यह एक अहम कारण है। हमारी पार्टी इसी संस्कृति को बड़े पैमाने पर, लाखों लोगों के बीच ले जा रही है।

राजसत्ता यह आरोप बार–बार लगा रही है कि माओवादी अपनी पार्टी में शामिल महिलाओं/आदिवासी महिलाओं को अत्याचार व यौन प्रताड़ना का शिकार बनाते हैं। गद्दार बन चुके पण्डा ने भी माओवादियों पर शासक वर्गों की तरह बेहद नीचतापूर्ण तरीके से हमला किया है तो इसमें अश्चर्य क्या है? अतीत में हमारी पार्टी ने हर बार जो जवाब दिया आज भी इस पर हमारा वही जवाब है। हालांकि इस आरोप का अत्युत्तम जवाब दे रही हैं वे सैकड़ों महिलाएं जो हमारी पार्टी में भर्ती हो रही हैं, वे हजारों–लाखों महिलाएं जो क्रांतिकारी महिला संगठनों में सदस्यता ले रही हैं, वे महिलाएं जो आंदोलन के इलाकों में मौजूद हैं और वे सैकड़ों महिला साथी जो नक्सलबाड़ी के दिनों से लेकर पिछले 45 सालों से शोषित जनता की मुक्ति के लिए अपने प्राणों को कुरबान कर चुकी हैं।

1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद, आंदोलन के अब तक के 90 से ज्यादा सालों के इतिहास पर नजर डाली जाए तो ऐसा कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी पिछले 25 बरसों में जनता, जन संस्कृति और जन जीवन के तमाम पहलुओं के साथ जितना ज्यादा एकताबद्ध हुई, उतना पहले कभी नहीं हुई थी। न सिर्फ एकताबद्ध हुई, बल्कि वह जन जीवन के राजनीतिक व सांस्कृतिक पहलुओं में से तमाम प्रगतिशील अंशों को ऊंचा उठाकर, उन्हें अपने अंदर समाहित कर, उनका और ज्यादा क्रांतिकरण कर रही है। पण्डा के इस आरोप को कि त्यौहारों पर घर देखने को इच्छुक कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया जाता है, क्रांतिकारी जनता कतई विश्वास नहीं करेगी। जिन लोगों को क्रांतिकारी आंदोलन के साथ ज्यादा परिचय नहीं है, ऐसे लोगों को उस पर घृणा की भावना पैदा करने की नीयत से ही वह इस प्रकार अवसरवादी तरीके से हमला कर रहा है।

यह आरोप कि गणपति आतंक और भय पर आधारित तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं, इतना हास्यास्पद है कि दरअसल इसके लिए स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं है। भाकपा (माओवादी) किसी बुर्जुआई पार्टी जैसी कतई नहीं है। हमारी पार्टी ने तय किया है कि मौजूदा अर्द्ध सामंती व अर्द्ध औपनिवेशिक

राजसत्ता को क्रांतिकारी हिंसा के जरिए ध्वस्त कर, नई जनवादी क्रांतिकारी सत्ता, यानी सर्वहारा की अगुवाई में मजदूर–किसान एकता की बुनियाद पर आधारित चार वर्गों – मजदूर, किसान, निम्न पूंजीपति वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्गों की जनवादी तानाशाही की स्थापना हमारा फौरी लक्ष्य है, जबकि बाद में समाजवाद और साम्यवाद लाना अंतिम लक्ष्य है। ऐसा भी नहीं है कि यह सब पण्डा को मालूम नहीं है। संसदीय लोकतंत्र की आड़ में देश में मनमानी तरीके से तानाशाही चलाने वाली दलाल नौकरशाही बुर्जुआ व सामंती वर्गों की निरंकुश व्यवस्था से, जिसकी साम्राज्यवादियों से सांठगांठ है, समझौता करके उसमें अपनी जगह पक्की करने के इरादे से ही पण्डा कामरेड गणपति और हमारी पार्टी पर गलत आरोप लगा रहा है।

दरअसल पण्डा खुद ही ओड़िशा में अपनी तानाशाही स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। राज्य की विशेष प्लीनम में की गई समीक्षाओं और फैसलों को देखने के बाद उसने समझ लिया था कि पार्टी के कैडर उससे दबकर रहने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने उसके नौकरशाहाना व्यवहार और अन्य राज्यों के साथियों के प्रति गैर–जनवादी व संकीर्णतावादी रवैये की आलोचना की। यह पहचानते हुए कि नौकरशाहाना व्यवहार को जारी रखना संभव नहीं है, इस अवसरवादी ने पार्टी छोड़ने का फैसला लेकर तबसे अपनी पूर्व तैयारियों में तेजी लाई।

दरअसल, राज्य स्तरीय प्लीनम के आयोजन के बाद से उसने ओड़िशा राज्य प्रभारी सी.सी. कामरेड से संपर्क करना ही छोड़ दिया। तबसे, करीब छह महीनों तक वह अपने बयानों और साक्षात्कारों में लगातार पार्टी पर जहर उगलता रहा। इससे पार्टी में राजनीतिक व सांगठनिक समस्याएं उत्पन्न हुईं जिससे ओड़िशा के आंदोलन को तीव्र नुकसान पहुंचा। क्योंकि बहुत से मामलों में उसका रवैया विशेष प्लीनम के फैसलों, पार्टी लाइन और नीतियों के खिलाफ रहा। उसकी अगुवाई में जब इटली के सैलानियों को बंदी बनाया गया था, तब वह निहायत अवसरवादी तरीकों पर उतर आया। उसने समूचे ओड़िशा राज्य में एकतरफा संघर्षविराम की घोषणा की। ओड़िशा और उसके सीमावर्ती

इलाकों के उल्लेखनीय हिस्से में जब दो–दो सीमावर्ती कमेटियां काम कर रही हों, तब उसका इस तरह घोषणा करना अनुचित था। इस तरह बाकी दो कमेटियों को आदेश देने का उसे कोई अधिकार भी नहीं था। उसके द्वारा एकतरफा संघर्षविराम की घोषणा के बाद जब एओबी के साथियों ने एक विधायक को बंदी बनाया और एक एसआई को गोली मार दी, तब उसने न सिर्फ एओबी के साथियों की खुलेआम आलोचना की, बल्कि यह तक कह दिया कि उनके लिए मारना फैशन बन गया।

ओड़िशा एसओसी के दायरे में समूची पार्टी द्वारा की गई समीक्षाओं को ताक पर रखकर पण्डा ने यह घोषणा की कि लक्ष्मणानंद, जगबंधु जैसे वर्ग–दुश्मनों का सफाया गलत था। दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर उसने कामरेड निखिल के नाम से बयान जारी करते हुए अलग–अलग समुदायों व अलग–अलग राज्यों से आए हुए कामरेडों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिशें करते हुए एक जहरीली मुहिम शुरू कर दी। जब मीडिया में लगातार खबरें आने लगी थीं कि पण्डा पार्टी छोड़ने वाला है और एक नया ग्रुप बनाने वाला है, लगातार मीडिया के संपर्क में रहते हुए भी पण्डा की ओर से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आना महज इत्तेफाक नहीं था। साफ जाहिर है कि विशेष प्लीनम के बाद ही उसने पार्टी छोड़ने की योजना बनाकर खुलेआम अवसरवादी तरीकों और विघटनकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। अपने पतन की पराकाष्ठा के रूप में उसने आखिरकार पार्टी छोड़ दिया।

ओड़िशा आंदोलन के दौरान सामने आई राजनीतिक समस्याओं पर दक्षिणपंथी अवसरवादी रुख अपनाते रहे पण्डा का पतन आखिर में संशोधनवाद के स्तर पर हुआ जो दीर्घकालीन जनयुद्ध की लाइन को ठुकरा देता है। उसके अंदर मौजूद संकीर्णतावादी, अतिजनवादी, अनुशासनहीन, गुटीय, गैर–सांगठनिक, पदलोलुपतावादी, नाम और प्रसिद्धि के पीछे भागने आदि रुझानों ने ओड़िशा में पार्टी और आंदोलन को बेहद नुकसान पहुंचाया। वह हमेशा सुखी जीवन की तलाश में रहता था। उसके अंदर मेहनती स्वभाव का बिल्कुल अभाव था। संगठित होने के क्रम से गुजर रही ओड़िशा राज्य पार्टी को हुए गंभीर नुकसान

की स्थिति और सी.सी. पर दुश्मन का हमला केन्द्रित होने से जो गंभीर नुकसान पहुंचा था उसका इस अवसरवादी ने फायदा उठाया ताकि राज्य में विघटनकारी गतिविधियां जारी रखी जा सकें। इन सबकी जड़ उसके अंदर गहराई से मौजूद व्यक्तिवाद में है जो व्यक्ति को केन्द्र में रखता है। इसके अलावा, क्रांतिकारी आंदोलन पर साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के सम्पूर्ण सहयोग से भारत के शासक वर्गों द्वारा जारी प्रति–क्रांतिकारी युद्ध में 2009 के मध्य से आपरेशन ग्रीनहंट के नाम से खासा बदलाव आ गया। तबसे हमारे आंदोलन के खिलाफ जारी देशव्यापी व चौतरफा भारी सैनिक हमले की पृष्ठभूमि में ही पण्डा के पतन व विश्वासघात को देखना होगा। इस हमले में पार्टी को देश भर में तीखे नुकसान हुए हैं। हालांकि ओड़िशा में आंदोलन अभी भी कमजोर ही है, लेकिन वह भी इस हमले का बुरी तरह शिकार हो रहा है। खासकर 2010 के आखिर से उसे गंभीर नुकसान झेलने पड़े। यह हमला और भी तीखा होने वाला है। भारत जैसे पिछड़े देशों की प्राकृतिक सम्पदाओं और संसाधनों को लूटने के रास्ते में बाधा बनने वाले संगठनों और लोगों को कुचलने के पीछे अहम कारण बहुराष्ट्रीय व देश की दलाल कार्पोरेट कम्पनियों के हित ही है। विश्व अर्थव्यवस्था को घेरने वाला वित्तीय संकट और जितना तीखा होगा, क्रांतिकारी पार्टी, उसके नेतृत्व, आंदोलन व शोषित जनता पर वे अपना हमला उतना ही तेज करेंगे ताकि वे खुद को उससे उबार सके। इस पृष्ठभूमि में क्रांतिकारी पार्टी के नेताओं के लिए आंदोलन को चलाना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। पार्टी के सच्चे नेता देश और दुनिया में छाई हुई बेहतरीन क्रांतिकारी परिस्थिति का फायदा उठाकर जनता को राजनीतिक रूप से तैयार करते हुए, जनयुद्ध को विकसित करने व क्रांति के पक्ष में बदलने की ही कोशिश करेंगे। इसके लिए क्रांतिकारी सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता, दृढ़ इरादे, साहस के साथ फैसले लेना, पार्टी, जनसेना व जनता को एक सूत्र में बांधकर चलाना, बलिदानी भावना आदि जरूरी होते हैं। क्रांति की जरूरतों और कार्यभारों के मुताबिक खुद को और पार्टी को ढालने के लिए फौलादी संकल्प जरूरी हो जाता है। ऐसे लक्षणों के अभाव में कोई भी नेता क्रांति का नेतृत्व करने में या तो विफल हो जाएगा या

फिर अक्षम हो जाएगा। ऐसे लोगों में से कुछ जंगे मैदान को छोड़कर कायरों की तरह भाग खड़े हो जाएंगे या फिर दुश्मन की शरण में चले जाएंगे। इस सच्चाई को छुपाते हुए ऐसे अवसरवादी और क्रांति–द्रोही शासक वर्गों का बचाव करते हुए पार्टी और पार्टी–नेतृत्व पर अनाप–शनाप आरोप लगाते रहते हैं। अतीत में न सिर्फ हमारी पार्टी के इतिहास में, बल्कि विभिन्न देशों की क्रांतियों में भी ऐसे गद्दार रहे थे। ऐसे लोगों में पण्डा आखिरी व्यक्ति भी नहीं होगा।

उपरोक्त सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए हमारी केन्द्रीय कमेटी ने पण्डा पर आए तमाम आरोपों को उसके सामने राजनीतिक रूप से पेश कर, उसे गलतियों से बाहर आने का मौका देते हुए, सुधारने की विशेष कोशिश शुरू की। लेकिन राज्य की विशेष प्लीनम के बाद से उसने सम्बन्धित सी.सी. कामरेड से पूरी तरह सम्बन्ध तोड़ लिया और पार्टी, आंदोलन व नेतृत्व पर लगातार खुला हमला करता रहा। इन सबकी पराकाष्ठा के रूप में मीडिया को यह जहरीला पत्र जारी करके खुद को गद्दारों में शामिल कर लिया। इसलिए हमारी केन्द्रीय कमेटी सब्यसाची पण्डा को पार्टी से बहिष्कार करती है। और हम इसकी सूचना ओड़िशा में मौजूद हमारी पार्टी के तमाम साथियों, समूची क्रांतिकारी जनता और देश के तमाम क्रांतिकारी खेमे को देते हैं।

ओड़िशा के साथियों, जन संगठनों और क्रांतिकारी व जनवादी जनता से हम अपील करते हैं कि वे हमारी पार्टी, आंदोलन और नेतृत्व के प्रति पण्डा द्वारा अपनाए गए शत्रुतापूर्ण व अवसरवादी रुख तथा शासक वर्ग–अनुकूल व जनविरोधी रुख का खण्डन करें। उसे, उसकी सड़ी–गली नव संशोधनवादी राजनीति और उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को ठुकरा दें। इतिहास ने कई बार साबित किया है कि जो खुद ही खुद को बेजोड़ क्रांतिकारी नायक के रूप में दिखाते हैं या फिर शासक वर्गों द्वारा इस तरह फोकस किए जाते हैं, ऐसे गद्दार आखिरकार इतिहास के कूड़ेदान में ही फेंक दिए जाएंगे जबकि सच्ची क्रांतिकारी पार्टी, उसके नेता और उसकी अगुवाई में क्रांतिकारी जनता अनुपम साहस के साथ, भारी तूफानों से होकर अंतिम जीत की ओर अनवरत आगे

बढ़ते रहेंगे। जनता ही इतिहास का निर्माता है, पण्डा जैसे नकली क्रांतिकारी नहीं। हमारी पार्टी को सम्पूर्ण विश्वास है कि ओड़िशा का सिक्का चलाते हुए शासक वर्गों की चरण–सेवा में जी–जान से जुट जाने वाले पण्डा जैसे गद्दारों को ओड़िशा की क्रांतिकारी जनता जरूर ठुकरा देगी तथा ओड़िशा के साथी व व्यापक उत्पीड़ित जनता भाकपा (माओवादी) की अगुवाई में क्रांति के पथ पर अग्रसर होंगे।

आनंद
पीबीएम, सीआरबी सचिव
केन्द्रीय कमेटी की ओर से
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)